मेडिकल ऑफिसर के रूप में join किया और जो लगातार 6 साल तक सेवाएँ दे रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस proposal पर अभी opinions लिए जा रहे हैं, हम इस पर विस्तारपूर्वक अभी scrutiny कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि इस पर सबके जो सुझाव आएँगे, उनके आधार पर एनएमसी कोई निर्णय लेगी। इसमें मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि ...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): प्रश्न काल समाप्त हुआ।

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials]

1.00 **P.M.**

$ THE UNION BUDGET 2025-26

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Further Discussion on the Union Budget, 2025-26. On 10th February, 2025, Dr. Bhagwat Karad had not concluded his speech while participating in the Discussion. Therefore, I call upon Dr. Bhagwat Karad to continue his speech.

डा. भागवत कराड़ (महाराष्ट्र): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बजट पर बोलने का जो वक्त दिया है, उसके लिए मैं आपका, हमारे हाउस लीडर जे.पी. नड्डा जी का और पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर, माननीय किरेन रिजिजु जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे भारत देश की अर्थ मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सतत आठवीं बार भारत देश का बजट इस सभागृह में पेश किया है और एक सर्वसमावेशी विज़न हमारे भारतवासियों को दिया है। मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी तीसरी टर्म का पहला बजट सभागृह में पेश हो चुका है। इन 11 सालों में माननीय प्रधान मंत्री जी ने 140 करोड़ भारतीयों को एक नया विचार दिया है। वह नया विचार है – "विकसित भारत संकल्प – 2047."

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार)** *पीठासीन हुईं।*]

माननीया उपसभाध्यक्ष महोदया, अगर हमें इस बजट की स्टडी करनी है, इसे देखना है, तो हमें दो इंपॉर्टेंट चीजों को देखना चाहिए। एक है - Budget Estimate और दूसरा है - Budget

---

$ Further discussion continued from the 10th February 2025.

receipts में क्या है। अगर हम यूपीए सरकार के टाइम का Budget Estimate और अभी के टाइम का Budget Estimate में compare करना चाहें, अगर हम 2013-14 की बात करें, तो Budget Estimate at that time was Rs.16.65 lakh crore और यही Budget Estimate 10 सालों के बाद यानी last year, 2024-25 में Rs. 47.16 lakh crore था। इस बजट में यह Budget Estimate Rs. 50.65 lakh crore हो चुका है, यानी 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा हुआ बजट हो चुका है। उसी तरह अगर हम total receipts देखें, तो 2013-14 में यह receipts Rs.13.20 lakh crore था और अभी यह Budget receipts, except borrowings Rs. 34.96 lakh crore है। यानी 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, fiscal deficit is very important in every Budget. This year, the fiscal deficit is only 4.4 per cent. अगर हम लास्ट ईयर से इसे कंपेयर करें तो it was 4.8 per cent. मैं माननीया वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। जैसे उन्होंने लास्ट बजट में बताया था कि हम fiscal deficit कम करेंगे, तो इस वक्त इस बजट में fiscal deficit 0.4 परसेंट कम किया है। अगर हम इस बजट का ध्येय देखें, तो भारत को एक स्वस्थ, सशक्त, सुरक्षित तथा स्वावलंबी नया भारत बनाना हमारे प्रधान मंत्री जी की थीम है, प्रधानमंत्री का ध्येय है। अगर हमें एक स्वस्थ, सशक्त, सुरक्षित तथा स्वावलंबी नया भारत बनाना है, तो जैसा इस बजट में बताया गया है, हमें गरीबी शून्य तक लानी पड़ेगी; 100 परसेंट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी; high quality, affordable and comprehensive healthcare देना पड़ेगा; hundred per cent skill labour with employment देना पड़ेगा; 70 परसेंट महिला आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल करना पड़ेगा; भारतीय किसानों की आय बढ़ाकर दुनिया के फूड बास्केट में ऊपर आना पड़ेगा; इसी तरह common man को tax में relief देनी पड़ेगी; एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा; ease of doing business को प्रधानता देनी पड़ेगी और import कम करना पड़ेगा। इन सभी 10 चीजों को माननीया अर्थ मंत्री जी ने इस बजट में समाविष्ट किया है।

मैं कल हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी को सुन रहा था। हम अपेक्षा कर रहे थे कि वे बड़े अनुभवी पूर्व वित्त मंत्री जी हैं, हमें कुछ न कुछ सुझाव देंगे, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री जी ने आधे वक्त में तो रक्षा मंत्रालय पर भाषण दिया। मैं पर्टिकुलर्ली पूर्व वित्त मंत्री और हमारे विपक्ष के सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूँ कि पूर्व प्रधान मंत्री जी ने बताया था कि अगर हम केंद्र से 100 रुपए भेजते हैं, तो 85 रुपए भ्रष्टाचार में चला जाता है और सिर्फ 15 रुपए नीचे तक जाता है। इस तरह से उस समय सिर्फ 15 परसेंट पैसा नीचे तक जाता था और 85 परसेंट पैसे का भ्रष्टाचार होता था। अगर इसको किसी ने हंड्रेड परसेंट कंट्रोल किया है, तो वह प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डीबीटी आया है, उस डीबीटी के माध्यम से हंड्रेड परसेंट लोगों को benefit मिलता है।

उसी तरह अगर हम 2012-13 की बात करें, तो अभी का विरोधी पक्ष, तत्कालीन गवर्नमेंट के कुछ मंत्री जेल गए थे। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, इसलिए वे जेल गए थे। लेकिन मैं सभागृह में बताना चाहता हूँ कि इस 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी के ऊपर नहीं है। गवर्नमेंट भ्रष्टाचार से बहुत हद तक कंट्रोल है। उसी तरह से अगर हम आतंकवाद की बात करें, तो 2004 से 2014 में पूरे देश में पर्टिकुलर्ली बड़े-बड़े शहरों में आतंकवाद होते थे, लेकिन इस 10 साल में यानी 2014 से 2024 तक किसी भी शहर में आतंकवाद की घटना नहीं हुई है, बॉर्डर में जो कुछ आतंकवाद हो चुका है, उसको भी कंट्रोल में लाया गया है। अगर 2004 से 2014 में भारत

देश की इमेज देखें, तो एक गरीब देश जैसी इमेज थी, लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इमेज एक सम्माननीय देश और विकसित देश जैसी इमेज बन चुकी है। मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश का तस्वीर और तकदीर, इमेज बढ़ाने का काम, सम्मान बढ़ाने का काम हो रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और यह मोदी जी का परिवार है। इस परिवार के लिए सैकड़ों स्कीम्स पिछले 10 सालों में प्रारंभ किए गए हैं। मैं इन स्कीम्स में से कुछ बताना चाहता हूँ। 'जनधन योजना' के माध्यम से 54 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। जब हमारे हाउस लीडर माननीय नड्डा जी फर्स्ट टर्म में हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उस समय 'आयुष्मान योजना' प्रारंभ की गई, जिसका फायदा 55 करोड़ लोगों को हो रहा है। इसी तरह 'प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना' के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, 'पीएम उज्ज्वला योजना' के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है, 'पीएम मुद्रा योजना' के माध्यम से without collateral 43 करोड़ लोन्स बांटे गए हैं, 'पीएम स्वनिधि योजना' के माध्यम से 68 लाख रेहड़ी-पटरी वाले लोगों को लोन मिला है, 'पीएम आवास योजना' के तहत 4 करोड़ लोगों को घर मिला है और 3 करोड़ लोगों को घर मिलने वाला है। ऐसे सैकड़ों स्कीम्स माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई हैं और इन सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है।

अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, तो हमारी अर्थव्यवस्था दसवीं नंबर से पांचवें नंबर पर आई है और हमें पांचवें नंबर से तीसरे नंबर पर जाना है। अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण चीज है, उसके संबंध में मैं दो-तीन इंडेक्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर हम भारतवासियों का per capita income देखें, तो 2014-15 में per capita income 86,647 रुपए प्रति वर्ष था, लेकिन यही per capita income 2025 में 2,12,000 रुपए प्रति वर्ष है यानी डबल से भी ज्यादा per capita income बढ़ा है। किसी भी बजट में Consumer Price Index देखा जाता है। अगर हम अभी Consumer Price Index को 2023-24 से कंपेयर करें, तो यह 5.23 है। यह भी कंट्रोल्ड कंडीशन में है। The important thing in the Budget is the Central Bank, that is, the Reserve Bank of India, which controls all the interests of the Banks. इसी को रेपो रेट बोलते हैं और इस रेपो रेट को तय करने के लिए एक Monetary Policy Committee है। Monetary Policy Committee हर 2 महीने में बैठती है और रेपो रेट के बारे में डिसीजन लेती है। मुझे सभागृह को बताने में खुशी हो रही है कि अभी जो मीटिंग हुई है, उसमें रेपो रेट .25 बीपीएस कम हुई है। अगर हम यही रेपो रेट 2013-14 में देखें, जब यूपीए की सरकार थी, उस समय यह रेपो रेट 7.75 परसेंट थी। प्रधान मंत्री मोदी जी की अवधि में यह रेपो रेट 6.25 BPC है। इसका मतलब business और credit facilities स्वस्थ्य हुई है।...(**समय की घंटी**)... इतना ही नहीं कृषि क्षेत्र में अलग-अलग स्कीम्स प्रारंभ हुई हैं।

महोदया, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ था, लेकिन उसकी रिपोर्ट का एक पन्ना भी इन्होंने नहीं देखा। मोदी जी के नेतृत्व में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की कोशिश की गई है। इसी तरह, मैं किसानों की कर्ज माफी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैडम, जब हमारे महाराष्ट्र के पवार साहब कृषि मंत्री थे, तो कृषि मंत्री ने सिर्फ एक बार किसानों का ऋण माफ किया था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी के

नेतृत्व में "किसान सम्मान योजना" शुरू की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को अभी तक 3.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार): माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हो गया है।

डा. भागवत कराड़: पीएम फसल बीमा योजना, सब्सिडी टू यूरिया, कुसुम योजना, ई-नाम योजना जैसी किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देश की 140 करोड़ जनता ही मोदी जी का परिवार है।

मैडम, अब मैं उपलब्धियों के बारे में बतलाता हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अलग-अलग नए मंत्रालयों की शुरुआत की गई है, जैसे - फिशरमेन और किसानों के लिए फिशरी और डेयरी मंत्रालय, देश के ग्रामीण भागों में पानी पहुंचाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, इसी तरह, आयुष मंत्रालय, कोऑपरेटिव मंत्रालय, ओबीसी आयोग। ये सब नए मंत्रालयों का आरंभ प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार): माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हो गया है।

डा. भागवत कराड़: मैडम, हमारे लीडर ऑफ दि हाउस कल अपोजिशन को बोल रहे थे कि national interest के लिए आप पोलिटिकल चश्मे को उतारिए। आप हर जगह विरोध करते हैं। जैसे, इन्होंने जीएसटी का विरोध किया है, कलम 370 का विरोध किया है, UPI technology, जिसे आज पूरी दुनिया ने मान लिया है, उसका विरोध किया है, One Nation, One Election का विरोध किया है, वक्फ बोर्ड अधिनियम का विरोध किया है और ईवीएम का भी विरोध किया है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार): अगले स्पीकर, श्री प्रफुल्ल पटेल। ...(**व्यवधान**)...

डा. भागवत कराड़: इनका काम हर जगह विरोध करना है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार): आपका समय खत्म हो गया है, अब आप प्लीज़ कनक्लूड कीजिए। नेक्स्ट स्पीकर, श्री प्रफुल्ल पटेल।

SHRI PRAFUL PATEL (Maharashtra): Hon. Member is still speaking.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार): उनका समय खत्म हो गया है।

डा. भागवत कराड़: मैडम, मैं दो मिनट में कनक्लूड कर दूँगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार): मिस्टर कराड़, आप कनक्लूड कीजिए।

डा. भागवत कराड़ः मैडम, मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों का हर जगह विरोध है। अभी इनका रिसेंट विरोध ईवीएम के बारे में चल रहा है। इस सभागृह में 1977 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर चर्चा हुई थी, 1982 में इसके ऊपर प्रयोग हुआ, 1988 में इस पर दोनों सदनों ने मंजूरी दी, उस वक्त प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। 1992 में सारे रूल्स बने, 2001 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस हो गये और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ईवीएम के पक्ष में निर्णय दे दिया। उसके बाद, 2017 से लेकर अभी तक चुनाव आयोग के ऊपर कुछ आरोप लगे, जिसके बाद आयोग ने EVM मशीन को आयोग में खुला रखा, objection मांगे, लेकिन उसके बाद भी आयोग के पास कोई भी पक्ष नहीं गया। वहां केवल सीपीआई और एनसीपी गईं, लेकिन उन्होंने भी कोई सजेशन नहीं दिया।

मैडम, मैं उस वक्त के प्रधान मंत्री, राजीव गांधी जी की एक बात को क्वोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की पिछले पार्लियामेंट में लोक सभा की 86 सीटें आई थीं। उनमें आज तक 86 सीटें जीतने की ताकत नहीं है। उनका वोट प्रतिशत बढ़कर 12% हो गया है, यह होने से उनको 86 सीटें मिलीं। इससे हिसाब नहीं जुड़ता। इस हिसाब से कांग्रेस को 500 सीटें आनी चाहिए थीं। कुछ तो बैलेट पेपर में गड़बड़ है, इसीलिए ईवीएम मशीन लानी है। यह प्रधान मंत्री जी के उसी वक्त का क्वोट है। लेकिन, अभी के Leader of the Opposition in Lok Sabha बोलते हैं कि ईवीएम मशीन नहीं होनी चाहिए। मैडम, मुझे बताना है कि हमें भारत को यदि विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें टेक्नोलॉजी का adopt करना चाहिए। ईवीएम एक मशीन है, लेकिन हम एनर्जी, विकास और मेहनत करके चुनाव जीतते हैं।

मैडम, आखिर में मैं एक लाइन बोलता हूँ। समय का पल-पल, शरीर का कण- कण व्यतीत करते हुए माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने विकसित भारत-2047 का लक्ष्य रखा है। महोदय, 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है और 140 करोड़ जनता कैसे सशक्त बने, इसीलिए प्रधान मंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और उनके दिल और मन-मस्तिष्क में एक ही विचार है। एक ही विचार और एक ही लक्ष्य है, 'विकसित भारत'। इसलिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। मैं हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दो पंक्तियां सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगाः

कदम मिलाकर चलना होगा
हास्य-रुदन में, तूफ़ानों में,
अगर असंख्यक बलिदानों में,
उद्यानों में, वीरानों में,
अपमानों में, सम्मानों में,
उन्नत मस्तक, उभरा सीना,
पीड़ाओं में पलना होगा!
विकसित भारत बनाने के लिए हमें क़दम मिलाकर चलना होगा।

हमें कितने भी कष्ट उठाकर आगे बढ़ना पड़े, हम बढ़ेंगे। मोदी जी का परिवार 140 करोड़ जनता है, जो हमारे साथ रहेगी और हम विकास करके दिखाएंगे। सभी विरोधी पक्षों से मेरी विनती है कि आप सभी मिलकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मदद कीजिए। अंत में मैं

वित्त मंत्री महोदया और माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार): श्री प्रफुल्ल पटेल।

श्री प्रफुल्ल पटेल: उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरा सौभाग्य है कि आप यहां पीठासीन हैं और मुझे बोलने का अवसर मिला है ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): मैडम, बीजेपी के बाद हमारा समय आता है।

श्री प्रफुल्ल पटेल: जयराम जी, प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए।

श्री जयराम रमेश: मैडम, यह प्रथा है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस का समय आता है।

SHRI PRAFUL PATEL (Maharashtra): Madam, my turn was yesterday, which I gave up voluntarily to speak today. My turn would have come way earlier yesterday. Anyway, my compliments and congratulations to the hon. Finance Minister for having given a historic 8th Budget in a row. Under the stewardship and the leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, we should be proud Indians that we have become the fifth largest economy in the world. In the coming years, in a very short span, we will become the third largest economy in the world. We are not too far away from the days when the slogan in this country used to be 'गरीबी हटाओ', हमें लोगों को अनाज देना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा। 'रोटी, कपड़ा और मकान' was the essence of our political and economic discourse. But now, we are talking of a confident, self-reliant and a developed India. We are no more a third world country; we are already a developing country and we shall soon become, in 2047, a developed country, holding our own amongst the nations of the world. So, I think, we should be very proud. The second thing is a recent development which we saw all over the world, especially after the elections in the United States. What is the slogan the new President of the United States has given? "Make America Great Again". I am not trying to say what they do there should apply to us. But we should also be conscious of the fact that our Prime Minister, from 2014, has set India on a new trajectory by instilling the confidence or by giving the 'Make in India' Programme and the Atmanirbhar Bharat Programme. What does it mean? Like America says, 'Make America Great Again', we are also talking, 'make India big and proud again'. We want India to become prosperous. हमारे पुरातन इतिहास में कहा जाता था कि पूरा विश्व भारत को सोने की चिड़िया के तौर पर देखता था। Our country should become great again. That is what Prime

Minister Modi has started in 2014 itself. That is why we are seeing so many different sectors जहां पर विदेशों के भरोसे ही हमारी इकोनॉमी चलती थी। एक जमाना ऐसा था कि हम लोग करीब-करीब सभी चीज़ें बाहर से मंगाते थे, इम्पोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट बहुत सामान्य होते थे। यहां बहुत ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स होते थे, उसके अलावा हम विश्व में कुछ भेज नहीं पाते थे। हमारी क्वालिटी बहुत poor थी, हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ी कंपनीज़ नहीं थीं। आज जिस तरह से हम अपने देश से हर तरह का एक्सपोर्ट कर पाते हैं और एक्सपोर्ट के अलावा हमारे देश के भीतर आज आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, डिफेंस जैसे क्षेत्र में, जहां पर हम लोगों को बम, बारुद के अलावा, ordnance factories के अलावा हमारे पास या एचएएल के बेसिक असेम्बली की टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ नहीं था। आज हम लोग हमारे आरएंडडी के साथ बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और विश्व में आज एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अगर आप इसी बात को आगे बढ़ाकर देखेंगे, तो देश कब आगे बढ़ेगा, जब देश में हम लोग कनेक्टिविटी लाएंगे, देश को एक करने का काम करेंगे। भारत कोई छोटा भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। भारत में हमारी विभिन्न जातियां हैं, धर्म हैं, बोली हैं, हमारे अलग-अलग प्रांत हैं, रीजन्स हैं, तो जब हम सही तरीके से इन सारे लोगों को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम भारत को एक नहीं कर पाएंगे और भारत का विकास जिस तरह से balanced development चाहिए, वह हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पिछले 11 सालों से यह फोकस रहा है कि भारत को पहले एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट देना पड़ेगा। किसी भी देश में जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट नहीं होगा, तब तक उस देश में economic activity equitably नहीं हो पाती है। That is why the programmes to build Highways and now Super Highways. We are building them across the length and breadth of the country. The other day when the Finance Minister was speaking, the Chenab Bridge came in her speech. The Chenab Bridge may be just one bridge. But it is symbolic of the achievements of the entire nation. It instills a sense of pride and confidence. It provides connectivity with the rest of the country. आज चिनाब के ऊपर ब्रिज बनाकर कश्मीर को जोड़ा जा रहा है, तो शायद कल यह भी हो सकता है कि ओडिशा में भी कोई पिछड़ा जिला हो या महाराष्ट्र का या किसी और जगह का पिछड़ा जिला होगा, उसकी भी यह अपेक्षा हो गई है, उसकी उम्मीद जाग्रत हो गई है कि मुझे भी भारत की मेनस्ट्रीम के साथ जोड़ा जाएगा। जब तक हम पूरे देश को मेन स्ट्रीम के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम लोगों का equitable growth और विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने रोड कनेक्टिविटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया, उन्होंने पोर्ट्स के मामले में ध्यान दिया। अभी महाराष्ट्र के लोगों को बहुत गर्व होना चाहिए कि अंडमान का पोर्ट मुंबई के ऊपर के हिस्से में जो बन रहा है, पूरे देश का सबसे बड़ा पोर्ट भारत सरकार के माध्यम से बनाया जा रहा है। प्रधान मंत्री जी ने 76 हज़ार करोड़ रुपये की योजना की नींव डाली है। That will catapult our Western Coast and our port infrastructure to the next level. It is a great thing that today ports are being given this priority and port does not mean just एक बंदरगाह बन गया। पोर्ट के साथ बहुत सारा पैरीफेरल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनता है। पोर्ट्स के साथ वहां की टाउनशिप्स बनती हैं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, इसलिए एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। बाकी पोर्ट्स का भी वही मामला है। आज एक ट्राइबल एरिया में पोर्ट बन रहा है। कल जब उसके आस-पास का विकास

होगा, तो वहां पर कोई पिछड़ापन नहीं रहने वाला है। उसके विकास के साथ देश का भी विकास होने वाला है। इसलिए आज चाहे पोर्ट्स हों, रोड्स हों, सभी का विकास होगा।

महोदय, मैं अभी एयरपोर्ट्स के बारे में, उड़ान स्कीम के बारे में भी कुछ कहूंगा, क्योंकि मैंने इस सिविल एविएशन विभाग का मंत्रालय आठ सालों तक संभाला है। जिस तरह से एक नई दिशा जा रही है, वह बहुत अच्छी बात है। जब हम सरकार में थे, तो हम 75 एयरपोर्ट्स तक पहुँचे थे, लेकिन आज आठ से दस साल के समय में हम 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स तक पहुँच रहे हैं। महोदय, एक एयरपोर्ट केवल एक रनवे नहीं होता है, बल्कि वह उस क्षेत्र की उमंग, अपेक्षा और उम्मीदों को जगाता है। बड़े से बड़ा उद्योगपति हो या बाहर का कोई भी व्यक्ति हो, जब वह आसानी से पहुँचता है, तो वहाँ उद्योग आते हैं, वहाँ पर दूसरी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ता है। आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दुर्गम इलाके हैं, जहाँ पर हमारे पास eco-tourism है, wildlife tourism है, religious tourism है। महोदय, जब व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है, तब उसे भी लगता है कि मैं बहुत आसानी से आ गया हूं, जिससे वहाँ पर और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इस connectivity पर, जो प्रधान मंत्री जी दे रहे हैं, इससे रेलवेज़ का – मैंने ब्रिज का उदारहण दिया, आज सभी जगहों पर जिस तरह की गति से रेलवेज़ बढ़ रहा है, वह उत्तम है। महोदय, पहले हमें लगता था कि अगर हमें डिस्टेंस पार करना होगा, तो हम हवाई जहाज से ही जल्दी पहुँच पाएंगे, लेकिन आज सड़कें हैं, सड़कों के अलावा आज रेलवेज़ में वंदे भारत ट्रेन्स हैं और जिस तरह से आज लोगों को वहाँ पर एक आदत सी लगती जा रही है, उससे किसी को नहीं लगता कि मैं हवाई जहाज से आगरा जाऊँ, किसी को नहीं लगता कि मैं हवाई जहाज से ग्वालियर जाऊँ, बल्कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं वंदे भारत ट्रेन से लखनऊ चला जाऊँ। महोदय, अब लोग मुंबई से नासिक और शिरडी वंदे भारत ट्रेन से जाते हैं। यह प्रगति का एक चिह्न है।

महोदय, जब बुलेट ट्रेन शुरू होगी, तो और भी अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में अलग-अलग बातें की हैं कि बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है? क्या आपको अपने देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना है? अगर आपके देश में बुलेट ट्रेन चलेगी, तो क्या आपके मन में गर्व का भाव नहीं होगा? महोदय, आज अगर एक देश की प्रगति का सिलसिला जारी होता है, तो उसका स्वागत सभी लोगों को करने की जरूरत होती है।

महोदय, मैं इसीलिए आपसे कहना चाहूंगा कि आज हमारा एनर्जी पर कितना फोकस है? एक जमाना था कि पॉवर प्लांट लगाने के लिए हमारे मित्र के पास जा-जाकर मांगना पड़ता था कि हमें मंजूरी दे दीजिए। महोदय, उन्होंने कितने सालों तक, कितने पॉवर प्लांट्स को और इस देश के कितने लोगों की उम्मीदों को, उद्योगों को तरसाया है, मैं स्वयं उसका उदाहरण हूं।

श्री जयराम रमेशः सर, इनके घोटाले ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रफुल्ल पटेलः आप छोड़िए। ...(**व्यवधान**)... आपको इसके अलावा कुछ और बोलना आता ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)... आप छोड़िए। ...(**व्यवधान**)... नवी मुंबई का एयरपोर्ट, जो आज बनने जा रहा है, ...(**व्यवधान**)... मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह केवल आपकी मेहरबानी से हुआ है। ...(**व्यवधान**)... आप मुझे क्या बता रहे हैं? आप छोड़िए। ...(**व्यवधान**)...मैंने जान-बूझकर यह बात बोली है, क्योंकि आपको इसके अलावा और कुछ बोलना आता नहीं है। आप छोड़िए। ...(**व्यवधान**)...

इन्हें ऐसी बातें करने के अलावा कुछ और मालूम नहीं है। ...(**व्यवधान**)... आप बातें करते हैं। आपके मन में कोई जज्बा नहीं है। आपके मन में सच्ची बातें सुनने का जज्बा नहीं है, आप छोड़िए। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, आज इस तरह से पॉवर प्लांट्स में जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ थीं, हम उन्हें छोड़कर एक नए युग में जा रहे हैं। पूरा विश्व देख रहा है। महोदय, आज जो solar energy है, हमारे देश में इतनी बड़ी मात्रा में सोलर एनर्जी है, हम wind energy को harness कर रहे हैं, आज ग्रीन हाइड्रोज़न की बात हो रही है, हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन की कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अगर मैं इथेनॉल की बात कहूँ, तो आज हमारे देश में 20 प्रतिशत तक मिक्सिंग करने का मौका अब मिला है। इथेनॉल को आप केवल एक फ्यूल के हिसाब से ही मत छोड़िए, बल्कि आज फार्मर्स को कितनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल की वजह से, एक productive farming का मौका मिला है। मैं अपने ही क्षेत्र में देखता हूं कि हम एक जमाने में इथेनॉल के लिए खाली शुगरकेन की बात करते थे कि उसके जूस में से कंवर्ट करो, लेकिन आज मक्के से इथेनॉल बनता है, राइस से इथेनॉल बनता है। महोदय, ब्रोकन राइस, जो हमारा अदरवाइज़ वेस्ट होता था, आज हम उससे productively इथेनॉल बना रहे हैं। इसका फायदा किसको मिल रहा है - इस देश के किसानों को मिल रहा है। उन्हें उनकी उपज का ज्यादा दाम मिल रहा है। उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इसका positive असर हो रहा है, तो हम लोगों को इन सब बातों को कहीं-न-कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भारत बदल रहा है।

आज आप फूड सिक्योरिटी के मामले में सोचिए। मैं कह रहा था कि रोटी, कपड़ा, मकान ही हमारा एक मूल मंत्र था। वह जमाना बदल गया है। चार करोड़ मकान बन चुके हैं। चार करोड़ मकान अगले पाँच साल में बनने वाले हैं। ज़रा बताइए कि विश्व में कोई भी ऐसा देश है, चाहे वह कितना भी प्रगतिशील हो, इतनी complex प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया और कैसे सॉल्व कर पाए हैं? यह भी हम लोगों को कहीं-न-कहीं कबूल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ, 80 करोड़ लोगों को पिछले तीन साल से और अगले पाँच साल की गारंटी मोदी साहब ने दी है, जिससे अब किसी को भी इस देश में भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। इस बात की खबरदारी ली गई है।

मैं थोड़े समय में इतना ही कहूँगा कि आज बजट में मिडिल क्लास को पहली बार सम्मान दिया गया है। आज तक ऐसा ही होता था कि सभी वर्गों को कुछ-न-कुछ दे दो, लेकिन मिडिल क्लास ऐसा था कि उसके लिए एक ओर महंगाई की परेशानी होती थी, एक ओर उनके बढ़ते हुए एंबीशन और आकांक्षाओं की बात आती थी और वे सैंडविच हो जाते थे। उनके लिए न इधर का रास्ता था, न उधर का रास्ता था। उन्हें अपना जीवन सीमित आय में गुजरना पड़ता था। आज एक लाख रुपए महीने की सामान्य इनकम बहुत से मिडिल क्लास लोगों की भी है। ...(**समय की घंटी**)... एक लाख रुपये की इनकम पर एक मिडिल क्लास फैमिली को 80,000 रुपए तक का सालाना फायदा हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि 80,000 में कितने लोग अपनी गाड़ी, घर या अन्य वस्तुओं की ईएमआई दे सकते हैं। आज आप लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन के सामने एक hedge के तौर पर भी टैक्सेशन का फायदा हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार): माननीय सदस्य, आपका टाइम खत्म हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रफुल्ल पटेल: मेरे पास बीजेपी से वक्त है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: कहाँ से है? ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रफुल्ल पटेल: यहाँ से। ...(**व्यवधान**)... आपके पास तो वक्त बचा ही नहीं है, जबकि यहाँ तो वक्त ही वक्त है। इशारा समझ जाइए। आपके पास वक्त ही नहीं है, यहाँ वक्त ही वक्त है। अंत में, मैं इतना ही कहूँगा कि भारत का यह सफर सुहावना है। इस सुहावने सफर करने के लिए नेतृत्व भी वैसा ही दमदार और शानदार चाहिए और आज मोदी जी के माध्यम से, यह हमारे देश को प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सबके प्रयास में आपका साथ जोड़ दीजिए, तो देश आगे बढ़ेगा और आपको भी थोड़ी बहुत तसल्ली मिलेगी कि देश के लिए कुछ हमारा भी योगदान रहा है। आपको इतना ही कहते हुए, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

SHRI IMRAN PRATAPGARHI: Madam, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री चंद्रकांत हंडोर (महाराष्ट्र): मैडम, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे नेता खरगे साहब का भी आभारी हूँ। इस बजट को लेकर मैं मेरे कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। यह मेरी मेडन स्पीच है।

देश में हजारों साल से एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग को उन्नति का रास्ता नहीं मिला था। देश की स्वतंत्रता के बाद इन सभी पिछड़े वर्गों का विकास करने का मौका हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत हर सरकार को मिला है। हमारे प्रधान मंत्री जी भी कहते हैं कि 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। देश को विकसित करने के लिए जो तकनीक और इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उसके लिए कार्य करेंगे, लेकिन जो जातिवाद का बुनियादी ढांचा है, उसे समाप्त करना भी बहुत जरूरी है। जब तक पिछड़े हुए और गरीब लोगों का शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक तौर पर उत्थान नहीं होता है, तब तक 2047 क्या, और 50 साल बाद भी हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि देश की तरक्की के साथ-साथ इन पिछड़े वर्गों को साथ में लाना भी जरूरी है। दुर्भाग्यवश जो 2025-26 का बजट मैं देख रहा हूं, उसमें सामाजिक न्याय विभाग के बजट में बहुत वेरिएशन दिखाई दे रहा है। हालांकि 2011 की एससी की संख्या 16.6 प्रतिशत है, एसटी की संख्या 8.2 प्रतिशत है और ओबीसी की संख्या, जिसे मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार 52 प्रतिशत होना चाहिए था, लेकिन अगर हम उसे भी छोड़ दें, तो कम से कम वह 27 प्रतिशत तो होनी ही चाहिए, लेकिन वह भी नहीं है। Denotified areas में रहने वाले लोग and nomadic tribes की संख्या 7 प्रतिशत है। कुल मिलाकर अगर हम आंकड़े देखें, तो वे 70 प्रतिशत के ऊपर जाते हैं और यह 70 प्रतिशत लोगों को उनके विकास के लिए सरकार जो भावना व्यक्त करती है, सरकार जो मुद्दे उपस्थित करती है, सरकार जो योजना तैयार करती है, उस योजना का इंप्लिमेंटेशन नहीं होता है। उनके लिए जो प्रावधान किया जाता है, वह

भी नहीं होता है। 2005 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंह साहब के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी। उसमें कहा गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी की जनसंख्या के अनुसार सामाजिक न्याय विभाग को निधि देनी चाहिए। 2010 में प्लानिंग कमीशन द्वारा डा. नरेन्द्र जाधव के नेतृत्व में टास्कफोर्स तैयार की गई थी। उसमें भी यह कहा गया कि उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको हिस्सा देना चाहिए। उसके बाद 2015 में नीति आयोग आया। यदि हम 2017-18 की नीति आयोग की ड्राफ्टिंग देखें, तो उसमें भी यह कहा गया है कि according to population, एससी, एसटी, ओबीसी, VJNT को percentage देना चाहिए। अगर इस साल मोटा-मोटा अर्थ संकल्प को देखा जाए, तो वह 50 लाख करोड़ का है। इस अर्थ संकल्प के हिसाब से हम देखें, तो 16.28 परसेंट एससी को मिलना चाहिए, 8 per cent एसटी को मिलना चाहिए, 27 per cent ओबीसी को मिलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो रहा है। चलो हम उनको भी छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा यह कहना है कि नीति आयोग ने इस वर्ष 2,30,000 करोड़ रुपए सामाजिक न्याय विभाग को देने की सिफारिश की है। वित्त विभाग ने सिर्फ 62,000 करोड़ सामाजिक न्याय विभाग को दिया। यह कहा गया कि हम लोग 2,30,000 करोड़ में से 1,68,000 करोड़ देंगे, लेकिन वह नहीं दिया गया। उसके बाद 62,000 करोड़ दिया और उसमें भी और बदलाव किए गए। आज लोगों को सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट के बारे में ही मालूम है। लोग उसकी तरफ अपेक्षा से देखते हैं कि हमें इस विभाग से अपने विकास के लिए फंड मिलेगा। आप देखेंगे कि इस डिपार्टमेंट के साथ और 26 concerned departments बनाए गए। मैं इसके बारे में समझता हूं। 62,000 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, उसमें सिर्फ 13,000 करोड़ रुपये ही सामाजिक न्याय विभाग को दिया गया और 49,000 concerned department को दिया गया है। आज देश भर के पूरे स्टेट्स में बोंबाबोंब चल रहा है। वहां के लोग यह कहते हैं कि हमारा पैसा लैप्स होता है। हमारे डिपार्टमेंट का पैसा योजना नहीं बनाने की वजह से लैप्स हो जाता है। उसके बाद लास्ट मूमेंट में विधान सभा या परिषद में जो सप्लिमेंट्री बिल आता है, तो कहा जाता है कि यह खर्च नहीं हो रहा है। वह दूसरे डिपार्टमेंट को divert किया जाता है। इससे लोगों के बीच में असंतोष है। हमारा कहना यह है कि जब हम विकसित देश की बात करते हैं, तो हमारे पिछड़ा वर्ग का विकास होना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए आप देखेंगी कि कर्णाटक स्टेट और आन्ध्र प्रदेश स्टेट, इन दोनों स्टेट्स ने अपने स्टेट लेवल पर कानून बनाए कि जो भी पैसा divert होता है, उसको एक साल के लिए carry forward करना चाहिए और जो पैसा lapse होता है, वह lapse नहीं होना चाहिए। कई जगहों पर ऐसे अधिकारी बैठे हैं, जो यह सोचते हैं कि जाने दो, यह दलित की स्कीम है, इसको क्यों करना है। उनके दिमाग में ऐसी भी सोच आती है, जान-बूझ कर वे स्कीम को बाजू में रखते हैं और पैसा lapse किया जाता है। इसलिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको 3 साल की सजा होनी चाहिए और किसी भी हालत में यह पैसा divert नहीं होना चाहिए। मैं सभागृह से, सरकार से विनती करूँगा कि केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसे प्रावधान के साथ कानून लाना चाहिए और पूरे देश के जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ यह कानून लागू किया जाना चाहिए, ताकि जो सामाजिक न्याय है, वह सबको मिले। आज हम संविधान का 75 years, अमृत महोत्सव celebrate करते हैं। इस सभागृह में सभी नेताओं ने अच्छी-अच्छी स्पीच दी, बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इसलिए इस 75वें साल के अवसर पर सरकार को यह कानून लाना चाहिए, ऐसी मेरी माँग है।

दूसरी बात यह है कि आप देखेंगी, हम 75वाँ साल, अमृत महोत्सव celebrate कर रहे हैं और दूसरे बाजू में हर रोज, हर दिन atrocities के cases बढ़ते जा रहे हैं। आज करीब दो लाख-पौने दो लाख cases pending हैं। जो SC Commission है, उसके पास 50,000 cases pending हैं। उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, वह कारवाई नहीं होती है। उसके लिए यहाँ पर कुछ 471 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन वह प्रावधान बहुत कम है। आज 2 लाख केसेज़ हैं। जिनका घर जलाया जाता है, जिनकी खेती जलाई जाती है, जिनका शारीरिक नुकसान किया जाता है, जिनका मानसिक रूप से नुकसान किया जाता है, उनका पुनर्वसन करने के लिए सरकार उनको मुआवजा देती है। At least 20 या 25 लाख रुपए हर व्यक्ति के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो 5-7 साल में ये सारे cases nil हो सकते हैं। उसके लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

मैडम, मैं एक बात भूल गया कि जो 26 डिपार्टमेंट्स हैं और जो सामाजिक न्याय विभाग है, तो सामाजिक न्याय विभाग को 50 परसेंट बजट देना चाहिए और 50 परसेंट बजट बाकी डिपार्टमेंट्स को देना चाहिए। ऐसी योजना एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के लिए मददगार हो सकती है। बाकी डिपार्टमेंट्स के पास भी योजनाएँ हैं।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब मैं महाराष्ट्र में मिनिस्टर था, तो मैंने हर जिले में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर सामाजिक न्याय भवन बनाया था। एक-एक भवन 10-10 करोड़ का है। महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने 36 डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर भवन बनाए थे। उसमें यह व्यवस्था थी कि उसमें सारे डिपार्टमेंट्स, सामाजिक न्याय विभाग के concerned departments के अधिकारी बैठेंगे। जिले के हेडक्वार्टर में वह बिल्डिंग रहेगी, भवन रहेगा। उस भवन से जिले के कोने-कोने से आने वाले हर इंसान को मालूम पड़ेगा कि सामाजिक न्याय विभाग के लिए, पिछड़े लोगों के लिए यह विकास का भवन यहाँ पर है, तो वहाँ पर जाकर हम लोग उसका फायदा ले सकते हैं। इसी तरह हर जिले में सामाजिक न्याय भवन की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि देश के करीब 750 जिले हैं, तो हर जिले में अगर डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर वे भवन बनते हैं, तो Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, Nomadic Tribes के सारे लोग वहां पर जाएँगे। उनके लिए क्या स्कीम्स हैं, उनका फायदा कौन सी स्कीम में है, वे देखेंगे और उनका फायदा उनको मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके जमीन लीजिए, वहाँ पर बजट दीजिए और उस तरह से उनका काम शुरू कीजिए। अगर अभी से वहाँ शुरुआत हो जाएगी, तो 2047 तक विकसित भारत बनने के साथ-साथ इन सारे पिछड़ों का विकास भी दिख जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।

उसी तरह से यहां पर होस्टल की योजना सामाजिक न्याय विभाग में रखी है। एक ही होस्टल के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। मैंने तो महाराष्ट्र में हर तहसील में - महाराष्ट्र में 353 तहसीलें हैं, 36 जिले हैं, तो उनमें मैंने 5 साल के अंदर लड़कों के लिए तथा लड़कियों के लिए 150 होस्टल्स बनाए। मैं चाहता हूं कि देश के हर जिले में बच्चों तथा बच्चियों के लिए ऐसे होस्टल्स बनाए जाएं, भले उन पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण रहे। उन पर केन्द्र सरकार

का ही नियंत्रण रहना चाहिए, लेकिन को-ऑपरेशन स्टेट गवर्नमेंट से लेना चाहिए। इस प्रकार, उसमें होस्टल का भी प्रावधान भी करना चाहिए। दूसरा, एससी समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जाए। इसमें भी सरकार की रेजिडेंशियल स्कूल्स की जो भूमिका है, उसके लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं चाहता हूं कि at least एक जिले में एक रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित करें। अभी एक गांव के मां-बाप अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे जिले में जाकर नौकरी करते हैं। नौकरी यानी जो भी रोजगार उनको मिलता है, वे करते हैं और उनको अपने बच्चों की तरफ देखने का मौका नहीं मिलता है। इससे illiteracy बढ़ रही है। उससे साक्षरता का परिमाण कम हो रहा है। अगर बच्चों को वहाँ रेजिडेंशियल स्कूल में रखेंगे, तो उनका स्कूल भी वहीं पर होगा, उनका होस्टल भी वहीं पर होगा तथा उनके खान-पान और सारा जो प्रबंध है, वह एक कॉम्प्लेक्स में हो जाना चाहिए। इसके लिए पूरे देश में ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल्स की योजना बनानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

दूसरा यह है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए Venture Capital Fund योजना के तहत एससी और ओबीसी के उद्यमियों को नये व्यापार और उद्योग में प्रवेश करने के लिए वित्तीय सहायता देने की जो बात है, इसके लिए Venture Capital Fund का निर्माण करना चाहिए, ऐसा वित्त विभाग का कहना है। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर हजारों करोड़ रुपए सामाजिक न्याय के लिए या बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो हम क्यों Venture Capital Fund खड़ा करें! सामाजिक न्याय विभाग को उसके लिए पैसा देना चाहिए, हजारों करोड़ रुपये देना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम स्टार्टअप इंडिया चलाएँगे, हम मुद्रा लोन देंगे और हम बाकी की योजनाएँ लाएँगे, तो एससी, एसटी, ओबीसी और Nomadic Tribes के लोगों के लिए भी यह जरूरी है। जब मैं मिनिस्टर था, तो करीब 400 के ज्यादा एससी-एसटी के लोगों को 7-7 करोड़ रुपये देकर मैंने उनके लिए फैक्ट्री का सेटअप तैयार किया था। ...(**समय की घंटी**)... हमने मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था नाम से एक संस्था बनाई थी और उनको 7-7 करोड़ रुपया वहाँ पर दिया गया था। मेरी यह रिक्वेस्ट रहेगी कि यहां पर जो उतना प्रावधान नहीं किया है, सिर्फ 2 लाख रुपये का प्रावधान इसके लिए किया गया और Venture Capital Fund के माध्यम से यह पैसा खड़ा करने की बात हो रही है। मेरा कहना है कि सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना चाहिए और हमारे Scheduled Castes, Scheduled Tribes के बच्चों को आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

यहां पर और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे - सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप, Scholarship for Higher Education है, यह इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें मैं चाहता हूं कि जो foreign scholarship है, हम जो फॉरेन में बच्चे भेजते हैं, महाराष्ट्र में सिर्फ 575 बच्चों को abroad में एजुकेशन के लिए भेजते थे। इसमें देश भर से 125 बच्चों को भेजने का प्रोविजन है। मैं चाहता हूँ कि देश भर से कम-से-कम 1,000 बच्चे फॉरेन स्कॉलरशिप के माध्यम से विदेश में एजुकेशन लेने के लिए जाएँ, चाहे वह academic education हो या professional education हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उनको वहां पर भेजना चाहिए - ऐसी मेरी मांग है। मैंने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। मैं चाहता हूँ

कि हमारे वित्त मंत्री इसके ऊपर गौर करें। जब 2047 में विकसित भारत की बात होती है, तो साथ-साथ इन सारे समूहों का भी विकास हो जाना चाहिए - यह मेरी मांग है, धन्यवाद।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री पी. विल्सन)** *पीठासीन हुए।*]

श्री जयराम रमेश: सर, मेरा आपके माध्यम से नेता सदन से गुजारिश है कि जब बजट पर चर्चा चल रही है, तो वित्त राज्य मंत्री तो मौजूद हों। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है कि आप वित्त राज्य मंत्री को तो यहां बिठाइए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): The next speaker is Shri Saket Gokhale.

SHRI SAKET GOKHALE (West Bengal): Thank you, Sir, for giving me the opportunity. I have heard a lot of speeches over the last couple of days, lots from that side because they get more time. There is one thing we are not taking seriously, and I have to say this, Sir, that our economy is in serious trouble. Our economy is very shaky today, just like this shaky coalition that came to power in June 2024. Sir, when a wall is infested with termites, putting even 2047 layers of paints, is not going to fix that wall. The termites will continue to hollow that wall until that wall falls down. That is the state of our economy today. It is rotten and crumbling from inside. In this Budget, the hon. Finance Minister has tried to put 2047 layers of paint on this wall but the wall of this economy is going to crumble unless something serious is done. Sir, [£] Therefore, Sir, this is the charge sheet being filed by me today on behalf of the people of India against the Government for destroying the Indian economy. [£] and the judges, of course, are the people of India. Sir, the case is called the people *Vs.* the Modi Government.

Let me now tell you the chronology. [£] When the Prime Minister showed up on our TV screens and in one swoop of knife announced the disastrous decision called demonetization. The demonetization killed the one important thing that investors look for, which is stability. After this demonetization, private investors lost faith in the Indian economy. As a result, the amount of private investment in the Indian economy started falling. Now, the problem is that, when the businesses do not invest, businesses cannot grow. And the Modi Government then realized that when a business does not grow, that business cannot contribute funds to their party kitty. Therefore, in 2019, the Modi Government drastically slashed the taxes on corporates. We have come to a bizarre point in our economy today, when income-tax paid by

[£] *Exupnged as ordered by the Chair.*

Indian citizens is higher than the tax paid by corporates. After slashing corporate tax, the Modi Government hoped that corporates would start putting those savings into the economy. ...*(Interruptions)*.. But that did not happen. Sir, corporates completely lost faith in the ability of the Modi Government to run the economy. Therefore, instead of making new investments, corporates started using their savings from tax cuts to pay off existing debts or they started putting them in their own reserves. They did not invest in the market even after this tax cut. So, now, due to the lack of corporate investment, there has been a lack of jobs in the market because no new jobs are being created. Due to this, Sir, unemployment in India is at a 45 year high level. Lack of investment in economy led to a fall in the supply of goods; naturally. And, lack of employment resulted in people having no money which killed demand and consumption. Sir, this was followed by the devastating Covid-19 pandemic, which was again imposed by PM Modi announcing on TV at 8.00 p.m. that after 12 o'clock, everything is going to be locked down. We saw migrants losing their jobs, walking thousands of kilometers back to their villages from cities. The Modi Government could have fixed this, during the pandemic, by putting more money into people's pockets, either through tax cuts or through a stimulus. Sir, we saw in the United States that ... ...*(Interruptions)*... Madam, you are new in Parliament; learn and then you can comment on what is unparliamentary.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Go ahead.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, like the United States, the Government could have put money into the pockets of people. Instead of doing that, the Government did nothing. ...*(Interruptions)*... Sir, instead, the Government decided to compensate for lack of demand from people by artificially creating demand through Government spending. This spending is called 'capital expenditure' or 'CAPEX.' How did the Government raise money for this spending? It did so by heavily taxing the people of India. Sir, CAPEX spending creates shiny new infrastructure, highways, like this new Parliament building we are sitting in, like this harebrained Central Vista that this Government has planned. So, in the middle of a broken economy, they are spending crores of rupees on creating all of these things. The problem with Capex-spending is that it does not create jobs across sectors. Capex-spending of thousands of crores by the Government led to a sudden rise in the supply of money, liquidity, which led to inflation. Prices of goods started to go up. The Modi Government brought our economy to a point where people have no money left, but inflation is rapidly increasing which has led to price rise. Sir, we are in this stage of economics called

'stagflation.' It is stagnancy plus inflation. Today, the total amount of loans given by banks is much higher than the number of deposits made by people in banks. The question is, if people are taking loans, why are they not spending that money on consumption? The reason for this is that people are taking new loans either to meet their basic needs or to pay-off existing debts. The amount of outstanding unsecured loans like credit cards and personal loans in our economy today is equal to a shocking Rs. 62 lakh crores. That represents 35 per cent of India's GDP. Sadly, Sir, the words 'inflation', 'unemployment', 'price rise' do not find a mention in the Finance Minister's speech. Forget that. Even promises made in the last Budget seven months ago have conveniently disappeared from this Budget. In the last Budget, the Finance Minister announced the 'PM Internship Scheme' where the target was to offer one lakh twenty-five thousand internships in private companies to the youth. What is the current status, Sir? She didn't say it in her speech. Only 10,000 internships, out of a target of 1,25,000, have been provided. That is less than 10 per cent of the target that has been met. Now in this Budget also, several new schemes have been announced. This is the pattern. The Finance Minister will come, announce 20 new schemes in the Budget and hope that by the next Budget, the people would have forgotten about the previous schemes. So you don't have to give a status update. Just keep announcing new schemes where there is no follow-up on any of that.

Sir, this Modi Government in December, 2023 passed the *Bharatiya Nyaya Sanhita* after suspending 146 MPs in this House. Therefore, I am going to read out the charges against this Government based on the Sections of the *Bharatiya Nyaya Sanhita* because nobody really knows about the details of this thing.

Sir, in the matter of people versus the Modi Government, we have Section 212 - offence for furnishing false information. In her budget speech, the hon. Finance Minister announced a major income tax relief. Good. However, while announcing it, she declared that the Government was foregoing a revenue of Rs. 1 lakh crore through this tax relief. How true is this? Sir, the tax revenue of the Union Government this year was Rs. 25 lakh crore. In the next year, according to the Budget, the tax revenue is going to increase to Rs. 28 lakh crore. It is going to go up. The revenue deficit of the Government last year was 1.9 per cent of GDP. That GDP, the Finance Minister said in the next Budget is going to fall to 1.5 per cent of GDP. So, in simple terms, the Government is going to earn more from taxes in this Budget. How is it going to do this? By compensating for the reduction in income taxes through GST and other indirect taxes through which people are going to be extorted. Sir, only 2.2 per cent of India's population pays income tax, benefits from it. But 100 per cent of

the population pays GST. When you take money through GST, everybody is going to get impacted by that.

Sir, in the matter of people versus the Modi Government, then, section 67 - £. In 2021, my leader, Ms. Mamata Banerjee, and the people of my State, West Bengal, resoundingly defeated the BJP in the Assembly elections. ...*(Interruptions)*... Despite the constant efforts to target and defame the people of Bengal, PM Modi's BJP could not win against Ms. Mamata Banerjee. After the BJP's loss, the Modi Government started depriving the State of Bengal of its rightful dues by withholding payment. Under various Schemes like MGNREGA and *Awas Yojana*, Bengal's dues of over Rs. 1.75 lakh crore have been withheld by the Modi Government. So this is a £ hatched by the Modi Government of depriving Bengal just because our people don't vote for them. ...*(Interruptions)*... Then, Sir, section 308 - £. The Modi Government is £ the people of India through blood-sucking taxes like the GST. People's incomes are being £ from them by imposing GST on everything under the Sun. So, even something as simple as health and life insurance premiums have not been exempted. ...*(Interruptions)*... My Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, last year wrote a letter requesting that the 18 per cent GST on insurance be removed.

2.00 **P.M.**

This Government has still not done that. Sir, instead of the *license raj*, today we have the *GST raj*. Companies across India live in the dread of the GST Inspector who would find the smallest violation and would then £ huge fines from them. ...*(Interruptions)*... The purpose of this £ from corporates is to encourage them to quietly donate crores. ...*(Interruptions)*...

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Sir, I want a ruling... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): One minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAKET GOKHALE: I am not yielding, Sir. ...*(Interruptions)*... Sorry, I am not yielding. He can have his chance later. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): One minute. ...*(Interruptions)*...

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

SHRI SAKET GOKHALE: No, I am not yielding, Sir. ...*(Interruptions)*... I am categorically not yielding.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: It is not a question of yielding. It is a question that he would have to understand. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAKET GOKHALE: Mr. Nadda, this is not going to help you win elections. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I would request you to expunge the words that are unparliamentary. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAKET GOKHALE: Mr. Nadda, this is not going to help you win elections. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, he is using unparliamentary words. He should have at least the decency of having a better debate. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, this is absolutely uncalled for from the leader of the House. Mr. Vice-Chairman, Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I am sorry to say that the standard of debates has been reduced to such a level that the expressions and words which are being used are unparliamentary. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, my time is not being paused. ...*(Interruptions)*... Sir, my time is not being paused. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, I would request you to better advise the Member to use parliamentary words. That is number one. Number two, remove all the unparliamentary words used by the Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): We would consider that. ...*(Interruptions)*... Please go ahead, Mr. Gokhale. You have got two minutes.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, he has taken a minute of my time. ...*(Interruptions)*... I have lost one minute of my time. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please go ahead. You have two more minutes. ...*(Interruptions)*... Please finish. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, Mr. Nadda...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please, no personal exchanges ....*(Interruptions)*... Go ahead.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, the hon. Leader of the House is understandably insecure of the 2026 elections in West Bengal. The frustration is coming out. But that is okay. Ms. Mamata Banerjee is going to win again. Delhi did not have Trinamool Congress, Madam. ...*(Interruptions)*... Sir, section 351 — £. From students to journalists, to an average Indian posting on social media, everyone lives under the constant threat of £ by the Modi Government. If you criticize the Government, you are punished. Minorities in our country live in a state of constant dread and fear of the Government. ...*(Interruptions)*... Sir, now I have to say something very important which the Leader of the House might be interested in. मिनिस्टर को क्रेडिट नहीं मिलता; Prime Minister would come and wave the flag. ...*(Interruptions)*... Sir, I understand their predicament. So, I understand, Mr. Nadda; you have to do your job. ...*(Interruptions)*... Sir, the matter — 'people *versus* Narendra Modi', section 318 — £ In the last eleven years, the Modi Government has been systematically £ the people of India. They have even found a new word to describe it, called '*jumla*'. ...*(Interruptions)*... Prime Minister, Modi's promise to create two crore jobs — *jumla*; PM Modi's promise to double farmers' income by 2022 — *jumla*. Therefore, in this Union Budget, you will find the term '*Viksit Bharat*-2047'. The £ is not short-term now; the £ is now till 2047; you will have to wait. ...*(Interruptions)*... Sir, all I have to say at the end is this. The jury in this...(*Time-bell rings.*) He took one minute of my time. Now, I would take one minute. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Kindly conclude.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, to put it very simply, in this charge sheet, jury is normally 12 people; you are a Senior Advocate as we know. ...*(Interruptions)*...

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Kindly conclude.

SHRI SAKET GOKHALE: In this matter, the jury is the 1.6 billion people of India. Let me tell you something what Shri Gopal Krishna Gokhale said, 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow.' ...*(Interruptions)*... Now, Saket Gokhale is saying that in 2026 in Bengal, the BJP would be cleaned out and thrown out by Mamata Banerjee, and what Bengal does in 2026, India will repeat that in the rest of the country. Thank you, Sir.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Mr. Vice-Chairman, Sir, we want a ruling from you. He has used words like £ and others. All these unparliamentary words have to be expunged. ...*(Interruptions)*... I want a ruling from you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): We would certainly give that ruling. ...*(Interruptions)*... We would certainly give a ruling on that. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: And, Sir, these words should be expunged from the proceedings of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): We would go by the rules. ...*(Interruptions)*... The word £ is unparliamentary. We would certainly look into it. We would look into it. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... I call upon the next speaker, Shri Meda Raghunadha Reddy. Your time is six minutes.

SHRI MEDA RAGHUNADHA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise today to address the House on a Budget that embodies the timeless wisdom of our ancient text "*Sarve Bhavantu Sukhinah*" -- may all become happy, may all be free from illness. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Please allow him to speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI MEDA RAGHUNADHA REDDY: This vision of collective well-being resonates strongly with the goals set by our hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister, whose focus on GYAN -- *Garib, Yuva, Annadata and Nari* -- guides us towards a

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

Viksit Bharat. ...*(Interruptions)*... However, as a representative of Andhra Pradesh, I must draw the attention of this House to the unique challenges our State continues to face, even as we celebrate the nation's growth and progress. ...*(Interruptions)*...

Sir, today India faces a rental crisis, especially in urban areas. ...*(Interruptions)*... The rent of a 1000 square feet house in Delhi, Mumbai or Bengaluru is about Rs.40,000 per month with additional security deposit which is unaffordable for many. Rents in India are increasing by 12 per cent to 15 per cent each year and, therefore, finding affordable homes is becoming difficult for the middle class in our cities and our State is not an exception. Therefore, there is further need to control the rental prices by allowing more construction of housing units and also expanding.

Sir, the Government's plan to set up five National Centres of Excellence for skill development is a major step towards preparing India's youth for the future. A Rs.500 crore Centre of Excellence for AI in education will further boost learning opportunities. Given Andhra Pradesh's large youth population, we urge the Centre to ensure that one of the five skill development centres is set up in the State of Andhra Pradesh.

The Government's decision to allocate additional funding for infrastructure and fellowships across all IITs, including a boost for the five youngest IITs like IIT Patna, is a welcome step to strengthening higher education. However, IIT Tirupati also requires similar financial support to enhance its infrastructure, expand research facilities and accommodate more students. We urge the Centre to ensure equitable funding for IIT Tirupati, enabling it to emerge as a leading institution in science and technology education in the southern part of India.

Sir, the recent income tax reforms, including raising the exemption limit to Rs.12 lakh and the standard deduction to Rs.75,000, will boost disposable income and stimulate consumer spending, savings and investments. However, despite the corporate tax cut from 30 per cent to 22 per cent in 2019, wage growth has lagged behind inflation, effectively reducing real incomes and dampening economic growth, even as corporate profits hit a 15-year high. Personal income tax now contributes 31 per cent of gross tax revenue, surpassing corporate tax at 26.75 per cent, shifting the burden onto salaried individuals. To address this imbalance, the Centre should decrease the tax on the individual from 30 per cent to 25 per cent so that the vicinity of the tax-paying community increases. Special mechanism may be adopted to decrease the fraudulent transactions, especially where the senior citizens are being victimised at large. A two-step authentication or a time-gap authorisation may be adopted to reduce these transactions considerably.

Regarding the Railway Safety, while we appreciate the ongoing improvements in the railway sector, safety remains a serious concern. Despite the introduction of the Kavach Train Collission Avoidance System (TCAS), it has limited coverage and inadequate funding. ...(*Time-bell rings.*)...I conclude, Sir. I take this opportunity to bring to the notice of the House and request the Government to please consider the long-pending wish of the people of our Rayalaseema region for setting up of new Balaji Railway Division of Tirupathi with its headquarters in newly-formed zone, that is, South-Coastal Railway Visakhapatnam.

In conclusion, while this Budget lays a strong foundation for a Viksit Bharat, it is imperative that the unique challenges of Andhra Pradesh are addressed with greater urgency and targeted interventions. I urge upon the Central Government to recognise the pressing concerns of our State and work collaboratively to fulfil the aspirations of our people. As the saying goes, "The prosperity of a nation lies in the prosperity of its States." Thank you, Sir.

SHRI SUBHASISH KHUNTIA (Odisha): *Jai Jagannath.* Hon. Vice-Chairman, Sir, this Budget is not for the people. It is a Budget for perception, a Budget for Press conferences, not for the public welfare. It is a Budget for announcements, not for accountability. It is a Budget for the privileged, not for the neglected. Odisha, the land that powers India's industries, is still left struggling for its rightful share. The USA's tariffs are disrupting the global trade, weakening the rupee and impacting India. As a BRICS Member, are we leveraging our partnership to protect our economy? This House must discuss the Government's strategy to counter these challenges and provide clear awareness to the people. Double-engine सरकार है, मगर ओडिशा की बग्गी खाली है। वादे के डिब्बे तो भर गए, मगर हकीकत में बदहाली ही बदहाली है। As the saying goes, "An empty vessel makes much noise", while the Government celebrates, the comman man struggles. हाल ही में प्रधान मंत्री जी ओडिशा के प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में गए थे, वे उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव में भी गए थे। वहाँ पर प्रधान मंत्री जी बोलकर आए थे, उन्होंने ओडिशा को दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार बताया था, लेकिन ओडिशा का क्या हुआ? महोदय, जब बजट का आवंटन हुआ, तो उसमें ओडिशा का नाम ही नहीं था। प्रधान मंत्री जी बार-बार पूर्वोदय की बात करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ओडिशा को हर बार नज़रअंदाज किया जाता है।

सर, मैं ओडिशा के फार्मर्स के लिए बोलूंगा। जब अचानक बारिश हो जाती है, फार्मर्स का क्रॉप लोस हो जाता है, तब फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं। जब उनकी क्रॉप का नुकसान होता है, तो वे ऐसा कर लेते हैं। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि ओडिशा के फार्मर्स के लिए क्या है? ओडिशा गवर्नमेंट बार-बार सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है, हमारे प्रिय नेता नवीन बाबू ने बहुत बार गवर्नमेंट से हेल्प करने के लिए बोला है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फार्मर्स के लिए कुछ भी

नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे ओडिशा प्रदेश को Special Category Status देने के लिए हमारे प्रिय नेता नवीन पटनायक जी बार-बार बोल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर cyclone है और natural disaster भी होता है, लेकिन जब बजट आता है, तो ओडिशा को Special Category Status का दर्जा नहीं दिया जाता है। यह क्यों होता है?

दूसरी बात, आप बिहार के इलेक्शंस को देखकर बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दे दीजिए। इसमें हमारा कुछ नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश को दे दीजिए, महाराष्ट्र को दे दीजिए, लेकिन जब ओडिशा की बात आती है, तो पुरी इंटरनेशनल टूरिज्म प्लेस है। उस टूरिज्म प्लेस में चार धाम में से महाप्रभु जगन्नाथ का धाम है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नवीन पटनायक जी ने लैंड acquisition किया, नवीन पटनायक जी ने बाउंड्री वॉल बनवाई, लेकिन हमारे जगन्नाथ पुरी, ओडिशा को आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं देते हैं। आप क्यों नहीं देते हैं? आपको सब लोग देख रहे हैं। आप आंध्र प्रदेश को देखिए। उससे बड़ी बात कोई नहीं है। ...(**समय की घंटी**)... जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, उससे सब बह जाएगा। जो ओडिशा के दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, मैं उन्हें भी देखना चाहता हूँ। मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि While the Minister claims that we are nearing the Viksit Bharat, the reality is that this Budget offers no relief for the poor and the middle class.

महंगाई की आग में जलता गरीब,
पर यह बजट सिर्फ सपनों की तकरीर,
थाली की रोटी हुई आधी से कम,
पर मंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत है करीब।

जय जगन्नाथ! वन्दे उत्कल जननी!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Thank you. Now, Shri Sanjay Yadav.

श्री संजय यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा का अवसर देने के लिए मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष, श्री तेजस्वी यादव जी और आपको भी धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, यह बजट आर्थिक विकास का नहीं, बल्कि जुमलों का एक दस्तावेज है और बिहार के लिए तो यह एक चुनावी बुलबुला है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, यह बुलबुला फट जाएगा। यह आम आदमी और किसानों का नहीं, बल्कि बाजार और धनवानों का बजट है। महोदय, यह प्रोग्रेसिव नहीं, रिग्रेसिव बजट है। इस बजट में युवाओं, किसानों, बेरोजगारों, छात्रों के लिए कुछ नहीं है। उनके लिए सरकार ने इस बजट में []नौकरी को न कहा, महंगाई को मोर, धरातल पर कुछ नहीं, बिना बात का शोर।[] इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है। अभी मैं सुन रहा था। हमारे ओडिशा के साथी बोल रहे थे, इधर के भी साथी बोल रहे थे कि इस बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है। मेरे साथियों यह सच्चाई नहीं है। बिहार को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। 2015 से वही घोषणाएं बार-बार हो रही हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 2015 में एक तरह से बोली लगाते हुए

1,65,000 करोड़ कहा था। आप पिछले दस वर्ष के जितने बजट भी उठाकर देख लीजिए, वही चीज़ repeat हो रही है। बिहार के लिए बजट में घोषणाएं संसद से शुरू होती हैं और संसद में ही खत्म हो जाती हैं। यहाँ की घोषणाएं दिल्ली का बॉर्डर भी पार नहीं कर पाती हैं, बिहार तो फिर भी 1,000 किलोमीटर दूर है। महोदय, इनकी घोषणाएं बिहार में बने हुए पुलों की तरह हैं। कागजों में तो ये घोषणाएं बहुत शानदार, लम्बी-चौड़ी और चमचमाती हुई नजर आती हैं, लेकिन धरातल पर उतरते ही जैसे बिहार में भरभराकर पुल गिर जाता है, वैसा ही इनकी घोषणाओं का हश्र होता है। हमारे बिहार में भोजपुरी में एक कहावत है – गाछ में कटहल, होंठ में तेल, यानी जब कटहल पेड़ पर रहती है, तो लोग होंठ पर तेल लगा लेते हैं। पिछले दस वर्ष से वहाँ की सरकार और बिहार के लोग झोली फैलाकर खड़े हैं कि कब कटहल से पेड़ गिरेगा, कब हमारा कल्याण होगा और हम उसे खाएंगे। सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, कुछ नहीं मिला है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार को वह मिला, जिसकी बिहार को जरूरत थी? क्या बिहार को वह मिला, जो पटना ने माँगा था या बिहार को वह दिया गया, जो दिल्ली देना चाहती थी? जो इस सवाल का जवाब देगा, वह बिहार और बिहार के लिए इस बजट का महत्व समझ जाएगा।

महोदय, बिहार के लिए योजनाएं तो बहुत बनाई जाती हैं और डंके की चोट पर बताई भी जाती हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता अलग है। जैसे कि इस बजट में बिहार के बारे में चार-पाँच बातों का जिक्र हुआ। चार-पाँच बार बिहार का नाम आया। चूँकि चुनावी वर्ष है, तो लोगों को लगा कि पता नहीं बिहार को क्या मिल गया। एयरपोर्ट्स की बात हुई। इन्होंने कहा कि बिहार में दो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे, इसका जिक्र नहीं है। कितनी राशि आवंटित हुई, इसका जिक्र नहीं है। बाद में सुनने में आया कि एक सोनपुर में बनाया जाएगा और एक राजगीर में बनाया जाएगा। महोदय, मैं उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताता हूं। वहां बीच में पटना है, उसमें एक पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन चल रहा है। यह बहुत वर्षों से चल रहा है और हर बजट में इसका जिक्र किया जाता है। इस बजट में भी जिक्र किया गया कि पटना में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है और बिहटा में भी हो रहा है, वह ब्राउनफील्ड बनाएंगे। दो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की बात हुई – सोनपुर और राजगीर। दो existing हैं और दो अन्य बनाने की बात हुई। महोदय, ये चारों एयरपोर्ट 65 miles or around 57 nautical miles की दूरी पर हैं। इन चारों एयरपोर्ट्स की क्या viability होगी? आप इधर सोनपुर में बनाएंगे, इधर राजगीर में बनाएंगे और बीच में पटना और बिहटा का तो ऑलरेडी existing है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या उद्देश्य है? अगर इस देश में 65 माइल्स पर कहीं पर 4 एयरपोर्ट्स हों, तो हम माननीया वित्त मंत्री और सरकार से कहना चाहेंगे कि इस संबंध में हमारा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिएगा। 65 माइल्स पर 4 एयरपोर्ट्स, जो आपने प्रपोज किए हैं, इनकी क्या viability होगी? यह नहीं बताया गया है कि ये कहां बनेंगे और इसके लिए कितनी राशि होगी? हम तो यही कहेंगे कि पहले बोलते थे कि 2005 से पहले तो सृष्टि ही नहीं थी, जैसे कहते थे कि 2014 से पहले कुछ नहीं होता था। 2005 से पहले बिहार में इंटरनेशनल फ्लाइट चलती थी।

महोदय, आप दरभंगा-बेंगलुरु का किराया देखिए। आज आप देखिएगा कि कल का किराया 60,000 – 65,000 रुपये मिलेगा। अगर आप बिहार को एविएशन सेक्टर में कुछ देना चाहते हैं, तो आप दूसरे शहरों में नई हवाई सेवा शुरू कीजिए। मखाना बोर्ड की भी बात की गई। महोदय, 23 साल पहले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना की स्थापना हुई थी। यह 23 साल से

कार्यरत है। वहां 42 सैंक्शन पोस्ट्स हैं और वहां स्टाफ में 10 लोग काम करते हैं। वहां आज तक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति भी नहीं हुई है। पिछले 5 सालों में मात्र 3 करोड़, 40 लाख रुपए ही खर्च हुए हैं। ...(**व्यवधान**)... मखाना और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना का मेन्डेट सेम ही है। जब रिसर्च सेंटर था, तो मखाना बोर्ड बनाने की क्या आवश्यकता थी? ...(**व्यवधान**)... इन्होंने Western Kosi Canal Project की बात की। महोदय, यह प्रोजेक्ट 60 साल से अधिक समय से चल रहा है। इस संबंध में बजट में केवल एक लाइन लिखी है कि वित्तीय मदद दी जाएगी, लेकिन कितनी मदद दी जाएगी, इसका जिक्र नहीं किया गया है। इस बजट में पेज 9 पर इन्होंने लिखा है कि Patna IIT will also be expanded. That's it! How will it be expanded? How much money will be given? There is no mention of it.

महोदय, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तो मैं माननीया वित्त मंत्री से पूछना चाहूंगा कि केंद्र के द्वारा बिहार में किया गया प्रति व्यक्ति निवेश कितना है और इसी सरकार का महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवेश कितना है? आपने बिहार में प्रति व्यक्ति निवेश कितना किया है और प्रति व्यक्ति निवेश की राष्ट्रीय औसत क्या है? यह सरकार हमें बताएं। बिहार पिछड़ा राज्य है, लेकिन इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया है कि बिहार में उद्योगों की स्थापना की क्या योजना है, पलायन रोकने की क्या योजना है, बिहार में बाढ़ और आपदा से निपटने की क्या योजना है, बेरोजगारी और गरीबी समाप्त करने की क्या योजना है? ...(**व्यवधान**)... बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम है, उसे बढ़ाने की क्या योजना है? ...(**व्यवधान**)... इन्होंने बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया, स्पेशल पैकेज नहीं दिया, लेकिन हां, बिहार को स्पेशल जुमले और स्पेशल सपने जरूर दिए हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि बिहार को नम्बर वन बना देंगे। 20 साल से वहां एनडीए की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार मुख्य मंत्री हैं और 11 साल से दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, लेकिन क्या बिहार को इन्होंने नम्बर वन बनाया? नहीं बनाया। ...(**व्यवधान**)... आप नीति आयोग का सूचकांक उठाकर देख लीजिए, कोई भी इंडेक्स उठाकर देख लीजिए, इन्होंने बिहार को नीचे से नंबर वन बनाया है। ...(**व्यवधान**)... विकास में नीचे से नंबर वन है, साक्षरता में नीचे से नंबर वन है, रोजगार देने में नीचे से नंबर वन है, स्वास्थ्य सेवाओं में नीचे से नंबर वन है, बुनियादी सुविधाओं में नीचे से नंबर वन है, आधुनिक सुविधाओं में नीचे से नंबर वन है। ...(**व्यवधान**)... एनडीए बिहार में 20 साल से सरकार में है। इन्होंने बिहार को कुछ चीजों में नंबर वन जरूर बनाया है। किन चीजों में नंबर वन बनाया है - अपराध में नंबर वन बनाया है, भ्रष्टाचार में नंबर वन बनाया है, पेपर लीक में नंबर वन बनाया है, बेरोजगारी में नंबर वन बनाया है, पलायन में नंबर वन बनाया है, नौकरी मांगने पर लाठी, डंडा चलाने और थप्पड़ मारने में नंबर वन बनाया है, multi-dimensional poverty में नंबर बनाया है। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, माननीया वित्त मंत्री 2020 के चुनाव में बिहार गई थीं, उन्होंने घोषणा की थी कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर 19 लाख नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी नौकरियां दी गईं? माननीया वित्त मंत्री जी इसका जवाब दें। आप दो दशक से वहां सरकार में हैं और एक दशक से यहां सरकार में हैं। मैं सरकार से इतना ही कहूंगा कि बहुत हो चुका है, अब बिहार का भाषण और राशन से शोषण मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)... 14 करोड़ बिहारवासी हैं, युवा बिहार है, वे भी सपना देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बिहार नंबर वन रहे।

हमारे नेता, तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए सरकार में थे, तो उन्होंने 5 लाख नौकरियाँ दीं, 3.5 लाख नौकरियाँ प्रक्रियाधीन करवाईं, ...(**व्यवधान**)... जातिगत सर्वेक्षण देश में प्रथम बार करवाया, ...(**व्यवधान**)... 65 प्रतिशत तक आरक्षण बढ़वाया। ...(**व्यवधान**)... 11 वर्षों से बिहार इनकी घोषणाओं की भेंट चढ़ रहा है। अरे, मन की बात करने वालों, थोड़ा अन्न की भी बात किया करो; सपनों की बात करने वालों, थोड़ा सच की भी बात किया करो।

महोदय, देश में आमदनी का कोई जरिया नहीं है। नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। आप जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी हमारी ambitions को माप सकता है, लेकिन हमारी condition को नहीं माप सकता है। मिडिल क्लास के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। लोग आर्थिक तंगी के कारण छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज ले रहे हैं। वे उसको चुका नहीं पा रहे हैं। देश में 10,000 रुपए का कर्ज लोग चुका नहीं पा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... हमारी अर्थव्यवस्था के हालात पर मुझे यह शेर याद आ रहा है:

दीवारें खड़ी हुई हैं,
लेकिन अंदर से मकान गिर रहा है।

अगर इन्हें सच्चाई से अवगत कराओ, तो ये बुरा मान जाते हैं। हम इन्हें कहते हैं कि आप बीमारी को खत्म करो, लेकिन ये बीमारी को खत्म करने के बजाय बीमार को ही खत्म करना शुरू कर देते हैं। महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि:

मुद्दतों पुरानी दीवार को कब तक
कलाकारियों से नया करते रहेंगे,
बुनियाद दिन-ब-दिन कमजोर होनी ही है,
दीवार रंगीन ही सही, गिरनी ही है।

महोदय, इन्होंने इस देश के नौजवानों की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। नोटबंदी ने आबाद व्यापार को बर्बाद कर दिया है, मुमकिन को नामुमकिन कर दिया है, सुख को दुख में बदल दिया है और देश की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है। ये बेरोजगार और युवाओं पर इतना अत्याचार कर रहे हैं कि ये अग्निवीर योजना लेकर आए। ठीक है, आप ले आए, लेकिन अब अगर कोई अग्निवीर का फार्म भरता है, तो उसको 550 रुपए देने होते हैं और उसके ऊपर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होता है। यह इन्होंने युवाओं के साथ किया है!

इसी बजट में पेज नंबर 12 पर माननीया वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया का ज़िक्र किया। आपने क्या मेक इन इंडिया किया है! इन्होंने मेक इन इंडिया किया है, महँगाई में मेक इन इंडिया हुआ है, बेरोजगारी में मेक इन इंडिया हुआ है, गरीबी में मेक इन इंडिया हुआ है, पलायन में मेक इन इंडिया हुआ है, इन्होंने नफरत और घृणा का मेक इन इंडिया किया है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जब मुल्क में शांति, सौहार्द, प्रेम और भाईचारा होगा, समावेशी नीतियों और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप निर्णय लिए जाएँगे, तभी हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। सामाजिक सद्भाव रहेगा, तभी देश आगे

बढ़ेगा, नहीं तो चंद लोगों को छोड़ कर कोई आगे नहीं बढ़ेगा। महोदय, हालात खराब होने से कौमें तबाह नहीं होतीं, दिमाग खराब होने से कौमें तबाह होती हैं। दिमाग कौन खराब कर रहा है? हम बेरोजगारी की बात कर दें, तो इन लोगों की, ...(**समय की घंटी**)... सरकार में बैठे लोगों की धार्मिक भावनाएँ तुरंत आहत हो जाती हैं। महोदय, मैं एक मिनट लूँगा, अभी मेरी पार्टी का समय है। इन लोगों की धार्मिक भावनाएँ तुरंत आहत हो जाती हैं, लेकिन देश में, समाज में व्याप्त असमानता और बेरोजगारी को लेकर इनकी भावना कभी भी आहत नहीं होती। इन लोगों के पास केवल धार्मिक भावना ही है, इन लोगों के पास मानवीय भावना नहीं है। मैं तो वित्त मंत्री से इतना कहना चाहूँगा कि देश में आज इतना गुस्सा, घृणा, नफरत, अहंकार है, कुछ नेता भी फैला रहे हैं, कुछ गोदी मीडिया के चैनल्स भी फैला रहे हैं, कुछ व्यक्ति भी और कुछ इंस्टिट्यूशंस भी। अगर आपको जीएसटी लगाना है, तो आप नफरत, घृणा पर 100 परसेंट जीएसटी लगाइए, ताकि हमारे देश में सामाजिक सौहार्द और सद्भाव बना रहे।

महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनावी वर्ष है। जैसा बिहार के बारे में बताया गया है, हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, हम सब युवा हैं, चिराग भाई वहाँ बैठे हैं, वे भी युवा हैं, लेकिन आप केवल लॉलीपॉप मत दिखाइए। महोदय, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी वाला क्या करता है कि सब्जी लेने के बाद थोड़ा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देता है, बिहार के साथ वही हुआ है। सब्जी ले गया गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और इन्होंने बिहार को वह हरे धनिया की कुछ पत्तियाँ दे दीं। वह हरा धनिया का गुच्छा भी नहीं दिया, कुछ पत्तियाँ और एक-दो हरी मिर्च डाल दी, तो लोगों को लगा कि पता नहीं, बिहार को क्या मिला। यह सच्चाई नहीं है। बिहार को कुछ नहीं मिला है।

महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. WILSON): Shrimati P.T. Usha. She is absent. Shri Kapil Sibal.

SHRI KAPIL SIBAL (Uttar Pradesh): Sir, I thank you for giving me this opportunity to place my thoughts on the Budget of 2025-26. When a new Government comes to power, naturally, the people of India expect that Government to give us a vision of what it intends to do in the next five years. This Government already had ten years and the delivery mechanism has been both slow and inconsistent. But, we were hoping that after the eighth Budget of the hon. Finance Minister, we will get some vision as to what the Government intends to do. First of all, before you do that, you have to identify कि हमारे सामने क्या चुनौतियाँ हैं। तभी हम तय कर पाएँगे कि हमें आगे क्या करना है। अब मेरे हिसाब से इस देश में जो सबसे बड़ी चुनौती है - मैं गलत भी हो सकता हूँ - इस देश में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है। जब तक शिक्षित बच्चे मेनस्ट्रीम में नहीं आएँगे और इनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक भारत कभी विकसित नहीं हो सकता। विकसित भारत का मतलब – शिक्षित भारत। मैं आंकड़ों में नहीं

जाऊँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस बजट में उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब आप हिन्दुस्तान की व्यवस्था देखिए कि ज्यादातर बच्चे, युवा देहात में रहते हैं। एजुकेशन की जो भी व्यवस्था है, कुछ अर्बन सेंटर्स में तो यह अच्छी है, परन्तु आम जनता को क्वालिटी एजुकेशन मिलती ही नहीं है। आपको मालूम है कि ASER Report में यह बात आई कि 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं, वे दूसरी क्लास के सबक नहीं पढ़ सकते, मैथ्स नहीं कर सकते। चलिए, आप इस बात को छोड़िए।

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*.)

Sir, the fact of the matter is that we need to have a plan as to how to make our children educated. If you really look back at the history of the world, and especially of the European powers, you will find that when the Industrial Revolution happened around 1750s, two things happened. One was universal education; the second was technology. That is how the empires ruled upon us. When China became the power that it is today, the first thing China did was universal education. Today, we have not even attained the goal of universal education; forget about quality education. So, if you do not have universal education and if you do not have quality education, तो आप बच्चों में skills कहाँ से develop करेंगे? पहली बात तो यह है।

दूसरी बात, 21वीं सदी में जो skills हमें चाहिए, वे 20वीं सदी में नहीं थे। आज के दिन ChatGPT and DeepSeek are the new technological revolutions which are taking place in the world. उसमें हम कहाँ हैं? What plans do we have for the future? We expected the hon. Finance Minister to tell us. What do we intend to do to deal with these challenges? We cannot afford to apply AI to our systems because if we do, we will lose jobs that we already have. अब Chartered accountant बैठकर देखता था कि account books में क्या है। अब तो वह AI से हो जाएगा। हमारे law clerks research करते थे कि ये judgments क्या हैं। अब तो वह AI से हो जाएगा। और जो software technologist थे उनके कई solutions AI से निकल आएँगे and the result will be that we will lose jobs where we have jobs. But, at the same time, we need AI. Otherwise, we cannot be competitive in the world. So, what is the vision of this Government *qua* AI? All that the hon. Finance Minister said was that we are going to set up 100 centres of Artificial Intelligence. But first understand what Artificial Intelligence is and what it can do. In the Economic Survey, the Economic Adviser has said that as far as Artificial Intelligence is concerned, it can only work in certain sectors of the economy; it would not work in rural India. That is his suggestion. There is nothing about it. That is one aspect that I wanted to mention to you. The second is health because the best investment that can produce the maximum results is investment in human capital. I talked about education; now, I want to talk about health.

आपको हेल्थ सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, वह कभी अपने आपको empower कर ही नहीं सकता है। इसमें मैं आपको थोड़े-से आंकड़े बताना चाहता हूँ। The fact of the matter is that 38 per cent of children born in this country are stunted; 21 per cent of children born in this country are wasted and 53 per cent of women in this country are anemic! How will you get children empowered if you do not invest in the health sector? There is a 9 per cent increase in the Budget in the health sector and that also because they want to create 10,000 new medical seats. That is not the solution to India's problem. The two biggest challenges facing this country are education and health. This is just one aspect I want to talk about. The second one is this. हम रोज बात करते हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएगी, जल्द हो जाएगी, 2024 में हो जाएगी। अब तो उन्होंने कहा है कि 2027 तक नहीं होगी। लेकिन 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का मतलब क्या है? यह गुमराह किया जा रहा है। Sir, a US$5 trillion economy is going to happen in this country in any case. I will show the hon. Finance Minister that even if she does nothing, this country will grow at 6 per cent. It will grow at 6 per cent, even if she has done nothing. Do not laugh. *...(Interruptions)...* That is a serious issue. Do not laugh at it. This country has been growing at 6.3 per cent, 6.7 per cent and it will continue to grow. But, what we need is a growth rate of 8 per cent! What we need is double digit growth! What is the vision of this Government to attain double digit growth and attain 8 per cent growth? I will tell you why I am saying this. I may be wrong. I am only here to have discussion. I may be wrong, Sir, but the fact of the matter is, . If we compare our economy with other BRICS economies, Russia's per capita income is US$14,000. China's per capita income is US$13,000. Brazil's per capita income is US$11,000. South Africa's per capita income is US$5,970 and we are at US$2,540. And we will be a US$5 trillion economy! What is the point of these numbers? That is why, I was saying that with the growth of 6 per cent, you will reach there and you will reach there in 2027. I will congratulate the hon. Finance Minister. But, how do you empower the young? How do you increase per capita income in this country to US$14,000, US$13,000, US$10,000? You have no vision for it. That is really the point that needs to be looked at and discussed on the floor of this House.

Let me, Sir, tell you another thing, which is even more important. We have certain external challenges we will have to face. You just saw, Mr. Trump has announced that there is going to be an import tariff on steel imports. Luckily, we do not export too much of steel. But, the fact of the matter is, while the hon. Prime Minister is going to America and will certainly have a dialogue with Mr. Trump, there are some imponderables that may happen in course of time. And, as a country, we have to be prepared for it, assuming that he may impose a 5 per cent or 10 per cent

tariff on software exports. I am just giving an example. What is the consequence of that on our software industry? Phenomenal! We will be non-competitive. How do we deal with that problem? Now, these are the issues that I expected the hon. Finance Minister to deal with in the course of our Budget presentation. But, we are talking about allocations today. What did the Economic Advisor in the Economic Survey say? I will just point that out. He said, 'Roll back regulations.' Do you see a bit of that in this Budget? No roll back of regulation. He said, 'Get out of the way'. But you are coming in the way. You are always in the way. Then he said, 'Change your operating procedures.' What are these operating procedures? In India, the operating procedure—I am not saying this; it is in the Economic Survey—is that the person is guilty till he is proved innocent. That is what the Economic Survey says. I do not say that. He said, 'Change that.' Change that to what,--that the person is innocent till he is proved guilty. Why has the Economic Advisor said this to you? Because he knows that the kind of principles that you are following, our big industry is running away. Our high net-worth individuals are leaving this country, because when you proceed against them, you proceed on the basis that you are guilty till you are proved innocent. That is a very dangerous trend that is happening in this country. Then, Sir, he also said, 'Make our economy competitive and innovative.' Now how do you make your economy competitive? Most of the people in this country are involved in agriculture, and you have a dream of making India a manufacturing economy and you have proclaimed that the manufacturing economy will contribute 25 per cent of the GDP. The fact of the matter is that whereas, it was 16 per cent of the GDP earlier, it has come down to 15 per cent, to 12.9 per cent, my learned friend corrects me. In other words, your manufacturing qua, the GDP has decreased. If you do not become a manufacturing economy, how will you become competitive? And what has the Finance Minister said about that on the Budget? Nothing! How do you become innovative? You only become innovative if you put money into R&D. The money that is put into R&D in US is 650 billion dollars a year. In China, it is 500 billion dollars a year. And what is it in India? It is 50 billion dollars a year. Unless you invest in R&D- Sir, I just want to give you an example. Take the mobile phone as an example. This mobile phone, actually, is a hardware in somebody else's hand, Europeans' hand. The software solutions are produced by us. Now the software is sold to the owners of hardware. So, that software ownership goes to the hardware company and then that company allows you to use the phone and charges you for the software. That is what it is. They give you a license fee that you are using my phone, you pay this much. This is what is happening. Sir, I was the Minister for Telecom. I asked the telecom industry, 'What is it in the telecom sector that you manufacture?' Nothing! They are

service providers. They do not manufacture anything. The routers, everything is manufactured from abroad. How are you going to become competitive? What is the vision of this Government? What is the vision of this Government in the Finance Bill, in this Budget? How will you compete with the rest of the world? This is a very serious issue. Now I will tell you. There is another thing that I want to mention. Then he said that now we have to deal with domestic growth. Do not rely on the growth through your external exports because you need to give more money into the hands of the people of this country. And on that, Sir, I just want to point out very, very interesting data that, in fact, there are about 8.09 crore people in this country who file income tax returns. Of those 8.09 crore people, about 4.9 crore pay zero tax and you are left with 3.19 crore people who actually pay tax. Now with 140 crore people in this country, there are 3.19 crore people who pay tax. ….(*Time-bell rings.*)… Sir, give me a few more minutes. Just 3.19 crore people pay tax.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI KAPIL SIBAL: That is, 2.2 per cent population of this country. You can have two inferences on that. एक तो यह कि चूंकि वे लोग टैक्स नहीं देते, इसलिए उनको पकड़िए। दूसरा, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वे टैक्स दें, तो उनके हाथों में पैसा दीजिए। आपने दोनों ही चीज़ें नहीं की। रियेलिटी यह है that 50 per cent of income groups spend...

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I will take just two minutes.

MR. CHAIRMAN: Please take one minute.

SHRI KAPIL SIBAL: Okay, fine. There is a Report of 2023, Oxfam Report, which says, "Survival of the richest, the India story". What does it say? It says, 'The bottom 50 per cent of income group spends a higher percentage of their income on indirect taxes than the middle 40 per cent and the top 10 per cent combined. The bottom 50 per cent of the population at an all-India level pays six times more on indirect taxation as a percentage of income compared to the top 10 per cent.' And, what you do? What have you done? You have not given any money to the bottom 50 per cent of the people! So, Sir, I will just conclude now by saying only one thing. Don't sell dreams. Give us a dream Budget. Mr. Chidambaram gave it. Give it to us. We want a dream Budget. We want India to move forward. We will all support you if you have a vision

as to when and how India will move forward. And, we all hope that that the dream Budget will come. Thank you, Sir.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I have to make one request only to Kapil Sibalji. But he is a senior Member. We like to hear the senior Members' intervention. They can make huge contribution by their sheer experiences and knowledge. My only request is, you have given a good suggestion, made relevant points, but be present in the House more often so that you can listen to the point of view of the Government and other Members also. It is good for the House. That is all.

MR. CHAIRMAN: Kapil*ji*, please take your seat. I have only allowed hon. Minister to intervene, no one else. Shrimati P.T. Usha; not present. Now, maiden speech by Shri Kunwar Ratanjeet Pratap Narayan Singh.

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, मेरी मेडन स्पीच नहीं है। मैं तो पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन आपने मेडन बोल दिया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति: आज के दिन मैं ज्यादा ही indulgent हूं, वरना कपिल जी ने मुझे काफी monetise किया है। सत्यपाल मलिक जी के साथ सोशल मीडिया में किया है। इनको मुझे royalty देनी चाहिए। मैं हकदार हूं।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: सर, ये महाराज हैं।

श्री सभापति: आप भी तो महाराज हैं। एक महाराज दूसरे महाराज से कह रहा है।

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह: सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं और अपनी पार्टी का आभारी हूं कि मुझे बजट पर बोलने का मौका मिला है। जिस दिन से निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उस दिन से विपक्ष बदहोश है। उनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा ऐतिहासिक और ऐसा dream budget भी कोई वित्त मंत्री पेश कर सकता है। जैसे आपने सदन को बताया था कि उन्होंने लगातार आठवीं बार बजट पेश किया है और एक रिकॉर्ड सेट किया है। उन्होंने न सिर्फ आठवीं बार बजट पेश करके रिकॉर्ड सेट किया है, बल्कि इस बजट को...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): सर, यह गलत है। संसदीय परम्परा है कि यदि कोई मेम्बर अपनी स्पीच समाप्त करता है, तो उसके तुरंद बाद दूसरा मेम्बर जब तक अपनी स्पीच समाप्त नहीं कर लेता, तब तक उस सदस्य को सदन में बैठे रहना होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी, जिनको संसदीय व्यवस्था की लम्बी जानकारी और अनुभव है, उन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि क्या एक सदस्य को अपना भाषण देकर तुरंत सदन से बाहर जाना चाहिए? इसका दूसरा रूप यह है कि क्या पूरे सत्र के दौरान सदन में अपना भाषण देने के लिए ही आना है? यह दूसरा है। इसका एक तीसरा पहलू और है कि संसदीय प्रणाली में, जिसकी व्याख्या बेस्ट पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में की गई है, कॉल एंड शकधर में की गई है और सदन के बाहर अनेक पीठाधीन अधिकारियों द्वारा भी की गई है। यह अति आवश्यक है कि मर्यादित आचरण का आधार दूसरे की बात सुनना और अपने विचार व्यक्त करना है, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था तभी आगे बढ़ सकती है, जब अभिव्यक्ति का अधिकार हो और वह अधिकार कुंठित न हो। जो अधिकार अभिव्यक्ति का इस सदन के सदस्यों को प्राप्त है, जिसके बारे में बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा अधिकार प्राप्त करने के बाद अनंतवाद में होना, दूसरे की बात न सुनना, अपनी बात को कहकर निकल जाना, यह मुद्दा आपने उठाया है। आपने उपयोग किया है कि अपना अभिभाषण दिया and you show back to everyone else. यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस सत्र के दौरान इस पर आपको मेरा निर्णय मिलेगा।

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): महोदय, एक तिवारी जी बोल चुके हैं, तो अब दूसरे तिवारी बोलना चाहते हैं। सर, मेरा भी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री सभापतिः प्रमोद जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए सदा प्रथम हैं, दूसरे नहीं हैं। सिर्फ आपको ही थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आपका ही हूं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर से भी सफर करूं और उधर से भी करूं। कुछ तो राहत मुझे भी मिलनी चाहिए।

श्री प्रमोद तिवारीः जी बिल्कुल। सर, परंपरा की बात चली है और मैं इस बात का समर्थक हूं, जो तिवाड़ी जी ने उठाई। सर, परंपरा यह भी रही है कि जब वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा हो रही हो और वे करें, तो माननीय वित्त मंत्री जी को भी ...(**व्यवधान**)... आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। वहां इस समय अखिलेश जी बोल रहे हैं। वित्त मंत्री जी को यहां से दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री जी लगातार अनुपस्थित हैं। मुझे मालूम नहीं है, शायद इस समय वित्त मंत्रालय का कोई राज्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं है, क्योंकि चौधरी जी एक ही हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह अपमान भी राज्य सभा का न हो, तो अच्छा है। मैं इस पर आपसे आग्रह कर रहा हूं, धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय सदस्यगण, आपने जो बात उठाई है, वह जानकारी के अभाव में उठाई है। अगर आप मुझसे जानकारी ले लेते, तो बहुत अच्छा होता। I would compliment the hon. Finance Minister that she has shown exemplary adherence to the rules. Finding that her commitments are there for parliamentary work, she has sent me a written communication well in advance and she has been scrupulously careful and regardful to the entire institution to depute Sri Harsh Malhotra for the purpose. And, Sri Harsh Malhotra is present here. And, number two, this I decide right now, parliamentary

practise allows it. There is no Government, at any point of time, which has not faced such situations. There are occasions when the hon. Prime Minister is required to be here. The Chair is always apprised of the situation as to who will handle the situations in his absence. And, I can tell you there has been no lapse. Howsoever I may take you as *pratham*, the point you raised is rejected because it did not have adequate foundation.

देखिए, यह तो तरीका है, वरना कपिल जी ने आखिर में जो बात कही, वह बात विस्तार से चिदम्बरम जी कह चुके थे। Chidambaram*ji* concluded his speech -- a very sound speech, every word was careful -- but with that observation, which Kapil*ji* monetized. Am I right? Please continue.

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंहः सभापति महोदय, मैं दोनों तिवारियों के बीच में एक किसान हूं। क्योंकि आप भी एक किसान हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक किसान को मौका देंगे। सभापति महोदय, मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं कह रहा था कि जब से बजट की announcement हुई है, तब से सारा विपक्ष बदहोश है।

[**उपसभाध्यक्ष** (**श्रीमती किरण चौधरी**) *पीठासीन हुईं*]

महोदय, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा बजट भी कभी पेश हो सकता था। हम चार सालों से सुनते आए, और सारा विपक्ष भी कह रहा था कि middle class के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मध्यम वर्ग के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। जब बजट में 12 लाख रुपये इन्कम टैक्स में माफ कर दिए गए, तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। महोदय, ये बस आंकड़े देते थे कि इतने नंबर नहीं देते थे, वह नहीं करते थे आदि-आदि।

महोदय, इनकी वाणी हमेशा निराशाजनक होती है। मोदी जी साफ तौर से कहते हैं कि इस देश के महान बनने में और विकसित होने में अगर कोई रोड़ा है, तो वह इनकी मानसिकता है। महोदय, जो विपक्ष की मानसिकता है, वह इस वजह से है कि इनके सारे भाषण बहुत निराशापूर्ण होते हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य मुझसे पहले बोल रहे थे कि five trillion dollar से क्या होता है, economy से क्या होता है? महोदय, दस सालों में मोदी सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत, जिसने हम पर हुकूमत की, उनसे ज्यादा बड़ी हमारी इकोनॉमी को बना दिया है, पाँचवें नंबर पर पहुँचा दिया, लेकिन इन्हें लगता है कि कुछ नहीं हुआ है। महोदय, हम बहुत जल्द तीसरे नंबर पर भी आने वाले हैं।

महोदय, ये बोल रहे थे कि यह क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये लोग ये आंकड़े दिखाएंगे, वे आंकड़े दिखाएंगे, परंतु इन्हें कभी भी किसी चीज़ पर तारीफ नहीं करनी है। हमारी वित्त मंत्री जी ने जो 12 लाख रुपये माफ किए हैं, क्या यह मध्यम वर्ग के लिए अच्छा था – उस पर इन्होंने कुछ नहीं बताया है, क्या यह एक खराब निर्णय था - इस पर विपक्ष नहीं बोलेगा। महोदय, पूरा भारत कह रहा है कि यह बहुत बेहतर है, यह बहुत अच्छा निर्णय है, परंतु विपक्ष उसके बारे में

आंकड़ों में बता रहा है कि आपने अमीरों का टैक्स काट दिया, उसका टैक्स काट दिया आदि-आदि।

महोदय, एक तरफ जब इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो ये कह रहे हैं कि आप 6 परसेंट पर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष भूल गया है कि अभी हाल ही में कोविड महामारी के कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी किस तरह से पीछे चल रही है। महोदय, अगर विश्व में कोई fastest growing economy है, तो वह हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, लेकिन इनको उसके लिए भी तारीफ करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि आठ होनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपको को साठ सालों तक मौका मिला था, आपको कर लेना चाहिए था, लेकिन उसके बारे में बात नहीं होगी।

महोदय, Infrastructure की बात होगी **...(व्यवधान)**... प्रियंका जी, आप न ही कहें, तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी पार्टी तो जिस मूल रास्ते पर चलती थी, आपने उस पर भी चलना बंद कर दिया है, इसलिए अब उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए।

महोदय, मिडिल क्लास की बात होती है और consumption की बात होती है कि इकोनॉमी इसलिए नहीं बढ़ रही है, क्योंकि consumption नहीं है, consumption नहीं होगा, तो कैसे हमारी employment बढ़ेगी, हमारे MSMEs कैसे बढ़ेंगे? महोदय, consumption के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का टैक्स हटाकर हमने इकोनॉमी के अंदर 1 लाख करोड़ रुपये को inject किया है, लेकिन आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इसलिए इन 1 लाख करोड़ रुपये से क्या होगा? महोदय, कुछ भी कीजिए – इनके कहने पर नहीं – क्योंकि इन्हें कभी उत्साह था ही नहीं, वे बुराई की तरह कहते थे, लेकिन जब वह काम हो जाता है और उम्मीद से ज्यादा हो जाता है, तो इन्हें कुछ न कुछ नुक्स निकालना है। इनके पास इसको सुधारने के लिए कोई सुझाव नहीं है, इनके पास रोजाना गाली देने के लिए कभी शब्द समाप्त ही नहीं होते हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, जहाँ तक इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है, इन्फ्रास्ट्रक्चर में, 2014 में 1 लाख करोड़ रुपये का बजट था, लेकिन अब इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या दस सालों में यह कंजम्पशन बूस्ट नहीं करेगा? मैं इसको समझ ही नहीं पाता हूं।

महोदय, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। यहाँ हमारे माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी बैठे हैं, मैं उन्हें 2014 से लेकर 2024 तक के आंकड़ों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। उन्होंने भी इस बजट के बारे में कुछ आंकड़े बताए थे। महोदय, बैंक के एनपीएज 2014 में कितने थे? महोदय, ये 11 परसेंट थे।

3.00 **P.M.**

आज 2024 में कितने हैं – 0.6 परसेंट हैं। 2009 से 2014 तक कितना वेल्थ क्रिएशन हुआ था – 13 लाख करोड़ का हुआ था और इन दस सालों में कितना क्रिएट हुआ है – 310 लाख करोड़ वेल्थ क्रिएशन हुआ है। फॉरेक्स की बात होती है। फॉरेक्स 2009 से 2014 तक 50 बिलियन डॉलर था और आज की तारीख में 350 बिलियन डॉलर है। 2009 से 2014 तक इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग 1.5

लाख करोड़ थी और आज 2019 से लेकर 2026 तक 55 लाख करोड़ होगा। फिगर्स आपको साफ तौर से बताए गए हैं।

महोदया, अभी हैल्थ की बात हो रही थी। इस सरकार ने पिछले दस सालों में तमाम योजनाएं लागू की हैं, जिससे तमाम लोगों के पैसे बच रहे हैं और सरकार के पैसे बच रहे हैं। उनमें से दो-तीन चीज़ों को ही मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड में जनता के 1.2 लाख करोड़ रुपये बचे हैं। जन औषधि केंद्र में 80 परसेंट का डिस्काउंट मिलने के बाद दवाई खरीद में लोगों के 30,000 करोड़ रुपये बचे हैं। नल से जल योजना में 12 करोड़ से ऊपर घरों तक पानी पहुंचाया गया है, जिससे बीमारियाँ कम हुई हैं। हर व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचा है। ...(**व्यवधान**)... वेस्ट बंगाल में तो दिक्कत है ही, मैं जानता हूँ। घबराइए मत, मैं उस पर भी आऊँगा। वेस्ट बंगाल के बारे में भी आपको विस्तृत से बताऊँगा। उसकी चिंता मत करिए। ...(**व्यवधान**)... जहाँ तक नल से जल योजना की बात है, उसमें लोगों के 40,000 रुपये बच रहे हैं। जिस घर में पीएम सूर्य घर बिजली योजना का लाभ प्राप्त होगा, उसे 25 से 30 हजार रुपया हर साल की बचत होगी। सॉयल हेल्थ कार्ड की बात होती है, तो किसान को उसके माध्यम से 30,000 रुपये बचते हैं। अगर आप इन्फ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें देखें, लोगों को जो डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, उसमें देखा जाए, तो साफ तौर से सरकार के तीन लाख करोड़ रुपये बचकर सीधे गरीबों के खाते में जा रहे हैं।

महोदया, मैं पूर्वांचल से आता हूँ और खेती करता हूँ। किसान की बहुत बातें होती हैं। इस हाउस में अन्नदाता की बात बहुत होती है। मुझे यह पता नहीं है कि कितने लोग खेत पर जाते हैं, कितने लोग किसानों से मिलते हैं। दिल्ली में फार्म हाउस बहुत हैं, तो हो सकता है कि विपक्ष के लोग उनमें जाकर किसानों के बारे में सोचते होंगे, क्योंकि किसानों के बारे में यहाँ विपक्ष जो चर्चा करता है, वह जनता से बिल्कुल परे है। मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। एक हमारे तृणमूल काँग्रेस के सांसद हैं। वे हिंदी पिक्चरों के बारे में पूरी बात बता रहे थे कि मदर इंडिया में किसानों जैसी हालत थी, वैसे ही किसान आज भी है। मैं उन्हें बताना चाहूँगा – ...(**व्यवधान**)... अखिलेश जी, मैं भी चाहता हूँ और आप भी इधर ही आना चाहते हैं। चिंता मत करिए, आप जल्द ही इधर ही मिलेंगे। घबराइए मत। आप बिहार के चुनाव से इधर ही आ जाएंगे। मैं आपसे साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मदर इंडिया की बात बताई। महोदया, यह पिक्चर 1957 में बनी थी। मदर इंडिया के जो दृश्य थे, वे 1960-70 के हिसाब से बिल्कुल सही थे। उस जमाने में किसानों का वही हाल था, जो अब किसानों का हाल है। जब से मोदी जी ने किसानों के लिए तमाम योजनाएं बनाई हैं, तो उसी पिक्चर में एक गाना था, जो आजकल किसान गा रहे हैं – "दुख भरे दिन बीते रे, भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे।" यह गाना हमारे शकील बदायूंनी जी ने लिखा था। हमारे किसान की जिंदगी में सचमुच में दुख के दिन बीते रहे। यहाँ तो डीएपी, पोटाश और यूरिया के बारे में कोई नहीं जानता है। यूरिया का दाम कितना है? पाँच साल में दाम ही नहीं बढ़ा है। दो-चार-पाँच रुपये का अंतर हुआ होगा। उस पर 12 लाख करोड़ सब्सिडी प्रदेश देता है। आज पोटेश हो, आज यूरिया हो, आज डीएपी हो, इन पर सब्सिडी देकर किसानों को सही दाम पर सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर मिल रहा है। आज यूरिया की एक नई फैक्टरी लगने जा रही है, जबकि यहाँ हम पचासों साल से सिर्फ इम्पोर्ट करते आए हैं। आज यूरिया में इम्पोर्ट खत्म करने के लिए एक यूरिया की फैक्ट्री बन रही है।

किसानों के लिए क्या-क्या किया गया है, यह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 2013-14 में किसानों के लिए बजट में 21,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब 2025-26 में किसानों के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से 8 करोड़ किसानों का फायदा हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। एक लाख करोड़ रुपये इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से किसानों की आमदनी बढ़ी है। किसानों के लिए सस्ती खाद के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। किसान सम्मान निधि से 3.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में गए हैं। किसानों की बात टीएमसी करती है। अरे, वैस्ट बंगाल में किसानों के क्या हाल हैं! आलू के कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली है, क्या इसके बारे में टीएमसी कोई रिपोर्ट देगी? ...(**व्यवधान**)... जब वहां अंग्रेज थे और वहां जब कोई किसान मरता था, तो वे बोलते थे कि यह malnutrition से मर गया है, यह किसानी की वजह से नहीं मरा है। ...(**व्यवधान**)... टीएमसी क्या कहती है - जब कोई किसान आत्महत्या करता है – अरे, ये मैरिज डिस्प्यूट की वजह से मर गए होंगे। ...(**व्यवधान**)... डिप्रेशन की वजह से मर गए होंगे ...(**व्यवधान**)... यह बड़े दुख की बात है और यह विपक्ष किसानों की बात कर रहा है! ...(**व्यवधान**)...

यहां स्वास्थ्य की भी तमाम बातें हुईं। अभी कहा जा रहा था कि डॉक्टर्स बढ़ाने से क्या होता है? हमारे पहले स्पीकर ने कहा कि डॉक्टर्स बढ़ाने के लिए पैसा बढ़ा दिया गया है। मैं आपसे साफ तौर पर पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आबादी में अगर डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे, तो कौन सा काम हो पाएगा? 2014 में हमारे पास एमबीबीएस की करीब 52,000 सीट्स थीं। अब ये 10 सालों में डबल होकर 1,12,000 से ज्यादा सीट्स हो गई हैं। पहले हमारे पास 31,000 पीजी सीट्स थीं और अब 72,000 हो गई हैं। डॉक्टर्स होंगे, तो उससे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार आएगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए - अगर किसी गरीब को कैंसर हो जाता है, तो उसका पूरा खानदान, तीन पुश्तों तक कर्ज में डूब जाता है। मैं प्रधान मंत्री जी को और खास तौर से निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कैंसर और गंभीर बीमारियों के इलाज को सुलभ बनाने के लिए बजट में अनाउंस किया। उन्होंने अनाउंस किया कि सरकार सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना करेगी। 2025-26 में 200 नए कैंसर सेंटर्स शुरू किए जाएंगे, जिससे मरीजों का बेहतर और समय पर इलाज किया जाए सके। 36 ऐसी जीवन रक्षक दवाए हैं, जिनको बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया है। क्या यह लोगों को फायदा नहीं करेगा?

अब मैं आयुष्मान कार्ड की बात करता हूं। तमाम ऐसे राज्य भी थे, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड को लागू ही नहीं किया और उसका एक उदाहरण दिल्ली है। जितनी ये केंद्र की योजनाएं थीं, जिनको दिल्ली ने लागू नहीं किया, उसकी वजह से ही आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। 2013 और 2014 में आयुष्मान कार्ड पर 33,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। इस साल इसे तीन गुना बढ़ाकर 96,000 करोड़ किया गया है। क्या गरीबों की मदद करना कोई पाप है! मुझे लगता है कि ये रोज गरीब-गरीब की बात करते हैं, ये गरीबी नहीं हटाना चाहते हैं, इन्होंने हमेशा गरीब को हटाने की बात की है। मुझे इसका दुख है।

मैं अंत में कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों की गणना नहीं है, बल्कि नए भारत की कहानी है।

एक ऐसा भारत, जो आत्मनिर्भर, नवाचार का अग्रणी और हर नागरिक के लिए अवसर भरा है।

अंत में, बैठते-बैठते मैं विपक्ष के लिए एक चीज कहना चाहूँगा:

विपक्ष से न उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ,
ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं।
अगर इस दौर में इंडी एलायंस से वफा ढूँढ़ रहे हो,
तो बड़े नादान हो तुम,
क्योंकि तुम जहर की शीशी में दवा ढूँढ़ रहे हो।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): The next speaker is Ms. Dola Sen. She will speak in Bengali.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Thank you, Vice-Chairman, Madam, for allowing me to speak and many thanks to our Party, All India Trinamool Congress, and our leader, hon. Mamata Banerjee, for giving me a chance to speak on Budget Discussion. I will try to deliver my speech in Bangla, my mother tongue. [&] "Much ado is being made about this Budget especially with respect to proposed income tax relief to the middle class for an income up to Rs. 12 lakhs. According to the 2023-2024 Periodic Labour Force Survey (PLFS), the total work force in India is about 60 crores. While, according to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) statistics, only 6.45 crore people in the country have an income over Rs. 5 lakh per year. Therefore, only 10.75% of the total work force has an income over Rs. 5 lakh. Accordingly, those who are rejoicing, do they really count as "middle-class people"? In terms of income, they count as the top 10% of the families. इसका मतलब यह है कि मिडिल क्लास हमारी टोटल पॉपुलेशन का 10 परसेंट है। बहुत अच्छा, इस 10 परसेंट मिडिल क्लास को टैक्स के इस concession को लेकर हमें कोई problem नहीं है, लेकिन बाकी 90 परसेंट का क्या होगा? जो लोग एक महीने में एक लाख नहीं, बल्कि 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार का रोजगार करते हैं, उन लोगों के बारे में बजट में क्या है? कुछ नहीं है। Rather, a reduction in indirect taxes in products like petroleum would have ensured that the benefits reached all the people of the country. But, unfortunately, what is the reality? In November, 2024, the price of international crude oil was 73 dollars per barrel. At the same time, the petrol price at the domestic market was Rs.95 per liter. Whereas, in 2014, the price of international crude oil was 78 dollars per barrel and, at the same time, the petrol price at the domestic market was Rs.64 per liter only. Which means

[&] English translation of the original speech delivered in Bengali.

that, when the prices of the crude oil have witnessed a steady decline in the international market from 2014 to 2024-25, the situation in our country has been the complete opposite with petrol prices rising day by day. Moreover, even diesel and cooking gases' prices have been increased. Accordingly, there is no question of reduction in the prices of commodities. This Budget is completely silent on the issue of inflation. Naturally, question would arise "so much price hike-what would we eat? From January to October, 2024, the food price inflation has averaged at 8 per cent and the household savings are also at 50-year low. Besides, in financial year 2024-25 the expenditure of the Central Government vis-à-vis devolution of taxes to the States has reduced by an amount of Rs. 1.13 lakh crore. Further, expenditure has been reduced for sectors like agriculture, rural development, MGNREGA, food subsidy, education and health to the tune of Rs. 1.06 crore of the Union Government.

During the last 11 years, unemployment has reached a record high rather highest in the last 48 years." Specifically, unemployment was to the tune of 37 million people between October to December, 2024; 8 out of 10 unemployed are youth. The Budget has failed to address the issue of this severe unemployment.

While there has been a deluge of promises for the State of Bihar in this budget, it has remained silent in so far as the State of Bengal is concerned. As our respected Tiruchi Siva*ji* told yesterday also regarding complete deprivation for Tamil Nadu. बिहार के development के लिए हमें कोई problem नहीं है, हम बहुत खुश हैं। May Bihar prosper. However, we know that the Budget for the year 2026 would have a lot of promises for the State of West Bengal. While election is set to take place in Bihar this year, it is slated for next year as for Bengal is concerned. Therefore, this is not an economic budget, rather a political one. It is not, at all, economic Budget; it is a political Budget, exclusively political. This Budget is devoid of any steps as to the alleviation of unemployment, issues concerning the MGNREGA.

The present Union Government wants to deprive the Government of West Bengal in all aspects. Why? अबकी बार 200 पार, बंगाल में क्यों बार-बार हार रहे हैं? इसीलिए इसी गुस्से में, बंगाल के बारे में सदन में भी असत्य भाषण होता है। It is so unfortunate and condemnable. In a completely illegal manner, the workers of Bengal have been denied of their wages what they have earned for 2 years vis-à-vis 100 days' work for the next 3-4 years. Even the allocation towards AWAAS Yojana has been freezed. The total due of the State of Bengal has reached about Rs. 2 lakh crore, which the State rightfully owns. Even the decision regarding change in the name of the State from 'West Bengal' to 'Bangla' has been kept in abeyance for the last couple of years. From closing of the traditional PSUs, shrinking and squeezing them, shifting them from Bengal to other States to depriving labourers and workers of the benefit of the

Labour law, there is destruction all around. Contractual workers are being harmed through the new recruitment portal which is outside the ambit of the law. Not only Bengal even the other opposition ruled States are also being made to suffer.

The Raw Material Department of the Steel Authority of India Limited (SAIL) has been completely shifted from Kolkata, so has the head office of the Ordinance Factory Board. Silently, the head office of the Coal India Limited has been shifted from the city. JPC's office has been shifted from the South Kolkata only on a day's notice. Due to merger of banks, Kolkata no longer remains as the head quarter of the United Bank of India (UBI).

Due to its electoral majority, the Treasury Bench considers the entire country as its territory. Accordingly, it has undertaken disinvestment worth lakhs of crores, corporatization, virtual privatization of profitable PSUs. From Rail to BHEL, SAIL to BSNL all are in line. Separate budget for the Railways has been dispensed with. Chittaranjan Locomotive Works, Liluah-Kancharapara workshops are slated to be privatized. Scores of hawkers have been uprooted. The only Government operated metro i.e. the Kolkata metro which is under the Railways-the lifeline of the country, is also about to get privatized.

Talking about Aviation, while hon. Ms. Mamata Banerjee has been trying for introduction of direct air routes between Kolkata – London and Kolkata – New York, the Alliance Air has kept only one ATR operational from the DumDum airport rendering it virtually devoid of any Government airline service.

In order to give benefits to favourable and close private concerns, BSNL has been virtually rendered finished. Having gotten access to the towers of BSNL for free, the private operators are providing 6G, 7G services, while the BSNL continues to provide only 3G and 4G services.

SAIL is also in danger. Alloy Steel is about to be decentralized. RINL-Vizag has already been privatized.

Kolkata and Haldia ports are about to be shut. Dredging has literally come to a halt. The Port hospital is closed. All the berths and jetties are being privatized. Contractual workers are being employed in place of permanent ones.

The sick IDBI is being saved at the cost of LIC. Now, even the capital of LIC is being traded upon in the Share Market. Further, the GIC is being led to ruin in order to make the PM Jan Dhan Yojana a success. While 100% FDI has been allowed in the insurance sector, despite assurances, the GST on insurances continues to be charged at a rate of 18%.

By virtue of the new recruitment portal (GeM portal), which stands in complete disregard of the Labour laws, in IICB, NITTR, in the four ordinance factories (arms

and ammunition factories), BSNL, Metro Rail, Banks, etc. change of contractors has rendered all the old contractual workers jobless. They are also being denied PF, ESI, gratuity, bonus and leave. There is no labour law; no law of the land.

All the eminent and traditional educational institutions of Bengal like IIT, ISI, Saha Institute, Bose Institute, Cultivation of Science, etc. are being trampled upon.

Earlier PSUs like Jessop, Dunlop were given at the hands of private entities like Chabarias and Ruias to manage very casually. Now, when the Bengal Government is trying to revive them through acquisition and rehabilitation scheme, the Central Government is not even giving the requisite permission for the last nine years.

Having been elected as the Chief Minister in 2011, Ms. Mamata Banerjee revived 26 Jute Mills and 46 tea gardens, notified minimum wages, introduced social schemes for the unorganized workers in the first economic year itself in 2011-12. However, despite promises, the Prime Minister could not make the Union Government tea gardens of Duncan operational in the last 11 years.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Please wrap up.

MS. DOLA SEN: While, in financial year 2023-2024, 272 Central Government organizations made a profit of about Rs. 3 lakh crore, but simultaneously they also withdrew about Rs. 6 lakh crore from the Reserve Bank of India. This has had a detrimental effect on the overall economic situation of the country. Besides, constitutional organizations like the Election Commission, CBI, ED, etc. are being misused for political purposes. We oppose the arbitrariness and undemocratic attitude in the thinking and working of the Central Government and playing an active role in saving Bengal, the country as well as profitable traditional organizations and the common people of India as a whole. People के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। We, the people of India, यह anti-people बजट के लिए, बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट को जरूर सबक सिखाएँगे, क्योंकि यह विकसित भारत नहीं है, 'सबका साथ, सबका विकास' नहीं है, अच्छे दिन नहीं है, जुमला है, आईवाश है, भाषणबाजी है।

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Next speaker is Shrimati Jaya Amitabh Bachchan.

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN (Uttar Pradesh): Thank you, Madam. मैडम, मैं सबसे पहले farming raja को कुछ कहना चाहती हूँ। यह आपका मैडन स्पीच नहीं है, आप तो ऐसे भी स्पीच देते ही रहते हैं। दूसरी बात, इनके पूरे भाषण में अपोजिशन का टैग था। जब ये

अपोजिशन में थे, तब सरकार बहुत खराब थी और अब ये गवर्नमेंट में आ गए, तो सरकार बहुत अच्छी हो गई। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी): कृपया आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह: मैडम, मेरा नाम लिया गया है, इसलिए मुझे मौका दिया जाए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SAKET GOKHALE: Madam, the hon. Member has not taken his name.

सुश्री सुष्मिता देव: इन्होंने नाम नहीं लिया है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी): कृपया आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह: मैडम, मैं कहना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)... मैं इनको इसलिए जवाब देना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी): कृपया आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... इनको बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... नाम लिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह: मैडम, जब मैं उस तरफ था, तब जो उनके बगल में बैठते थे, उनको रोज गाली देती थीं। ...(**व्यवधान**)... आज उन्हीं से गले मिल रही हैं। ...(**व्यवधान**)... मुझे क्या बता रही हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Please sit down. *...(Interruptions)...*

श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह: मैडम, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़ा, जो बढ़िया हुआ है, जो देश को आगे ले जा रहा है, मैं देश के साथ रहना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)... वे निराशवादी लोग, जो देश के विकास में रोड़ा बन रहे हैं, उनके साथ कोई भी नहीं रहना चाहेगा। ...(**व्यवधान**)... जो भी देश का भलाई चाहता है, मैं चाहूँगा कि वे इधर आएँ। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Please sit down, Mr. R.P.N. Singh.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Madam, this House has to run on rules. ...*(Interruptions)*...

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Let the hon. Member speak. ...*(Interruptions)*... Let the hon. Member speak. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Madam, why did you allow him to speak in between? ...*(Interruptions)*...

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): It is the Chair's discretion. I allowed him. Now, let Mrs. Jaya speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Madam, it is not fair. ...*(Interruptions)*...

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Mr. Siva, please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Madam, I did not yield. ...*(Interruptions)*... I did not yield, and, therefore, whatever the gentleman has said should be deleted. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Absolutely, it should be deleted from the records. ...*(Interruptions)*...

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Jaya ji, कृपया आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Madam, there was no point of order. She did not take his name. She did not yield. ...*(Interruptions)*... This House has to run on rules.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Jaya ji, please speak. ...*(Interruptions)*... Otherwise, I will have to allow somebody else to speak.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: I am sorry. You should not have ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी): कृपया आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... प्रियंका जी, कृपया आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... Jaya ji, please speak. *...(Interruptions)...* Hon. Members, please allow the lady Member to speak. *...(Interruptions)...* The Chair has the discretion. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Madam, she had not yielded. She had not taken the name. *...(Interruptions)...*

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Okay. I allowed him. *...(Interruptions)...* I allowed him to speak. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: But why? *...(Interruptions)...*

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): The Chair can do so. *...(Interruptions)...* The Chair has the discretion. *...(Interruptions)...* Jaya ji, will you speak or should I call the next speaker? *...(Interruptions)...* Please allow Jaya ji to speak. *...(Interruptions)...* Will you please allow your Member to speak? *...(Interruptions)...* Please allow Jaya ji to speak. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: You have allowed her to speak. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: I did not yield. Therefore, I request the Chair to delete everything that the gentleman stood and said. ..(*Interruptions*)..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी): शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप शांत हो जाइए। ...(**व्यवधान**)... मैडम, आप भी शांत हो जाइए, आप इनको बोलने नहीं दे रही हैं। ...(**व्यवधान**)... अगर आप शांत नहीं होंगी, तो ये बोलेंगी कैसे? ...(**व्यवधान**)... आप शांत हो जाइए। ...(**व्यवधान**)... शोर करने से कोई फायदा नहीं है, आप शांत हो जाइए। ...(**व्यवधान**)...आप भी शांत होइए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, आप शांत हो जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... अगर shouting match करना है, तो क्या फायदा? ...(**व्यवधान**)... जया जी, आप बोलिए, आपका टाइम जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... जया जी, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आप लोग ऑनरेबल मेम्बर को बोलने दीजिए, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... जया जी, आप बोलिए।

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Madam, I did not yield. Therefore, I request you to delete everything that the gentleman stood and said. ..(*Interruptions*).. Now, can we carry on?

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Yes, please.

श्रीमती जया अमिताभ बच्चन: मैडम, संजय यादव जी ने कहा कि सब्जी वाला सब्जी खरीदने के बाद मुफ्त में धनिया पत्ती और मिर्ची दे देता है। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? आप गृहस्थी तो नहीं चलाते हैं! आप गृहिणी से पूछिए, अदरक, मिर्च, धनिया जैसी चीजें, जो पहले फ्री में मिलती थीं, ...(**व्यवधान**)... संजय जी, सबके लिए ...(**व्यवधान**)...

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Please allow her to speak. इनको बोलने दीजिए। Let her speak.

एक माननीय सदस्य: धनिये से भी परेशानी है!

श्रीमती जया अमिताभ बच्चन: मिर्ची से ज्यादा परेशानी है। ...(**व्यवधान**)... अब सबके लिए पैसा देना पड़ता है। आज मैं यह सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इस हाउस में जितनी महिलाएं हैं, जो घर चलाती हैं, उनकी तरफ से बोल रही हूँ। ...(**व्यवधान**)...

मैडम, अभी यह होता है कि जो वक्ता आखिर में बोलते हैं, उनके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। मुझे फाइनेंस समझ में नहीं आता है। मैं महंगी चीज समझ सकती हूँ, सस्ती चीज समझ सकती हूँ, मगर कहां बढ़ोतरी हुई और कहां कम हुआ, यह मुझे समझ में नहीं आता। मैं सब्जी वगैरह की बात कर सकती हूँ। मेरी सिर्फ एक विनती है कि आपने बजट में एक इंडस्ट्री को पूरी तरह से इग्नोर किया। पहले भी सरकारें करती आ रही थीं, आज भी यह बहुत ज्यादा है। जब उनकी दरकार होती है, जरूरत होती है, आप उन्हें बुला लेते हैं, फोटो खींचवा लेते हैं, publicise कर देते हैं। आपने film industry, entertainment industry के बारे में क्या सोचा है? न उनका entertainment tax - जीएसटी तो छोड़ दीजिए, हालत इतनी खराब है कि सारी single screens बंद हो गई हैं। छोटी-छोटी स्क्रीन्स हैं, वहां भी लोग पिक्चर देखने नहीं जाते हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। क्या आप इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं? इससे बड़ा गलत काम आप नहीं कर सकेंगे। This is the only industry that connects the entire world to India. ..(*Interruptions*)..

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): The Minister has already clarified it. It is covered under the Ministry of Culture. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Sorry, Madam, I did not hear what he said. ...(*Interruptions*)...

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): I have repeated it.

श्रीमती जया अमिताभ बच्चन: मैंने तो रिक्वेस्ट की है, मैं कोई डिबेट नहीं कर रही हूं। मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, ऑडियो-विज़ुअल मीडियम की तरफ से रिक्वेस्ट कर रही हूं। इनके ऊपर इतनी मार मत मारिये कि आप अपने अंग के एक पार्ट को बिल्कुल खत्म कर दें। Please do not do it. There is a problem with literature. There is a problem with art. अभी आप ऑडियो-विज़ुअल मीडियम को भी खत्म कर दीजिए। This is my request to the Finance Minister. Please consider it very, very seriously. It is a very important matter. It is a very difficult industry. यहां के जो वर्कर्स हैं...एक दिन मिनिस्टर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ऑर्गनाइज़ करना चाहता हूं। यह भाषा मैं समझ सकती हूं। उन्होंने supportive बात कही। मैं यह कहना चाहती हूं कि please think about it. We are one of the highest tax-paying industries in the country. ...(*Interruptions*)... No? Then prove that we are not. ...(*Time-bell rings.*)... Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. आप लोग करते हैं। ...(*Interruptions*)... I am sorry for losing my cool.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Hon. Member, please use parliamentary language.

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: But you know, this kind of...(*Interruptions*)... I don't want to accept.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Remove the word [£] ...(*Interruptions*)... This is unparliamentary. ...(*Interruptions*)... This is not acceptable.

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Madam, I do not want to say anything further. यहां सब लोग फिल्मों के गाने, फिल्मों में लिखी गई शेर-ओ-शायरी और डायलॉग मारते हैं, मगर इस इंडस्ट्री की तरफ से – इस इंडस्ट्री में बहुत से गरीब लोग भी हैं, जो daily wage workers हैं, technicians हैं ...(*Time-bell rings.*)... Because of no reduction in entertainment tax, it is very, very difficult. Their survival is actually at a very, very difficult stage. I request the Finance Minister to consider it and please bring in something to help this industry survive. Thank you very much, Madam.

[£] *Exupnged as ordered by the Chair.*

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Thank you, Jayaji. Shri Balyogi Umeshnath. This is his maiden speech. He is not present. Shri K.R. Suresh Reddy.

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Thank you, Madam, for giving me the floor. I appreciate the hon. Finance Minister for opening her speech with a profound statement of a famous Telugu poet, Shri Gurajada Appa Rao *garu*. She quoted him saying, [&] 'It means, "A country is not just merely soil, a country is its people." I hope what she quoted will translate into action. We have seen a few initiatives, which I presume took inspiration from the great Telugu poet. She spoke about *Viksit Bharat*. I don't know whether it is out of choice or compulsion. But look at the statistics. Today, in our country, 50,000 TMC of water is not utilised. Out of the 432 GW of power, 200 GW, which is almost 35-40 per cent, is not utilised. This great country is blessed with one of the most arable lands in the world. The entire landmass of India constitutes almost 83 crore acres. This is why probably Appa Rao *garu* said, "A country is not just merely soil, a country is its people." Having 83 crore acres of landmass with majority arable, today the Minister and the Government come and say that they are giving subsidised ration to 80 crore people. And if the new Census comes out, probably another 13 crore or 14 crore would be added. So, closing on to almost 100 crore people getting free ration is not something what we can proudly tell our people in the 75th year of our Republic. It needs serious rethinking because when we have resources, when we have talent and when we have land mass, most of which is unutilized, definitely, the planners have to think of it. When she spoke about Viksit Bharat and also when she said that she is going to make agriculture as the first engine, it was quite inspiring and reassuring for people like us who come from rural India where 60 per cent of India's population still thrive on agriculture. So, a country is not just merely soil, a country is its people. When 60 per cent of people take agriculture as a profession and when you are going to fix your focus of Viksit Bharat on agriculture as the first engine and move in that direction, it will not only be a Viksit Bharat, but I am sure it can be a *Samaan* Bharat also. You will be able to bridge the inequality by focusing on and making agriculture a little more profitable and more workable.

Madam, I appreciate the Government for the middle class relief they have given. I will not dwell too much into the figures, but it remains a fact that when we

[&] English translation of the original speech delivered in Telugu.

look at the background of the middle class, which is existing today, the majority of them, if not they, at least their fathers or forefathers, came from the rural background mostly with agriculture as a base. So, if you want to expedite the percentage of middle class, the more you focus and make people developed in the rural areas, the country's middle class will continue to grow. I hope this is the direction about which the hon. Finance Minister thought about by giving agriculture the first priority. I hope and pray that they be successful in this.

Some initiatives in this are welcome. You have identified 100 low productivity districts, which is very good. Because agriculture is weak there, you want to strengthen irrigation, seeds and credit. So, these definitely will give a boost in those 100 districts. Then, you also spoke about Kisan Credit Card under which credit has increased from Rs. 3 lakh to Rs. 5 lakh. That is welcoming. It is reassuring the farmers. Then, you also spoke of how the environment is impacting the farmers, the farm produce and the seed. Having said that, what we get to see is that the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, insurance for farmers, is the lowest in seven years! There is a 23 per cent reduction compared to your RE of 2024-25. On one hand, we are agreeing to the fact that climate change impacted and affected the farmers; and, on the other hand, we are trying to bring down Fasal Bima! If you really see, there is a decline in insurance claims for farmers. There has been almost a sizable reduction in the claims. So, the point here is that the Government needs to look at the mechanism of disposal which also has to be re-examined. The farmer on the ground is vulnerable to many challenges, and claiming his insurance also is a big challenge, where, in my opinion, the Government should step in and do the necessary intervention in this.

Madam, when Bihar's Makhana Board was announced, there was a lot of jubilation. It is good. I mean you identify State-wise products which need specific intervention and help through the Boards. It is very welcoming. Now, I come from a turmeric-growing region. As Jayaji knows, turmeric is a very good home produce for any ailments, for any food-making, etc. Madam, I am talking about turmeric. Turmeric is very essential. करीबन दस साल से जहां भी किसानों की हल्दी को लेकर डिमांड आती रही है, Finally, after a lot of pressure, the pressure was to the extent that 75 farmers in 2019 went to Varanasi and filed their nomination against the hon. Prime Minister. It was not to challenge the hon. Prime Minister. It is only to bring to the notice of the country the need for a better remunerative price and betterment of the turmeric farmers. हल्दी के किसान वहाँ तक गए। खैर, बड़ी मेहनत के बाद प्रधान मंत्री जी द्वारा आज हल्दी के बोर्ड की announcement हुई। So, there has been a lot of jubilation on that कि प्रधान मंत्री जी की announcement हुई, और आज, जब हम बजट में देखते हैं, तो उसके लिए एक पैसा भी नहीं है। Not a single *paise* has been given after the announcement

made by the hon. Prime Minister. आपने वहाँ चेयरमैन को appoint किया है। चेयरमैन साहब, हमारे मित्र श्री गंगा रेड्डी जी, जो हल्दी बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका सम्मान हो रहा है, वे हर जगह फिर रहे हैं, वे उम्मीद में हैं, लेकिन उनके पास न तो बैठने के लिए कार्यालय है और न ही आदेश देने के लिए कोई पैसा है। तेलंगाना में एक कहावत है, *'बाहर से शेरवानी और अंदर से परेशानी।'* बस वे इसी तरह से फिर रहे हैं। I ask the Government to kindly look at it. And, as my friend Sanjay*ji* from RJD, rightly pointed out about Makhana Board, let there not be an overlap. Now, there is a Turmeric Research Centre which is running and now you bring in a board! One of the obligations of the board is to do research when there is already a research institute! It is same thing with Makhana Board. There is Makhana Research Centre and now we constitute a board! To ensure that there is no overlap and to give adequate funds, I think, the Commerce Ministry and the Agriculture Ministry need to really work in tandem and to ensure hon. Prime Minister's promise. Our Commerce Minister, Piyush *bhai,* did a very high-tech inauguration from Delhi. बहुत खुशी हुई, हमारे जिले में ही नहीं, बल्कि सारे देश में, जहाँ भी हल्दी होती है, I can say, at the most, if money is not given, through you, I request the hon. Members कि हल्दी के किसान को आपके एम.पी. डेवलपमेंट फंड से, आपके फंड से कम से कम, कुछ न कुछ फंड देकर हल्दी को जिंदा रखिए। Keep the turmeric alive as it is a very, very important crop. Otherwise, in years to come, it may, probably, disappear. One of the biggest challenges we are facing in the country is a decline in the arable land. महोदय, इसके लिए कहूं, तो एग्रीकल्चर, पहले जिस जमीन पर किया करते थे, अब वह जमीन कुछ कम होती जा रही है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि हिंदुस्तान में हमने काफी बड़े-बड़े डैम्स बनाए हैं, हम सालों से डैम्स बनाते आए हैं। There are almost 3700 big dams for major, medium and small irrigation. But, over a period of time, वक्त के हिसाब से, उसकी maintenance न होने से 25 per cent of the capacity has come down. आप जानती हैं कि आज एक major dam बनाने में कितनी दिक्कत होती है। पहले funding की प्रॉब्लम, फिर relief, rehabilitation and re-settlement is the biggest challenge today. अगर आप एक छोटा-सा कारखाना भी बनाना चाहते हैं, तो जमीन नहीं ले सकते हैं। ये जो ऐसे बड़े-बड़े डैम्स बने हुए हैं, उनकी storage, silt की वजह से, sedimentation से कम होता जा रहा है। I request the Government of India to take it up on a mission mode. क्योंकि यह जैसे-जैसे कम होता रहेगा, वैसे-वैसे आगे आने वाले दिनों में आपको और तकलीफ होगी और de-siltation is only increasing--I mean, bringing back the storage capacity--and desilted material can be used by the farmers. Once you test it through labs, if everything is okay, हमारे पास काफी डिमांड है। हर गाँव में तालाब से मिट्टी ले जाकर किसान अपने खेत में डालता है, फिर ये तो बड़े-बड़े डैम्स हैं! इनमें इतनी मिट्टी है, इतना मैन्योर है और आप organic farming के लिए इतनी तेजी से, इतने जोर से propagate कर रहे हैं, तो जब आप organic farming के लिए propagate कर रहे हैं और यहाँ पर tonnes and tonnes, लाखों, करोड़ों की organic manure पड़ी हुई है, Just lift it and give it to farmer. वह ले जाता है और इससे circular economy में भी लाभ मिलने का मौका

है। This is a very good suggestion. I think, the Government of India, in consultation with State Governments, should take it up. The Government of India has taken over dams. आप 2021 में बिल लेकर आए हैं, Dam Safety के नाम पर you brought all the major dams under your control. When you have taken them in the name of dam safety, desiltation also may not be a security, but definitely concerns the safety of the dam where the responsibility, in my opinion, would lie on the Government of India. I request the Government to look into this matter. And, then, we are speaking of the proud Indian diaspora overseas.

काफी लोग कामयाब भी हुए हैं। जो गरीब किसान हैं, यहाँ उसकी खेती में भी सूखा पड़ा हुआ है, तो वह बाहर जा रहा है। वह Gulf जा रहा है, कुछ लोग Singapore, Malaysia जा रहे हैं, but mostly in the Gulf. उनका खून-पसीना एक होकर जिंदगी वहीं गुजर रही है। उसकी कोई family bonding भी नहीं है। उसकी जिंदगी कर्जा चुकाते-चुकाते गुजर गई है। Government of India ने एक स्कीम निकाली है - प्रवासी भारतीय बीमा योजना, जिसमें in case of accidental death दस लाख रुपये दे रहे हैं, जिसके लिए वह दो साल में Rs.380 premium pay करता है। मेरी सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि accidental death ही नहीं, बल्कि जो भी गरीब इन Middle Eastern countries में या किसी भी देश में हैं, आप उन्हें accidental death के साथ-साथ natural death कवर भी दीजिए, क्योंकि वह वहाँ पर मेहनत करते-करते सूख कर मर रहा है। अगर वह आदमी, वह गरीब वहाँ गुजर गया, तो उनकी relief के लिए कुछ होना चाहिए। मेरी सरकार से गुजारिश है कि you treat it not only as an accidental death, but even this also. इसे लेकर काफी तकलीफ होती है। मेरी request है कि आप External Affairs Ministry से Kuwait के लिए एक Consulate खुलवाइए और South India के लिए Saudi Arabia की एक Consulate हैदराबाद में खुलवाइए। वहाँ पर लाखों की संख्या में लेबर है। उन्हें काफी लाभ मिल सकता है। That will be a big advantage for them. Of course, dams के बारे में तो बताया है। But I do not want to go into the details because of paucity of time.

And the biggest thing is that we come from South India. हमारे लिए south-north में कोई अंतर नहीं है, मगर तकलीफ है। तकलीफ इस बात की है कि we contribute to the Central Government and what is that which we are getting? Now, यह debate सिर्फ intellectual economists के बीच ही नहीं, बल्कि यह बात बिल्कुल जमीनी लेवल पर चली गई है। गाँव का आदमी भी बात कर रहा है कि हम इतने पैसे देते हैं, तो केंद्र से क्या आ रहा है। कर्णाटक आपके लिए एक रुपया देता है, तो उनके लिए 15 पैसे वापस आते हैं। शिवा जी यहाँ पर हैं। तमिलनाडु से एक रुपया भेजते हैं, तो उनके पास only 29 पैसे वापस आते हैं। मैडम, मैं तेलंगाना से आता हूँ। वह तो नई स्टेट है। Under KCR*ji*'s leadership, we have increased everything and today, we give you one rupee and we get only 43 paise. आंध्र प्रदेश है, उसके पास 49 पैसे आते हैं। केरल के पास 57 पैसे आते हैं। मैं कोई North-South की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर take for example, Uttar Pradesh and Bihar. बिहार से एक रुपया भेजते हैं, तो सात रुपये उनके पास जाते हैं। अब रह गया उत्तर प्रदेश - वे एक रुपया भेजते हैं, तो 2 रुपये, 73 पैसे उनके पास जाते हैं। अब आप कहेंगे कि यह तो Finance Commission का formula है, मगर

Finance Commission को formula कौन देता है? Finance Commision को आपकी Cabinet formula देती है। ...(*Time-bell rings.*)... मेरी request यह है कि before the Cabinet sets any suggestion to the Finance Commission, let there be an all-party meet. Take the opinion of the House, take the opinion of the floor leaders, take the opinion of the opposition leaders and look into the devolution. जब विकसित भारत की बात करते हैं, समान भारत की बात करते हैं, तो definitely North-South में भी यही रहना चाहिए। आप cess लेते हैं, जो devolution में नहीं आता है, तो जो progressive States हैं, इसे आप उन्हें दीजिए। That will be helpful.

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Thank you. Please conclude.

SHRI K.R. SURESH REDDY: I thank you for the time. Jai Hind!

THE VICE- CHAIRPERSON (SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY): Now Shri Arun Singh.

श्री अरुण सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, देश की वित्त मंत्री, माननीय निर्मला सीतारमण जी ने माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्रीय बजट रखा है, मैं उसके संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैडम, यह बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा-आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। गरीब कल्याण को समर्पित है, क्योंकि गरीबों को अनेक योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल रहा है और किसान की आमदनी भी बढ़ाने वाला है। इसमें युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं और इस बजट में महिला सशक्तिकरण के संबंध में भी अनेक योजनाएं केंद्रित हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था के मानक, जिनके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था परखी जाती है, चाहे जीडीपी हो, इसके साथ-साथ, inflation, current account deficit, fiscal deficit, asset creation, अगर हम सभी मानकों को देख लें, तो हम यह कह सकते हैं कि मोदी सरकार में सभी क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन हुआ है। यह इस बजट में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर 10 वर्ष पहले की बात करें, उस समय स्थिति क्या थी? उस समय स्थिति बहुत ही खतरनाक थी और हम कह सकते हैं 10 वर्ष पहले यूपीए के समय एक तरीके से काला अध्याय था। मैं एक-दो ही एग्जांपल्स दूंगा। यहां पहले के वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। 2008-09 में fiscal deficit 6.1 परसेंट था और वह 6.1 परसेंट इसलिए था कि एक तरीके से बजट में थोड़ा मैनिपुलेशन किया गया था। फर्टिलाइजर सब्सिडी देने के लिए उसका बॉन्ड, ऑयल बॉन्ड और इसी प्रकार एफसीआई आदि के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए गए, जबकि उसको बजट में होना चाहिए था। उसको बजट में नहीं दिखाया गया और fiscal deficit को 6.1 परसेंट पर रखा गया। यह 2008-09 की स्थिति है। यूपीए के समय में जो बजट आता था, उसमें हम कह सकते हैं कई under-statement, under-provisioning और manipulation देखने को मिलता था। 2013 में यूपीए के समय के कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं, 'Mainly many large projects, both in public sector as well as in private sector, especially in infrastructure

and manufacturing sector, have been held up for investment on account of delay in obtaining various approvals and clearances.' This is the statement of Cabinet Secretary of the UPA Government in 2013. वे कहते हैं कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट इसलिए रुक गए हैं, क्योंकि उनको क्लीयरेंस या अप्रूवल नहीं मिल रही है। उस समय के इकोनॉमिक एडवाइजर्स में डा. शंकर आचार्य से लेकर अन्य इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने इस बात को कहा कि यह जो यूपीए ने 10 साल का जो एक सुनहरा अवसर था, उसको खोने का काम किया है। उस परिस्थिति से मोदी जी आगे बढ़े और रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की पॉलिसी को मूल मंत्र बनाकर आगे चले। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था तीन साल लगातार विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था बनी। यह हमें सामने दिख रहा है। अभी कपिल सिब्बल जी भी बोल रहे थे, बहुत सारे सदस्य भी कह रहे थे और एक-एक हेड ऑफ Accounts का एलोकेशन लेते हैं और कहते हैं कि इस मिनिस्ट्री में कम दिया, इसमें ज्यादा दिया, इसमें ऐसा किया। बजट का एनालिसिस ऐसे थोड़े ही होता है। अगर बजट का एनालिसिस करना हो, तो आप देखेंगे कि पिछले बजट से 7.4 परसेंट इस बार बढ़ाया गया। इसको इस स्वरूप से देखो कि देश की आजादी के 67 साल तक, जिसमें अधिकांश समय यूपीए Congress ने शासन किया, देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल खर्चा कितना होता था? देश की आजादी के 67 साल बाद, जिसमें यूपीए ने अधिक शासन किया, वह 16.65 लाख करोड़ था। अब इन 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में क्या हुआ? देश के गरीबों, किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50.65 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि इन 10 सालों में मोदी सरकार तीन गुना से अधिक खर्च कर रही है। यह बजट का साइज है। इतने बड़े बजट का साइज देखकर हम कह सकते हैं कि मोदी है, तो मुमकिन है, अन्यथा यह संभव नहीं था। जब ये 16 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करते थे, तो कितने अस्पताल बनाते, सड़कों की स्थिति क्या होती और कितने गरीबों की मदद कर सकते थे? इसलिए इन्होंने कुछ नहीं किया।

अब मैं दो-तीन बातें और बताता हूं। मैं दो-तीन मिनिस्ट्रीज़ की ही बात बताऊंगा। हैल्थ सेक्टर में, मनुष्य को कम से कम स्वास्थ्य सुविधा तो मिलनी ही चाहिए, यूपीए के समय में 10 साल में 2013-14 में हैल्थ का बजट केवल 37,000 करोड़ रुपए होता था। हमारे समय में, मोदी जी के समय में इस बजट में अगर हम देखेंगे, तो इसको 37,330 करोड़ से बढ़ा कर 98,311 करोड़, मतलब तीन गुना अधिक बढ़ाने का काम किया गया है।

इसके साथ, आप रेलवे का बजट देखिए। आज रेलवे में जाना मूलभूत आवश्यकता हो गई है। लोग अधिक से अधिक रेलवे में सफर कर रहे हैं। यूपीए के समय में 28,174 करोड़ बजट था। आप 28,174 करोड़ खर्च करेंगे, तो आप कितनी रेलवेलाइंस बिछाएँगे, कितने कोच बनाएँगे, कैसे ट्रेन चलाएँगे, आप कल्पना करिए! उस 28,174 करोड़ से 2,65,000 करोड़, मतलब छः गुना अधिक रेलवे में खर्च मोदी सरकार के माध्यम से इस बजट में आप देखेंगे। अभी रेल मंत्री जी यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और रेल मंत्री जी ने महाकुंभ के लिए 137 स्पेशल ट्रेन्स चलाई हैं, ताकि श्रद्धालु वहाँ जाकर संगम में स्नान कर सकें, डुबकी लगा सकें। इसलिए उनका विशेष अभिनंदन।

मैडम, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कहना चाहता हूँ। किसान हमारा अन्नदाता है। उस अन्नदाता के लिए यूपीए के समय 2013-14 में 27,000 करोड़ रुपए बजट में रखे जाते थे। उस

27,000 करोड़ रुपए में अन्नदाता का कितना भला हो सकता था! यह मोदी सरकार है, जो इसको 27,049 करोड़ से बढ़ा कर 1,71,437 करोड़, मतलब छः गुना से अधिक किसानों को देने का काम कर रही है। इसके साथ-साथ, इस बजट को लेकर हमारे देश के किसान बहुत प्रसन्न हैं। हम लोग जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें इंटरेस्ट की भी छूट मिलती है, गाँव में हर किसान, किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। विशेष रूप से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहूँगा कि उस किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दी गई है। उसके साथ-साथ, किसान के लिए अनेक योजनाएँ चल रही हैं, किसान सम्मान निधि की योजना चल रही है। उसके साथ-साथ, इस बजट में विशेष रूप से प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की जो शुरुआत की गई है, उसके माध्यम से 10 वर्षों में 1.7 करोड़ किसानों की आमदनी बढ़ेगी, यह घोषणा हुई है। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित है। इसी का नतीजा है कि पूरे देश का किसान, जहाँ भी चुनाव होता है, मोदी-मोदी करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करता है और कांग्रेस तथा विपक्ष को हराने का काम करता है।

इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट देखें, तो इनके समय में 25,000 करोड़ खर्च होता था, जबकि आज चारों ओर एक्सप्रेसवेज़ दिख रहे हैं, तो इसलिए दिख रहे हैं कि 25,860 करोड़ के बदले 2,87,000 करोड़ केवल रोड ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो रहा है, ताकि पूरे देश में नेशनल हाईवे अच्छा रहे, एक्सप्रेसवे अच्छा बने। यह आपको देखने को मिलेगा।

मैडम, मैं एमएसएमई के बारे में जरूर कहना चाहूँगा। एमएसएमई सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और देश का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर, जो लोगों को रोजगार प्रदान करता है, वह एमएसएमई सेक्टर है। एक दशक पहले तक एमएसएमई वालों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। इंस्पेक्टर राज होता था। वे कई कानून के जाल में फँसे रहते थे। जब वे DRT और BIFR में जाते थे, तो उनका केस कभी resolve ही नहीं होता था। परेशान होकर एमएसएमई सेक्टर धीरे-धीरे बंद हो जाता था। देखिए, जब कोविड का समय आया, जब हमारा एमएसएमई सेक्टर परेशानी में था, तो कोविड के समय प्रधान मंत्री जी ने निर्णय लिया कि हमें एमएसएमई सेक्टर को बचाना है, क्योंकि यह अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देता है। उन्होंने मई, 2020 में 3 लाख करोड़ रुपए की Emergency Credit Line Guarantee प्रदान करने का काम किया कि 3 लाख करोड़ रुपए की गारंटी केन्द्र सरकार लेगी। उसके बाद वे वहीं नहीं रुके। उसके बाद 3 लाख करोड़ रुपए से आगे चल कर केन्द्र सरकार एमएसएमई की 5 लाख करोड़ रुपए की Credit Line Guarantee ले रही है। मैं माननीया वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बजट में एमएसएमई सेक्टर को 1.5 लाख करोड़ रुपए की और Credit Line Guarantee देने का काम किया है।

4.00 **P.M.**

इसका मतलब, कुल मिला कर 6.5 लाख करोड़ रुपए की जो क्रेडिट गारंटी एमएसएमई को दी जाएगी, इसके माध्यम से वे फलेंगे-फूलेंगे और फल-फूल रहे भी हैं। उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। मैडम, यूपीए के समय में हम देखें तो हमारे MSME sector में वर्गीकरण होता है। MSME

sector में सूक्ष्म, लघु और मध्यम का वर्गीकरण है। इसका criteria क्या है? वे कभी उसके criteria को बढ़ाते नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे मानते थे कि MSMEs में कोई फल-फूल नहीं रहा है। 2006 में turnover और investment के basis पर MSMEs के लिए एक criteria बनाया गया। 2006-07 के बाद के बीच में 2014 तक उसको बदला ही नहीं। यह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 10 सालों में दो बार MSMEs के investment और turnover के criteria को बढ़ाने का काम किया और इस बजट में तीसरी बार उसका criteria बढ़ाया है। उदाहरण के रूप में micro enterprises की यूपीए के समय में investment की limit 25 लाख होती थी, यानी जो 25 लाख तक का होगा, वह micro enterprises में आएगा। हमारी सरकार ने उसको 25 लाख से 1 करोड़ और एक करोड़ से ढाई करोड़ रुपए करने का काम किया। अगर ढाई करोड़ रुपए का plant and machinery में तथा और कहीं investment रहेगा, तो वह micro enterprises हो जाएगा। इसी प्रकार जो small enterprises है, उसमें भी criteria को ढाई गुना बढ़ाने का काम किया और हमारा जो medium enterprises है, उसका भी criteria बढ़ाया, जिससे उनके काम करने की साइज बढ़ जाती है। जब investment size बढ़ती है, तो उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। उनके turnover को भी बढ़ने का काम किया गया। कुल मिलाकर इसका आइडिया यह है कि अधिक से अधिक MSMEs को लाभ देने का काम करें। इनके लिए यह काम भी किया गया कि 200 करोड़ रुपए तक का global tender नहीं होगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से लोगों को MSME sector को लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही Prime Minister's Employment Generation Programme, Entrepreneurship and Skill Development Programme भी हैं। इतना लाभ देने का ही यह नतीजा है कि MSMEs का manufacturing sector में 36 परसेंट और एक्सपोर्ट में 45 परसेंट का योगदान है। और तो और, यह हमारा MSME sector ही है कि जो खिलौने हम पहले इंपोर्ट करते थे, आज के दिन हम खिलौनों को एक्सपोर्ट करते हैं। हम 239 परसेंट निर्यात कर रहे हैं, इंपोर्ट करने की बात तो छोड़ दीजिए। हम पहले विदेशों से भी खिलौने मंगाते थे। PLI Scheme के माध्यम से MSMEs को प्रमोट किया गया है। पहले हम 2013-14 में 49 हजार करोड़ रुपए के मोबाइल्स इंपोर्ट करते थे, अब हम 2024 में 15 बिलियन डॉलर्स के स्मार्टफोन, मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट किये हैं। हमारे यहाँ मोबाइल की पहले दो कंपनियां होती थी, अब हमारे यहां 300 से अधिक कंपनियां हैं।

महोदय, जहाँ तक मध्यम वर्ग की बात है, तो आज तो पूरे देश में मध्यम वर्ग प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन कर रहा है, चिट्ठी लिख रहा है, क्योंकि मध्यम वर्ग को जिस प्रकार से लाभ देने का काम किया गया है, वह अद्भुत है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) *पीठासीन हुए ।***]**

12 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स में exemption दी गई है। इसके अलावा पहले अगर आपकी रिटर्न लेट हो जाती थी और आप अपनी रिटर्न में कुछ चेंज करना चाहते थे, तो आप पहले 2 साल तक ही उसको रिवाइज कर सकते थे, लेकिन अब हम उसको 5 साल तक रिवाइज कर सकते हैं। पहले प्रोसेसिंग टाइम में बहुत दिन लगते थे, लेकिन अब 16 दिन के अंदर ही इनकम टैक्स का रिफंड आपके पास आ जाता है। इसमें सीनियर सिटीजंस को भी लाभ मिला है। अब

50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक टीडीएस नहीं कटेगा और इस प्रकार से रेंट पर भी TDS की सीमा बढ़ा दी गई है। मैं तो इतना ही कहूंगा, चूँकि समय नहीं है कि जो सामने वाले 50-50 परसेंट की बात करते थे कि 50 परसेंट वालों को क्या मिला, तो अगर मैं उसके बारे में बोलूंगा, तो इसमें 2 घंटे लग जाएंगे। 'प्रधान मंत्री आवास योजना' से लेकर 'नल से जल' और जन औषधि केंद्र से लेकर अनेकों योजनाओं के बारे में बात करूंगा, तो उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बताने में मिनिमम एक घंटा लगेगा कि 50 परसेंट को क्या मिला, 25 परसेंट को क्या मिला।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपने तो गागर में सागर भर ही दिया है।

श्री अरूण सिंह: महोदय, मैं अंत में यही कह सकता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में Ease of Doing Business में लगातार उछाल हो रहा है और हम 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच चुके हैं तथा तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। इससे यह मानकर चलिएगा कि 'विकसित भारत' बनाने का जो संकल्प है, उसको साकार भी करेंगे, यह प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव है। यह इसलिए सम्भव है, क्योंकि पूरे विश्व में केवल एक व्यक्ति केवल ऐसा है, जिसको 14 राष्ट्रों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं, उसका नाम है - नरेन्द्र मोदी। विपक्ष के साथी भी अगर अच्छी बातों की तारीफ करने लगेंगे, तो उनकी जो 'जीरो-जीरो' सीटें हर राज्य में आ रही हैं, अच्छी बातों की सराहना करें, जो आपको कमी दिखे, उसको क्रिटिसाइज करिए, तो जनता भी आपको कुछ ना कुछ सीटें देगी, लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे, इसलिए आपको लगातार हार का मुँह देखना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद, अरुण सिंह जी। श्री अशोक सिंह।

श्री जयराम रमेश: सर, इनका मैडन स्पीच है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): जी हाँ, इनका यह मैडन स्पीच है।

श्री अशोक सिंह (मध्य प्रदेश)**:** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी का और अपने वरिष्ठ नेतृत्व का आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे देश की सबसे बड़ी संसद में बोलने का अवसर दिया। महोदय, देश के वित्त मंत्री महोदया ने लोक-लुभावन बजट पेश किया है। जिसमें आंकड़े और डेटा के जरिए देश के गरीब और मध्यम वर्ग को फिर से छलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल ग्वालियर से आता हूँ और खेती-किसानी परिवार से आता हूँ तथा बजट पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूँ। मैं आंकड़ों के माया जाल से अलग, गरीब आदमी की भोजन की थाली पर बात करना चाहता हूँ। एक तरफ 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने की बात कही जा रही है। कौन-सी बात सही है - यह तो माननीय वित्त मंत्री ही बता पाएंगी। 12 लाख के आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के लिए धन्यवाद, लेकिन 12 लाख की आयकर छूट से कितने लोगों को राहत मिलेगी? मात्र तीन करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं। 137 करोड़ लोगों के बारे में, उनके विकास और

उनकी सुविधाओं के बारे में कोई बात बजट में नहीं कही गई है। गरीब, मध्यम वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं, वे बहुत ही नाकाफी हैं। आज भी किसानों को डीएपी व अन्य उर्वरकों के लिए रात-रात भर लाइन में लग कर, कड़ी ठंड में ठिठुरते हुए खाद लेना पड़ता है। आज इस देश में कौन-सी तरक्की की बात कही जा रही है?

महोदय, किसान पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। किसानों के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। किसान लगातार कर्ज में दबा जा रहा है। किसानों पर कर्जे और बढ़ते जा रहे हैं। हमारी तो माँग है कि जिस तरह यूपीए सरकार में लगभग 72 हजार करोड़ रुपए के किसानों के कर्जे एकमुश्त माफ किए गए थे, उसी तरीके से किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। एमएसपी भी बहुत कम है। उसको लेकर कोई बात नहीं कही गई है। उसे बढ़ाया जाए। उत्पादन आधारित उद्योगों की कीमत प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय होती है। बजट में कानून बना कर भी एमएसपी कानून बनाया जाए, जिसमें किसानों के उत्पादन के लागत मूल्य के आधार पर किसानों की फसलों के दाम तय किए जाएं।

इमरजेंसी की बहुत बात की जाती है, पर आज देश में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में उन्हीं लोगों के यहां ईडी ने छापे मारे, जिन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाग लिया था और सहयोग किया था। एक परिवार के बच्चे ने तो केवल गुल्लक भेंट की थी। उस परिवार के यहाँ ईडी का छापा पड़ा और उस बच्चे के माता-पिता को आत्महत्या करनी पड़ी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी मध्य प्रदेश में एक छापा पड़ा, जिसमें ईडी, आईटी और लोकायुक्त, तीनों संगठनों ने छापा मारा था। एक परिवहन कर्मचारी से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति - सोना, नकदी जब्त हुई। अभी हाल में ही एक उद्योगपति की पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया, क्योंकि उसकी फैक्ट्री पर केंद्र सरकार के किसी मंत्री के रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था।

महोदय, डॉलर की कीमत लगातार बढ़ रही है। इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जब रुपए की कीमत घटती है, तो प्रधान मंत्री की गरिमा गिरती है। अभी क्या हो रहा है, यह मुझे नहीं पता, लेकिन लगातार डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। उसके बारे में सरकार को कुछ स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए। मध्य प्रदेश में कभी कांग्रेस सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू की थी। यह उस वक्त भी 300 रुपये थी और आज भी 300 रुपये ही है। इस लगातार महंगाई के चलते क्या वृद्ध लोगों का गुजारा 300 रुपये में हो सकता है, यह आपको देखना चाहिए। भारत सरकार के कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश में डीएपी की कालाबाजारी भी हुई, खाद को लेकर लगातार संकट रहा, यहां तक की कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में भी डीएपी की कालाबाजारी हुई। युवाओं के सामने रोजगार का संकट लगातार खड़ा होता जा रहा है। युवा बेरोजगारी दर लगभग 45.4 परसेंट तक पहुंच चुकी है। ग्रेजुएट लोगों की बेरोजगारी की दर भी 29.1 परसेंट है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जीएसटी भी उन्हीं देशों में सफल हुआ है, जहां सिंगल स्लैब सिस्टम है, पर यहां अभी भी जीएसटी में पांच-छः तरह के स्लैब्स हैं और सेंट्रल सेस भी लिया जा रहा है, जो कि उपभोक्ता और इंडस्ट्रियलिस्टस, सभी के साथ एक तरह से अन्याय है। जीएसटी सिस्टम में एकरूपता लानी चाहिए, तभी यह सक्सेस हो पाएगा। यह राज्यों का सदन है। पेट्रोल, अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी में लिया जाना चाहिए। स्टार्टअप की बात की

जाती है, लेकिन कितने रजिस्टर्ड हुए और कितने सफल हुए, इसका कोई आंकड़ा इसमें नहीं है और मुझे लगता है कि यह एक सोच का विषय है।

महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें बजट एलोकेशन काफी कम कर दिया गया है। फूड, हेल्थ, हेल्थकेयर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और यहां तक कि अनुसूचित जनजाति के लिए भी बजट के प्रावधानों में कमी की गई है।

महोदय, देश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं और इनके इलाज के लिए गरीब आदमी को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। देश में AQI level को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम सरकार को करना चाहिए था, वह अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। सरकारी नौकरियां लगभग समाप्तप्राय हो गई हैं। प्राइवेट सेक्टर में युवाओं की जो वर्किंग कंडीशन है, वह बड़ी खराब है। वहां उनके लिए न तो बीमा की व्यवस्था है और न ही उनके हेल्थ के लिए कोई व्यवस्था की गई है।

महोदय, देश में लगातार जातीय जनगणना की मांग की जा रही है। सामाजिक- आर्थिक दृष्टि से किसको क्या जरूरत है, यह ऐसी जनगणना से ही सामने आ सकता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जातीय जनगणना भी शीघ्र से शीघ्र कराया जाए। हम स्टील के क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक देश बन गए हैं, लेकिन यह सिर्फ इस कारण नहीं है कि इन 10 सालों में इसमें कोई प्रगति हुई है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की दूरदर्शिता थी, जिन्होंने आजादी के बाद भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, जैसे कई बड़े प्लांट्स बनाकर इसको एक दिशा दी थी। देश अगर आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ है, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी और स्वर्गीय डा. मनमोहन सिंह जी के कारण हुआ है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चिदम्बरम जी ने अपने भाषण में कहा था कि डा. मनमोहन सिंह जी को "भारत रत्न" दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को इसकी जल्दी से जल्दी घोषणा करनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर जीडीपी बढ़ रही है, तो वेतन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, नौकरियां क्यों खत्म हो रही हैं? उत्तर स्पष्ट है कि इस सरकार में आर्थिक नीति केवल अमीरों के लिए बनाई गई है, आम जनता के लिए नहीं बनाई गई है। मेक इन इंडिया एक प्रचार अभियान बन कर रह गया है, न कि औद्योगिक क्रांति। निर्माण क्षेत्र में जीडीपी में योगदान बढ़ने की बजाय घटा है। घरेलू मांग में भी लगातार गिरावट जारी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी कटौती की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बजट की कटौती की गई है। महोदय, वर्ष 2013-14 में शिक्षा पर बजटरी खर्च 3.1 परसेंट था, जो अब घट कर 1.55 परसेंट रह गया है। महोदय, वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य पर खर्च 2.31 परसेंट था, जो अब घट कर मात्र 1.9 परसेंट रह गया है। वहीं कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में शिक्षा पर 10 परसेंट और स्वास्थ्य पर 5 परसेंट बजटीय खर्च किया जाता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हम एक अलग भारत की परिकल्पना करते हैं, जहां अर्थव्यवस्था सभी के लिए हो, केवल अरबपतियों के लिए न हो। जहां रोज़गार बढ़े, नौकरियां खत्म

न हों, जहां किसान समृद्ध हों, वह कर्ज़ के बोझ से न दबे और जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद। सभी ने आपकी मेडन स्पीच pin drop silent हो कर सुनी है। श्री निरंजन बिशी।

श्री निरंजन बिशी (ओडिशा): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यूनियन बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं अपने नेता नवीन पटनायक जी को भी धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमारे देश में 140 करोड़ नागरिकों ने यूनियन बजट को देखा है और 80 करोड़ नागरिक, जिनको हम राशन देते हैं, वे भी बजट से बहुत कुछ आशा करते हैं कि पेट्रोल का रेट कम होगा, डीजल के दाम कम होंगे, गैस-सिलेंडर के दाम कम होंगे। पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे, तो essential commodities, जैसे चावल, दाल, आलू, प्याज़ और तेल इत्यादि के दाम कम होंगे, inflation rate कम होगा। अगर दाम कम होंगे, तो उन 80 करोड़ भारतीय नागरिकों का भी डेवलपमेंट होगा। महोदय, इस बजट को देखें, तो पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं हो रहे हैं, तो essential commodities के दाम कैसे कम होंगे और inflation कैसे कम होगा। यह एक निराशाजनक बजट है। महोदय, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी कोल royalty में revision करने के लिए चिट्ठी लिखते आए हैं, डिमांड करते आए हैं कि अगर coal royalty revise होगी, तो ओडिशा को 10 हज़ार करोड़ रुपये royalty मिलेगी, जिससे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, irrigation आदि का विकास होगा और employment बढ़ेगा।

महोदय, हमारे ओडिशा में बहुत सारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, मिल्स आदि बंद हैं। शुगर मिल बंद है, पेपर मिल बंद है, स्पिनिंग मिल बंद हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हैं, तो unemployment बहुत बढ़ रहा है। अनइम्प्लॉमेंट इतना बढ़ रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी, लेबर वर्कर्स, किसान, छोटे किसान, मार्जिनल फार्मर्स सब रोज़गार की तलाश में दूसरे स्टेट्स और दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं और daily 4-5 dead bodies reported to Odisha. ऐसे हालात हो गए हैं, बेकारी की समस्या बढ़ गई है। महोदय, 80 करोड़ आम नागरिक, जिनमें एससी/एसटी भी शामिल हैं, वे इस बजट से परेशान हैं। महोदय, एससी/एसटी के लिए बजट में कुछ नहीं है और Ministry of Social Justice and Empowerment के अंदर एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन के welfare के लिए department होता है, उस डिपार्टमेंट के लिए मात्र 1,200 करोड़ रुपये फंड दिया है। एससी/एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और दिव्यांगजन की डेवलपमेंट कैसे होगी? एससी/एसटी डेवलपमेंट के 2024-25 में 26 हजार करोड़ रुपए का फंड था, इस साल भी वह 26 हज़ार करोड़ है, तो क्या केन्द्र सरकार एससी/एसटी डेवलपमेंट, ओबीसी डेवलपमेंट, माइनॉरिटी डेवलपमेंट और दिव्यांगजन के डेवलपमेंट के लिए बजट का प्रोविजन नहीं करेगी। जो marginalised community है, weaker section है, deprived community है, working class है, toiling masses है, उसका डेवलपमेंट नहीं होगी, तो सबका साथ, सबका विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा? इसलिए भारत का जो son of the soil है, वर्किंग कम्युनिटी है, toiling masses है, marginalised class है, उसके डेवलपमेंट के लिए इस बजट में प्रोविजन होना

चाहिए, बजट बढ़ाना चाहिए। अगर एससी/एसटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, माइनॉरिटी की डेवलपमेंट नहीं होगा, वीकर सेक्शन और दिव्यांगजन का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो देश का विकास कभी भी नहीं होगा। हम सब बहस करते हैं कि इस मिनिस्ट्री को इतना दिया, उस डिपार्टमेंट को इतना दिया, लेकिन जो इस देश के फार्मर्स हैं, marginalised farmers हैं, किसान हैं और महंगाई की मार से मजदूर की कमर टूट गई है, तो 80 करोड़ मजदूरों के विकास के लिए भी कुछ करना चाहिए। केन्द्र सरकार को इनके लिए बजट का प्रोविजन करना चाहिए। ओडिशा को दस हजार करोड़ की coal royalty देनी है। अगर नहीं देंगे, तो यहां मंत्री जी भी हैं, हमारे वेस्टर्न ओडिशा में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थीं, फैक्टरीज़ थीं, मिल्स थीं, वे सब बंद हो गई हैं। उनके लिए job and employment opportunity के लिए हमारे यहां कॉटन फैक्टरी की आवश्यकता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है ...(**समय की घंटी**)... एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। अगर मिल, फैक्टरी और इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, तो job opportunity बढ़ेगी, employment opportunity बढ़ेगी, तो देश का विकास होगा, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद। श्रीमती सुधा मूर्ती।

SHRIMATI SUDHA MURTY (Nominated): Thank you, Sir, for giving an opportunity to speak on the Budget. First, I want to congratulate Nirmalaji for her eighth consecutive submission of the Budget. As a woman, I am extremely proud about her. Secondly, her Budget is really good. Particularly for the middle-class, she has given tax exemption up to Rs.12 lakh annual income. As I grew up in a middle-class family, I know what this relief means to a family. She has also done good work for the senior citizens and infrastructure development. I congratulate her for that.

I have a small suggestion for her, and this is with my own experience that I am going to talk. We can teach children AI, computer science, mathematics, etc., but we are not making our children good citizens with good character. We are not able to give value-based education. The reasons are many. Number one is that there are nuclear families and there are no grand parents who can sit and talk about it or teach. Normally, husband and wife both are working in cities and there are cramped schools. So, there are many reasons for this. It is very difficult to bring up children without value system because ultimately, they do not become good citizens, even though they may be highly educated people. If you tell children that they should have *sathyam vada; dharmam chara,* and all these things, they may not understand. They will take it as those moral science classes and run away. Once I was working in a village in a school area and many parents, particularly mothers, came and told me that their children did not listen to them. They did not read and were not interested in doing any other work. So, they asked me for a solution. I told them that there was no quick solution for that, but let us experiment. It was a Government school and it had

good toilet and water facilities, mid-day meal and all these things. So, I told, let us build one big air-conditioned hall because it was a warm area. We built one air-conditioned hall and there I told them to keep some children books and story books. I called the volunteers and mothers, along with the teachers, and I told them, children's mind is like a wet wall.

If you properly teach them good values at this time through stories, then it is possible to catch and hold their attention and children may learn better. This is what we believe in. We gave them some material. I visited them after one year. The things were so different after one year. It was because there were many mothers who contributed towards this initiative in the afternoon time; there were some volunteers who wanted to contribute. It gave them an opportunity. The children were attracted to the air conditioned room in summer. They never went out. They came to school and went to the hall where they could do a lot of other indoor activities like chess, stitching, dancing and music etc. etc. Along with that, it creates good value system of good stories, good books and storytelling.

We come from a land where *smriti* and *shruti* were both equally important. Here, *smriti* means that we should remember and *shruti* means that we should hear. Many of our epics and many of our *vedas* have been continued for years with *smriti* and *shruti*. The story is not just telling children a few lines. It is actually an advantage to children to imagine and increase their creativity, and it is a great communication from one person to another person. So, the teachers and the volunteers, along with the mothers, started telling good value based stories, simple stories like *Kuchela and Krishna* - the value of friendship; *Arjuna and Ekagrachitta* - value of concentration, and, Buddha and compassion. These are the great stories which are available, and these stories should be told to children at a right age in a beautiful manner so that they can learn all these things, and, children did learn.

There, I could see a lot of paintings on the walls. Children also started writing their own stories. By this, I realized that if you want to attract children to school, you should have a big hall where they can do indoor activities, and, you should have teachers and volunteers who can tell them stories. I am sure that the Government of India in the new National Education Policy has revised the syllabus with stories. I have seen that. I really appreciate, but writing stories is different. As an author, I know, writing stories is different and telling stories is entirely different. This storytelling tradition was there in our country before also. We have to inculcate this with our teachers. When you give training to teachers, we always say, they should be B.A.-B.Ed., M.A.-M.Ed., but we never emphasized on converting the difficult situation, difficult subject in the form of stories, and convince the children. That is the reason I

feel we should have compulsory story telling sessions in school and we should also have teachers' training inclusive of storytelling and, if possible, we should have an institution to be built over a period of time for storytelling. India is always famous for stories. We have a great storytelling tradition with '*kathasaritsagara*'. '*Kathasaritsagara*' tells thousands of stories, but we do not worry about that. Instead, we always go and see what is there in the Western countries and tell their stories. No, it is not correlating to our culture.

I want to give a small example. 5,500 years ago, in Lothal, they found out an object. It was a very small cup and, on the cup, there was a story, a story without any words. A crow was sitting on a small bowl and there was a stone in the crow's mouth. All of us know this story. The crow was thirsty but there was little water in that cup. It dropped a stone and the water came up. The crow drank it and ran away. This story is 5,500 years old. It means that India had this tradition of passing great stories on to the next generation.

We have Pandit Vishnu Sharma's Panchatantra. What does it tell? When children did not study well and father was worried, he brought children back to a teacher and he taught the entire politics of the kingdom, the rules of the life and everything in the form of a story. We should not neglect this great art of storytelling and we should make this a part of the curriculum. We should also ask teachers to tell it in a proper way. For that, we require a big haul. May I request our Finance Minister that particularly until the primary education and high school level, they require this new art introduced in their lives, and the Government of India should give a little more funding for building a class room with an air conditioner or a fan, depending on the situation? We have always a tradition of talking and conveying our feelings in many ways. I have seen in this august gathering here that people express their views. The expressions come through talking and talking comes through stories. Stories also make you to imagine, unlike digital media. When you see something on digital media, your imagination is limited, whereas when you do not see the digital media and imagine, then there is no ceiling. You can go on the top only by imagining. That is the reason we say the beautiful *shaloka*:

"शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्।"

If you see a digital media, you can see a hero's features, but you can't imagine. If you want to imagine, you have to read stories, you have to tell stories. Please do not mistake me that because I am an author of children stories, I am selling

my book. It is not for that at all. My books are sold otherwise. But I got this creativity because I learned great stories in my childhood. I can imagine Lord Krishna or Vishnu or anybody of my choice closing my eyes. He has a *shanta chitta*; he has the *neel varna*. He has beautiful eyes. He is a गगनसदृशं, up to the top of the clouds. All this, I get with my imagination. This is only thanks to my elders who taught me stories, thanks to my teachers who inculcated the habit of storytelling, thanks to my readers who gave me the feedback. The best way to teach is through storytelling. Thank you, Sir, for giving me an opportunity to express my views. I want to ask Madam Nirmala ji to release a little more money for primary and high school level to build a beautiful library. Again, all the indoor games along with storytelling sessions should be there. And a library is nothing but the house of learning and knowledge. *Dhanyavad*. Jai Hind.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri A.D. Singh, not present. Shri Javed Ali Khan.

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मैं फाइनेंस के बारे में और अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। जोड़ना और घटाना मुझे आता है, इतना मैथमैटिक्स मैं जानता हूँ। चूँकि मेरा समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात बिल्कुल संक्षेप में रखूँगा। सर, सरकार का बजट या कोई भी नीतिगत दस्तावेज होता है, वह उसकी फिलोस्फी या उसके दर्शन को परिलक्षित करता है। यह 2025-26 का जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है, इसमें अल्पसंख्यकों की घोर उपेक्षा की गई है। अल्पसंख्यकों से मेरा तात्पर्य यह है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही थीं, जो कार्यक्रम इस सरकार ने बनाए थे या इससे पहले की सरकार ने बनाए थे, उन्हें या तो बंद कर दिया गया है या उनकी मद में भारी कटौती की गई है। एक वक्ता कह रहे थे कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक विकसित नहीं होंगे। अल्पसंख्यकों के संबंध में एक योजना थी - Pre-matric Scholarship for Minorities. वह योजना है। 2023-24 में इस योजना का बजट 433 करोड़ था, 95 करोड़ release हुआ था। 2024-25 के बजट में 326 करोड़ दिया गया, 90 करोड़ release हुआ। इसको इस बजट में 326 में से घटाकर - करीब 130 करोड़ घटाकर बजट 195 करोड़ हो गया है, लेकिन इसमें रिलीज कितना होगा, यह हम नहीं जानते हैं। वह अगले साल देखेंगे। पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ योजना का बजट 2024-25 में 1,145 करोड़ था। इस बजट में इस योजना के लिए 413 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें 731 करोड़ रुपए कम हो गए। माइनॉरिटीज़ की इस स्कॉलरशिप योजना के लिए बजट 65 परसेंट कम कर दिया गया। सर, Merit-cum-Means Scholarship for Professional and Technical Courses, इस योजना के लिए 2024-25 में 33.80 करोड़, यानी करीब 34 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और 2025-26 के बजट में 7.34 करोड़, यानी 83 परसेंट कम है और इसके अंदर 26 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं। Overseas Educational Loan Interest Subsidy, जो सरकार देती थी, इसमें 2024-25 के बजट में 5.30 करोड़ दिया जाना था और इस बार घटाकर उसे मात्र

8.16 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना के तहत भी 7.14 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं। पहले मदरसा और माइनॉरिटीज़ स्कीम को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए जाते थे। अटल जी के जमाने में वह स्कीम शुरू हुई थी। 2023-24 में इसका बजट 10 करोड़ था और 2024-25 में इसको मात्र 2 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस बार मात्र 1 लाख रुपये, यानी टोकन दिया गया है। मतलब इस योजना को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है।

सर, 2020-21 में माइनॉरिटीज़ की दो योजनाएं थीं - कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती स्कीम और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना, इन दोनों योजनाओं को मर्ज कर दिया गया। ये दोनों योजनाएं वक्फ की जमीन पर व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्याज मुक्त लोन देती थीं और इसका बजट 2023-24 में 17 करोड़ था। इसे 2024-25 में घटाकर 16 करोड़ कर दिया गया। इस बार घटाकर इसका बजट सिर्फ 13 करोड़ कर दिया गया। मैं यह समझता हूं कि इस तरीके की जो कटौती अल्पसंख्यकों से संबंधित मदों में की गई है, इसके पीछे निश्चित रूप से सबका साथ, सबके विकास की फिलॉसफी नहीं है। इसके पीछे कौन सी फिलॉसफी काम कर रही है? मुझे लगता है कि गोलवलकर जी की जो किताब है - We or Our Nationhood Defined, जिसमें माइनॉरिटीज़ को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का संकल्प लिया गया है और Bunch of Thoughts, जिसमें मुसलमानों को दुश्मन नंबर एक और ईसाइयों को खतरा नंबर दो बताया गया है - वह फिलॉसफी, वह दर्शन इस बजट के पीछे काम कर रहा है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان) اترپردیش** :(اُپ سبھاادھیکش جی، میں فائننس کے بارے میں اور ارتھ شاستر کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتا ہوں۔ جوڑنا اور گھٹانا مجھے آتا ہے، اتنا میتھ میٹکس میں جانتا ہوں۔ چونکہ میرا وقت کم ہے، اس لیے میں اپنی بات بالکل مختصر رکھونگا۔ سر، سرکار کا بجٹ یا کوئی بھی نیتی گت دستاویز ہوتا ہے، وہ اس کی فلاسفی یا اس کے درشن کو پریلکشت کرتا ہے۔ یہ 2025-26 کا جو بجٹ ہمارے سامنے پیش ہوا ہے، اس میں اقلیتوں کی گھور اپیکشا کی گئی ہے۔ اقلیتوں سے میری مراد یہ ہے کہ اقلیتوں کی بہبود کے لیے جو یوجنائیں چل رہی تھیں، جو کارئیے کرم اس سرکار نے بنائے تھے یا اس سے پہلے کی سرکار نے بنائے تھے، انہیں یا تو بند کردیا گیا ہے یا ان کی مد میں بھاری کٹوتی کی گئی ہے۔ ایک وکتا کہہ رہے تھے کہ جب تک شکشت نہیں ہونگے، تب تک وکسِت نہیں ہونگے۔ اقلیتوں کے تعلق سے ایک یوجنا تھی Pre-matric Scholarship for Minoritiesوہ یوجنا ہے۔ 2023-24 میں اس یوجنا کا بجٹ 433 کروڑ تھا، 95 کروڑ ریلیز ہوا تھا۔2024-25کے بجٹ میں کروڑ 326 دیا گیا، 90 کروڑ ریلیز ہوا۔

اس کو اس بجٹ میں 326میں سے گھٹاکر، قریب 130 کروڑ گھٹاکر بجٹ 195 کروڑ ہوگیا ہے، لیکن اس میں ریلیز کتنا ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ وہ اگلے سال دیکھیں گے۔ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ فار مائنارٹیز یوجنا کا بجٹ 2024-25 میں 1,145 کروڑ تھا۔ اس بجٹ میں اس یوجنا کے لیے 413 کروڑ مختص کئے گئے ہیں۔ اس میں 731کروڑ روپے کم ہوگئے۔ مائنارٹیز کی اس اسکالرشپ یوجنا کے لیے بجٹ 65 فیصد کم کردیا گیا۔ سر، Merit-cum-Means Scholarship for Professional and Technical Courses,اس یوجنا کے لیے 2024-25میں 33.80 کروڑ، یعنی تقریباً 34 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے اور 2025-26کے بجٹ میں 7.34 کروڑ، یعنی 83 فیصد کم ہے اور اس کے اندر 26 کروڑ روپے کم کردیے گئے ہیں۔Overseas Educational Loan Interest Subsidy,جوسرکار دیتی تھی، اس میں 2024-25 کے بجٹ میں 5.30 کروڑ دیا جانا تھا اور اس بار گھٹاکر اسے صرف 8.16 کروڑ کردیا گیا ہے۔ اس یوجنا کے تحت بھی 7.14 کروڑ

† Transliteration in Urdu script.

روپے کم کردیے گئے ہیں۔ پہلے مدرسہ اور مائنارٹیز اسکیم کو سیکڑوں کروڑ روپے دیے جاتے تھے۔ اٹل جی کے زمانے میں وہ اسکیم شروع ہوئی تھی۔ 24-2023 میں اس کا بجٹ دس کروڑ تھا اور 25-2024 میں اس کو صرف دو کروڑ روپے کردیے گئے تھے اور اس بار صرف ایک لاکھ روپے، یعنی ٹوکن دیا گیا ہے۔ مطلب اس یوجنا کو پورے طریقے سے بند کردیا گیا ہے۔

سر، 21-2020 میں مائنارٹیز کی دو یوجنائیں تھیں۔ قومی وقف بورڈ ترقیاتی اسکیم اور شہری وقف سمپتّی وکاس یوجنا، ان دونوں یوجناؤں کو مرج کردیا گیا۔ یہ دونوں یوجنائیں وقف کی زمین پر ویاپارک گتی ودھیوں کے لیے بیاج مکت لون دیتی تھیں اور اس کا بجٹ 24-2023 میں 17 کروڑ تھا۔ اسے 25-2024 میں گھٹاکر 16 کروڑ کردیا گیا۔ اس بار گھٹاکر اس کا بجٹ صرف 13 کروڑ کردیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی جو کٹوتی اقلیتوں سے متعلق مدوں میں کی گئی ہے، اس کے پیچھے واضح طور پر سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کے وکاس کی فلاسفی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کون سی فلاسفی کام کررہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ گولوالکر جی کی جو کتاب ہے We or Our Nationhood Defined, جس میں مائنارٹیز کو دوسرے درجے کا ناگرک بنانے کا سنکلپ لیا گیا ہے اور Bunch of Thoughts جس میں مسلمانوں کو دشمن نمبر ایک اور عیسائیوں کو خطرہ نمبر دو بتایا گیا ہے۔ وہ فلاسفی، وہ درشن اس بجٹ کے پیچھے کام کررہے ہیں۔ آپ نے مجھے بولنے کے لیے وقت دیا، بہت بہت دھینواد۔ ...)مداخلت(...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): नियम से हो जाएगा, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... श्री पी.पी. सुनीर।

SHRI P. P. SUNEER (Kerala): Sir, I rise today with a heavy heart but a resolute voice to expose the BJP-led Union Government's blatant financial discrimination and political vendetta against the State of Kerala and the Left on behalf of my party, the Communist Party of India. The BJP has made it clear -- through its policies, through its actions and through its systematic economic strangulation -- that it seeks to punish Kerala for its unwavering commitment to secularism, social justice, and the welfare of its people. Since the people of Kerala have repeatedly rejected the BJP's divisive and corporate-driven politics, this Government has chosen to retaliate by choking our State financially, undermining our developmental progress and depriving our people of what is rightfully theirs.

Sir, Kerala stands tall with an unparalleled model of development. One that prioritises human well-being over corporate profit; one that values education and healthcare over communal discord; one that ensures social security over crony capitalism. And because we have refused to fall in line with the BJP's agenda of corporate appeasement, religious polarisation and reckless economic policies, they have made Kerala a target of economic blockade. Is this how a federal democracy functions? Is this how a Government should treat its own people?

Let me present the facts. Kerala generates over 63.58 per cent of its own revenue, far higher than the national average of 53.9 per cent. Yet, despite our fiscal discipline and responsible governance, the Centre has systematically reduced our

share of funds. Our share in the divisible pool of taxes has been cut from 3.875 per cent under the 10th Finance Commission to a meager 1.925 per cent under the 15th Finance Commission. The BJP Government has choked our finances by ending GST compensation and the Revenue Deficit Grant, leaving Kerala struggling to meet even its basic obligations. When we requested a special package to mitigate this crisis, the Modi Government turned its back on us. Is this cooperative federalism? Is this economic retribution?

Hon. Chairman, Sir, the discrimination does not stop there. When a devastating landslide hit Wayanad on July 30, 2024, claiming more than 250 lives and displacing thousands, Kerala did not receive the assistance it deserved. Even after weeks of grueling rescue and relief efforts, after DNA sequencing to identify the dead, and after struggling to rehabilitate entire communities, the BJP Government continues to deny us Rs. 2,000 crore we need to rebuild. Are we second-class citizens in our country simply because we refuse to bow before the BJP?

Let us talk about infrastructure. The Vizhinjam Seaport -- a game-changer for India's logistics sector -- is up and running promising to transform Kerala into a transshipment hub. But, what does the Union Government do? Instead of supporting this strategic project, they impose unreasonable financial burdens! Kerala seeks Rs. 5,000 crore for critical infrastructure like rail connectivity, a maritime cluster and a green hydrogen hub. Yet, instead of supporting growth, the Centre demands that our Viability Gap Funding be treated as a loan, which would cost the State Rs.10,000 crore in repayments. When seaports receive unending Central support, especially in Gujarat, why does Kerala's port get step-motherly treatment?

This Government has also introduced a new methodology for determining open market borrowing by manipulating figures to strangle Kerala's borrowing space. We demand an increase in our normal borrowing ceiling from 3 per cent to 3.5 per cent of GSDP, along with an additional 0.5 per cent for power sector reforms. But, the Central Government refuses because it wants Kerala's development to stall. Why? It is because we have built a model where education is free, healthcare is accessible and women and the marginalised have security and dignity -- values that stand in stark contrast to the BJP's economic policies of inequality and corporate handouts.

Centrally Sponsored Schemes are another tool of BJP's economic arm-twisting. States are forced to co-fund projects, eating into our resources, while the Centre takes credit. Kerala must contribute Rs.17,500 crore over two years for the Jal Jeevan Mission. But, our borrowing limits are used as a noose around our neck, threatening Rs. 12,000 crore worth of ongoing investments. We demand that CSS funding be exempted from these arbitrary restrictions.

Then, what about social security? The Kerala Infrastructure Investment Fund Board (KIIFB) and Kerala Social Security Pension Company Limited (KSSPL) have been targeted. Their borrowings suddenly being counted as State debt. The Centre has, through deliberate policy tweaks, cost Kerala Rs.3,140.7 crore over four years. This is nothing but economic sabotage, a calculated effort to weaken our welfare State model and push Kerala towards disaster. Even under the so-called Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment, the BJP Government imposes branding requirements that essentially make a political PR exercise rather than a genuine financial aid programme. Why Kerala should be forced to toe the BJP's propaganda line just to receive what is rightfully ours?

The discrimination extends even further. Our National Highway widening projects, in which Kerala has invested 25 per cent of the land acquisition cost, are being wrongly classified in a manner that forces us to include these investments in our borrowing limits. We demand that Rs. 6,000 crore be allowed outside regular limits. But, as always, BJP remains deaf to our legitimate requests.

And, what about GST? The BJP claimed that GST would ensure fair revenue distribution, but Kerala has been systematically shortchanged, suffering due to systematic tax evasion and incorrect settlements. We demand continuation of the GST compensation scheme until these flaws are rectified. But, once again, this Government turns away because it knows that Kerala's robust economic model stands as proof of alternative models of development work.

Non-Resident Keralites (NRKs) have sent back millions in remittances, contributing immensely to India's Foreign Exchange reserves. Yet, their welfare board is struggling due to rising return migration and the Centre refuses to allocate even Rs. 300 crore annually to sustain it. At the same time, Kerala's proposals for migrant reintegration worth Rs. 2,000 crore have been ignored. Why? It is because BJP sees migrants only as ATM machines, not as human beings.

Hon. Vice-Chairman, Sir, this Government has given Rs. 60,000 crore to upgrade ITIs nationwide. Yet, Kerala's 108 ITIs are denied their rightful share of Rs. 2,100 crore. Our higher education sector has been ignored under PM-USHA despite submitting proposals worth Rs. 2,117 crore. Our cancer patients, at the Regional Cancer Centre in Thiruvananthapuram, are denied Rs. 1,293 crore needed for expansion. Why? It is because Kerala refused to surrender before BJP's communal politics.

Our fisheries sector is struggling, but harbour modernization funds remain elusive. Our coastal communities are fighting for survival against rising sea levels, but Rs. 2329 crore we need is nowhere in sight. We ask for increased subsidies for

essential commodities, support for cashew, coir, handloom sector, fair wages for MGNREGA workers and a much-needed AIIMS in Kerala. And, what is the BJP's response? Silence! Neglect! Contempt!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): अब आप समाप्त करें।

SHRI P.P. SUNEER: This is not governance. This is economic strangulation. This is a political conspiracy to break Kerala's resilience. But, let me and my party, the CPI, be clear--Kerala will not be bullied. Kerala will not bow down. Kerala will fight!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): अब आप समाप्त करें।

SHRI P.P. SUNEER: The people of Kerala can see the BJP's game. We see the contempt of this Government for our social model, our commitments to secularism and our welfare-driven economy. But, let me warn you, Kerala is not alone. The BJP's attacks on federalism are an attack on every non-BJP ruled State. If Kerala is strangled today, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal, Punjab and every progressive State will be next.

Kerala will resist. Kerala will fight. And, Kerala will prevail. The people of India will resist. The people of India will fight. And the people of India will prevail against all injustice. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Shri A.A. Rahim.

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, I thank you for giving me this opportunity. Sir, 'What Kerala thinks today, India thinks tomorrow', words by a popular journalist, Rajdeep Sardesai. Yesterday, I received an answer from the Ministry of Housing and Urban Affairs. My question was about the number of homeless people in urban areas. But, the Minister provided data of 2011. This is the picture of *Viksit Bharat*. The Union Government does not even have updated data beyond 2011. The number is so alarming. So, the Government is afraid to even disclose it.

Sir, I can proudly say that Kerala, under the leadership of Chief Minister, Comrade Pinarayi Vijayan, has built over 4,27,736 houses for the poor and homeless till this January. I am proud to say that this is the Kerala tradition. This is the Left's alternative. Even the Union Government chooses to neglect us. Kerala continues to lead the way in public welfare and social justice. The Union Government is completely neglecting the State of Kerala. Despite your financial sanction against Kerala, while

the country's economic growth rate is struggling at 6.4 per cent, Kerala is soaring ahead at 7.2 per cent; I can proudly say here. What Kerala thinks today, India thinks tomorrow! Come to the literacy rate. According to the Ministry of Statistics and Programme Implementation, the national literacy rate stands at 86.2 per cent. Please look at Gujarat. The literacy rate is 78.03 per cent. Look at the double engine *sarkaar* of Uttar Pradesh, it is 67.68 per cent. In Rajasthan, it is 66.1 per cent, but look at Kerala. We, the people of Kerala, declared total literacy way back in 1991. What Kerala thinks today, India thinks tomorrow! Sir, please look at me. With regard to the broadband connections in schools, in this Budget speech, the Finance Minister allocated funds for broadband connections in schools. But, every school in Kerala already has internet connectivity. In Kerala, more than 45,000 classrooms are digitalized. A vast majority of our schools have now become high-tech between 2016 to 2024. What the Finance Minister announced this year, we started earlier. Kerala is the only one State, which declared the right to internet as the Fundamental Right to all. What Kerala thinks today, India thinks tomorrow! This is our Kerala. Sir, start-up of Kerala has been recognised as the best performer in the fourth edition of the States' Start-Up Ranking, 2022 of the Union Ministry. This is our Kerala. Sir, I would like to proudly say in this House that on 1st November this year, we will make an historic announcement that all India can be proud of. Kerala will become the first State in India to eradicate extreme poverty from this landscape. Sir, this is Kerala. What Kerala thinks today, India thinks tomorrow! Building on these remarkable achievements, we are moving to the next level of growth and development across every sphere of life, however, the Union Government through unjust action and unfair tactics is deliberately obstructing our progress, hindering Kerala's rightful path to prosperity. Sir, the Union Budget is totally disappointing. According to the country's Economic Review report, economic growth is 6.4 per cent. We could see a significant decline from 8.1 per cent. How to enhance the purchasing capacity? This is the question before us. Sir, 29 per cent of the Indian population comprises young men and women. India has the largest workforce in the world. Yet most of them do not have enough money to spend in the market. This is the problem. Paragraph 12.9 of the Economic Survey Report confirms that regular salaried jobs have declined from 22.8 per cent to 21.7 per cent. Meanwhile, corporate profit has increased by 22.3 per cent, which means that stable salaried jobs are declining here. Despite soaring corporate profits, employees' salaries are not increasing. This is the phenomenon.

Sir, now, our India, a country where the cost of living is soaring, a country where stable, well-paying jobs are disappearing, a country where young professionals face wage stagnation, where people are forced to take loans just to

survive. Yet, this Budget proposes nothing significant to address this common and grave issue. Sir, now, I come to work-life balance. This is very serious. Sir, I am coming from Kerala. I am representing Kerala. A tragic death of Anna Sebastian, a young woman from Ernakulam, Kerala, who worked at the multinational firm, Ernst & Young, happened due to the work-related stress. Sir, this shook the entire nation. She is not only one. Many young professionals suffer immense mental stress due to exploitive working conditions. Yet, what does this year's Economic Survey Report proposes! Increase working hours! Allow up to 144 hours overtime per quarter! This is the proposal of Economic Survey. Sir, this policy has already been implemented in some of the States. I would not like to take the name of that State. Sir, this is not an opportunity for better earning. This is an opportunity for corporate to exploit young workers. The Union Government is imposing more work, more stress and more exploitation on Indian youth. Instead of ensuring fair wages, they are forcing workers to take excessive overtime. The Modi Government is not protecting workers, not protecting the spirit of young women and men. I am going to conclude, Sir. It is enabling modern slavery. So, right to disconnect is a right to young men and young women. This is very important, Sir. I am going to conclude. The illusion that income tax exemption will boost middleclass purchasing power is foolish. Sir, the true economic progress of the country will come only by increasing wages and purchasing power for vast majority of the workforce, including youth. The Modi Government has failed to address the real concerns of India's citizens. It is the time for the Government that prioritises people over corporates. Thank you very much, Sir.

डा. अजित माधवराव गोपछड़े (महाराष्ट्र): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं विश्व के नेता तथा हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ तथा इस बजट का मजबूत समर्थन करना चाहता हूँ।

महोदय, हमारे सदन में ऑस्कर फिल्मों के अर्थ संकल्प को जोड़कर कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई है। हमारे एक बहुत ही विद्वान साथी प्रतिपक्ष में बैठते हैं, मैं हमेशा उनकी बातें सुनता हूँ। हमारे हिंदुस्तान की जनता ऑस्कर फिल्म बहुत कम देखती है। जनता को अपने सुख-दुःख और अपने इर्द-गिर्द होने वाली घटनाओं पर आधारित फिल्में देखने में ज्यादा आनंद मिलता है। सर, मेरे पास चूंकि समय बहुत कम है, नहीं तो मैं उनकी पूरी 12 फिल्मों का भी चिंतन कर पाता। मैं भी जनता के दिलों में बसी हिंदुस्तान की मशहूर फिल्मों को इस बजट के साथ जोड़ना चाहता हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, चार-पांच दशकों से शोले फिल्म हिंदुस्तान की जनता के दिलों पर राज कर रही है। उसका खलनायक गब्बर सिंह और उसकी टोली रामगढ़ और उसके आसपास गांवों में लूटपाट, दहशत और उत्पात मचाते हैं। इससे वहां की पूरी जनता त्रस्त होती है, वह भयंकर भय और त्रासदी में होती है। इसी प्रकार का वातावरण 2014 से पहले गब्बर सिंह और उसकी टोली का इस देश में था। उसमें सांबा भी था, कालिया भी था और ऐसे बहुत सारे सरदार

थे। तब उस इलाके में जय और वीरू आते हैं और इस गब्बर सिंह का उत्पात खत्म करते हैं। उसके बाद, पूरी जनता जनार्दन उनको अपने सिर पर लेकर घूमती है, झूमती है। 2014 के बाद हमारे देश में यशस्वी प्रधान मंत्री, मोदी जी की सरकार ने अमन, शांति और समृद्धि की अनमोल भेंट हिंदुस्तान को इस बजट के माध्यम से महिला, किसान, युवा, वंचित, पीड़ित, शोषित और सारे विश्वकर्मा समाज को देकर महासत्ता होने की दिशा में पहल की है। हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने गब्बर टैक्स बंद करके देश में गब्बर सिंह जैसे लूटपाट और भ्रष्टाचार करने वालों को परास्त करके इस देश की महासत्ता को आगे लेकर जाने का एक सफल प्रयास किया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 1986 में "कर्मा" नाम की एक बहुत मशहूर फिल्म आई थी। उसमें डॉक्टर डैंग नाम का एक टेररिस्ट, मुख्य गुंडा पकड़ा जाता है। वह जेल में हमारे देश के अधिकारी को अपमानित करता है, तब उसको करारा झापड़ देशभक्त दिलीप कुमार जी लगाते हैं।

5.00 P.M.

उसके इलाके में घुसकर उसके साम्राज्य का खात्मा कर देते हैं। इसी प्रकार से माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे दुश्मन देश में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके देश के दुश्मनों के मुंह पर एक करारा झापड़ लगाया है। हमारी वित्त मंत्री जी ने रक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाकर दुनिया के सामने एक मज़बूत देश के रूप में हमें सामने लाई हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 1975 में 'दीवार' नामक फिल्म आई थी। वह जनता के दिल पर राज कर गई। उसमें दो मशहूर कलाकारों का संवाद है। एक कलाकार कहता है, "मेरे पास संपत्ति है, गाड़ी है, नौकर है, बंगला है, सब कुछ है" तो दूसरा कलाकार कहता है, "तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर मेरे पास मां है।" माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संपूर्ण भारत के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार समझकर जनता जनार्दन को 12 लाख रुपये की आय पर कोई आयकर न देने का प्रावधान किया है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इस तरह मोदी जी और वित्त मंत्री जी ने 140 करोड़ जनता को अपना परिवार समझ कर इस देश को एक भेंट दी है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1970 में पूरब और पश्चिम नाम की एक मनोज कुमार जी की फिल्म आई थी, जिसमें "प्रीत जहां की रीत सदा मैं, गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं।"

आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 'ज्ञान भारत मिशन' के माध्यम से डिजिटलाइज़ेशन, संस्कृति और ज्ञान का वैश्विक प्रचार किया है। भारत की सांस्कृतिक परम्परा, दर्शन, वेद, उपनिषद, तक्षशिला, नालंदा जैसे प्राचीन ज्ञान केंद्रों को फिर से ज़िन्दा किया है। प्रधानमंत्री जी ने "वसुधैव कुटुंबकम्" का नारा दिया है। आधुनिक तकनीक से भारत को सुरक्षित करके पूरी दुनिया को दिखाने का काम माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। अभी यह पुराना भारत नहीं रहा है, अभी यह नया भारत है, इसलिए "भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं।" हमारे युवा, किसान और गरीब, सब मिलकर इस गाने को दोहरा रहे हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, उन्होंने लगान फिल्म का ज़िक्र किया। जिसमें आमिर खान जी अपने गाँव में अंग्रेज़ों की गुलामी से बचने के लिए सारे जाति, पंथ, भाषा, दिव्यांग, पिछड़े वर्ग, वंचित, शोषित, सबको साथ लेकर क्रिकेट मैच में अंग्रेज़ दुश्मनों को हरा देते हैं। उसी तरह माननीय मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से सारे लोगों को साथ लेकर और 'सबका साथ, सबका विकास' की घोषणा करके दुनिया में यह साबित कर दिया है कि यह अर्थ संकल्प हमारे देश का फ़ख्र होना चाहिए। यह अर्थ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है।

महोदय, 'उपकार' फिल्म में मनोज कुमार जी का गाना है "मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती।" हमारी इन नीतियों का प्रभाव केवल कागज़ों की ओर नहीं है, बल्कि भारत के गाँव का चेहरा-मोहरा भी बदल दिया है। हर एक किसान अपने खेत में खड़ा होगा। हमारा बजट सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि गांव, गरीब, किसान के जीवन को समृद्ध बनाने का एक मिशन बन चुका है। 'उपकार' फिल्म का गाना किसान तब भी गाते थे, लेकिन अब फसल बढ़ गई है, साथ ही किसानों के जीवन में एक नई संजीवनी लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हमारे ग्राम स्वराज्य को विश्व गुरु तक ले जाने में हमारे मोदी जी सहायक हुए हैं। मैं मोदी जी और वित्त मंत्री जी को मन से सलाम करता हूं। प्रधान मंत्री जी ने युवाओं के लिए भी बहुत कुछ किया है।

महोदय, 90 के दशक में "कयामत से कयामत तक" फिल्म आई थी। उसमें एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था "पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।" आज हमारे युवा केवल 9 बजे से 5 बजे तक की नौकरी के पीछे भागना नहीं चाहते, बल्कि वे उद्यमी बनाना चाहते हैं। स्टार्टअप और उद्यमियों को बढ़ावा दे कर योजनाओं को प्रस्तुत किया है, जिसमें स्टार्टअप योजना, डीप टेक फंड ऑफ फंड्स, निर्यात प्रोत्साहन अभियान, स्टार्टअप की क्रेडिट सीमा, MSME की निर्यात सहायता, हवाई कार्गो का सुधार, इसी तरह से हमारा देश युवाओं के लिए रोज़गार देने वाला देश है। जो युवा है, वह नौकरियों के लिए नहीं भटकेगा, वह खुद सबको नौकरी देगा और एक पिता भी अपने बेटे के बारे में बोलेगा कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 1967 में 'एन इवनिग इन पेरिस' फिल्म आयी थी। उस फिल्म में एक प्रसिद्ध गाना था "आओ तुमको दिखलाऊं लंदन और पेरिस की रंगीन शाम" यह हमारे कांग्रेस के प्रधान मंत्री भी जब बताते थे, लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी ने वैश्विक शहरों के मुकाबले में आर्थिक क्लस्टर, एमएमआरडीए (MMRDA), बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो ट्रेनों का विस्तार, कोस्टल रोड, हाई-टेक सिटी प्लानिंग जैसी चीज़ें करके नए शहरों का आधुनिकीकरण, सौदर्यीकरण, वैश्वीकरण और इंटरनेशनल टूरिज़्म का वैश्विक स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करके अब हमें हमारे परिवार को पेरिस और लंदन ले जाने की ज़रुरत नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने इस देश को इतना बड़ा और इतना अच्छा बनाया है कि हम हमारे परिवार को लेकर भारत के सुंदर शहरों में पर्यटन कर सकते हैं। अब हम हमारे परिवार को कह सकते हैं कि आओ तुमको दिखलाऊंगा एन ईवनिंग इन इंडिया की शाम। मैं प्रधान मंत्री जी का मन से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन इसमें अभी दो-तीन फिल्में और बाकी हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, 2014 में मोदी जी

...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्य, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं...

डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः सर, मेरा समय जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपका समय नहीं जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सदन में कहानी कहना, कविता सुनाना और फिल्मों की ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बात कह सकते हैं।

डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः सर, मैं सुधार करता हूं। वर्ष 2014 में मोदी जी की सरकार आई, वह बाहुबली 1 की तरह थी। बाहुबली 1 की नई शुरुआत संघर्ष भरी थी, लेकिन एक बड़े विजन के साथ बाहुबली ने जैसे माहिष्मती को न्याय देने के लिए संघर्ष किया, वैसे ही मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत, जन-धन योजना, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से देश को नई दिशा दी, लेकिन चुनौतियों की भी कमी नहीं थी। विरोधी ताकतें, आर्थिक समस्याएं और प्रशासनिक सुधार की जरूरत थी। वर्ष 2019 में मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई। यह बाहुबली 2 की तरह थी। जब और भी मजबूत सरकार बन गई। बाहुबली 2 में हमने देश को आत्मनिर्भर बनाया। बाहुबली ने जैसा अपना असली हक पाया, माहिष्मती को न्याय दिलाया, वैसे ही मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत, धारा 370, राम मंदिर का निर्माण, किसान योजनाएं और कोविड वैक्सीन जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए। जिस तरह बाहुबली का विजन सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि पूरे राज्य का कल्याण करना था, वैसे ही मोदी सरकार भी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए काम कर रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, भविष्य के भारत के स्वर्णिम युग में 2047 तक ऐसी कई बाहुबली फिल्में आएंगी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत को महासत्ता बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। यह मैं यहां पर सभा के मंच में आप सब लोगों को कहना चाहता हूं। आपने बोला है कि फिल्मों का नाम मत लीजिए, कविता मत बोलिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिदम्बरम जी ने निर्मला जी को बोला है कि 2014 में कर में दो लाख रुपये की छूट थी, 2025 में 12 लाख की छूट दी गई। वर्ष 2014 से पहले बैंक का एनपीए 11 परसेंट था, 2024 में 0.6 परसेंट है। 2014 से पहले इन्फ्रा पर 1.57 लाख कोटी खर्च हुए थे और 2025-26 में 55 लाख करोड़ रुपये हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। अगर मैं संपत्ति के निर्माण की बात करूं, तो 2014 से पहले 13 लाख करोड़ था, अभी 2024 में 310 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का हमने निर्माण किया है। मैं FOREX addition के बारे में बोलना चाहता हूं, जिसको Foreign Exchange addition बोलते हैं, 2014 में 50 डॉलर अब्ज था, अभी 2024 में 350 अब्ज डॉलर हुआ है। 2014 में जीडीपी की रैंक 10वें नंबर पर थी, अभी उसके बाद हम 5वें नंबर पर आए हैं। सर, मैं आखिरी पैरा पर आ रहा हूं। 2014 में गब्बर सिंह के घोटालों के बारे में बोला गया था। वर्ष 2014 में बड़े-बड़े 78 घोटाले, छोटे-छोटे तो बहुत सारे हैं, 2024 के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ है। इस तरह से मैं अभिमान के तौर पर निर्मला सीतारमण जी को देश की सर्वोत्तम अर्थमंत्री बोलना चाहता हूं। मैं प्रधान मंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि उन्होंने पोस्ट कोविड, कोविड के बाद सारे देश गिर गए ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप समाप्त कीजिए।

डा. अजित माधवराव गोपछड़े: कोविड के बाद मोदी जी ने भारत को संभाला। इसलिए मैं माननीय मोदी जी का और निर्मला जी का अंतकरण से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL (Maharashtra): Sir, the Budget 2025, presented by the Finance Minister, is a clear example of the Government's misplaced priorities. This Budget has neglected the most pressing issues facing our nation such as unemployment, farmers' distress and rising cost of living. The lack of attention to these critical areas is a stark reminder of the Government's disconnect from the common man. Although the Finance Minister was mentioning the agricultural sector as the first engine of growth, the allocation for the agricultural schemes has seen a dip. The allocation to the Department of Agriculture and Farmers' Welfare has come down by Rs. 3,905/- crores from the Revised Estimates of 2024-25.

For Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Crop Insurance Scheme, the allocation this time has dropped by Rs. 3,621.73 crore. It has got Rs. 12,242.27 crore this time against Rs. 15,864 crore for the last Revised Estimates. The allocations for the Fertilizers Departments have also been cut by Rs. 26,500.25 crores. The Budget neglected the demand for legalized Minimum Support Price, MSP, which we are demanding time and again, legalized MSP, by Dr. M.S. Swaminathan's formula and a comprehensive scheme to waive farm loans.

The National Mission on Oilseeds does not find a mention in the agriculture budget figures and merely Rs. 1,000 crore has been allocated for the Mission for Pulses. The allocation for food subsidy is also more or less the same as last year, Rs. 2 lakh crore, indicating that there is no hope of pulses or oils being included in the Public Distribution System, PDS. This could have offered stable and affordable prices for consumers, allowing them to spend their income on other items. Even, the MGNREGS, which is a very prestigious Scheme of the UPA Government, also remains stagnant at Rs. 86,000 crore despite demands from workers' unions and also the corporate sector for an increase of wages under the Scheme.

Much was said in the Budget speech on the new crop-based missions but the allocations for these are minimum. The allocation for the Cotton Technology Mission is only Rs. 500 crore, the Mission for Pulses is Rs. 1,000 crore, the Mission for Vegetables and Fruits is Rs. 500 crores and the National Mission on Hybrid Seeds is Rs. 100 crores. A new Makhana Board, which is established recently with an allocation of Rs. 100 crores, has been announced for Bihar. But the already-existing Commodity Boards are cash-strapped. उनके पास पैसा नहीं है। For example, between

2024-25 and 2025-26, allocation for the Coffee Board -- especially for Karnataka and Kerala people, I would like to say it -- has remained unchanged, the Rubber Board's allocation has risen by just Rs. 40 crore and allocation for the Spice Board has risen by just Rs. 24 crores. Allocation for the Coconut Development Board has been cut from Rs. 39 crore in 2023-24 to Rs. 35 crores in 2025-26.

While the Budget speech mentioned 'agriculture' several times but it hardly matched the financial allocation. वे सिर्फ बोलते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। उनके खाने के दाँत अलग हैं और दिखाने के दाँत अलग हैं। The schemes and the programmes are starved of resources and the real issue that confronts the farmers and the sector remains sidelined. Further, the Economic Survey admits that the real wages have not risen for 80 per cent of workers in the last five years -- this is what the PLFS says -- but still claims that jobs have grown. So, it is rather a contradictory conclusion. The September 2024 Report of the Periodic Labour Force Survey revealed that in 2023-24, the youth unemployment rate for those aged 15-29 years had increased by 10.2 per cent and unemployment rate among graduates was 13 per cent. This is a matter of shame because youngsters, all young force, in our country are without work and they are without jobs. For a country that adds 60 to 70 lakhs new job-seekers each year, a country that has 46 per cent of its workforce now in agriculture, majorly as disguised unemployment, a country that has 10 crore youth [Not in education, employment or training] and about 25 crore unemployed, the Budget does not seem to address the challenges of the job-creation.

Thus, we demand a more comprehensive approach for addressing the nation's problem rather than just providing tokenistic relief and talking about the movies. We need a Budget that prioritizes our needs, the needs of the common man, boosts employment and entrepreneurship and addresses the critical issues facing our nation. सर, अब मैं थोड़े शब्द हिंदी में बोलना चाहूँगी। मैं आपके समक्ष हिंदी में बात करना चाहती हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मुझे दोनों भाषाएं समझ में आती हैं।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल: वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार के लिए नारी चार समूहों में से एक फोकस है। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तस्वीर देखें, तो श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, पुरुषों और महिलाओं की ग्रामीण वास्तविक आय के कारण महिलाओं को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, पुरुषों और महिलाओं की वास्तविक मासिक आय में गिरावट आई है। यह बजट महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद है, इसका विश्लेषण करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है।

सर, बजट आवंटन में कमी - सबसे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ तीन प्रतिशत की वृद्धि की है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए 2024-25 में दिए गए 21,200 करोड़ को बढ़ाकर, 21,960, यानी सिर्फ 500, 700 करोड़ रुपये का बढ़ावा दिया है, जबकि हमारे देश में महिलाओं और बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

अगर जेंडर बजट की बात करें, तो वर्तमान वर्ष में वह 1,12,396 करोड़ रुपए से घटकर 1,05,535 करोड़ हो गया है। इस गिरावट का असर पीएम आवास योजना – शहरी, गरीब परिवार के लिए योजना, एलपीजी कनेक्शन के बजट पर भी पड़ा है। वर्तमान वर्ष की तुलना में पीएम आवास योजना ग्रामीण या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के बजट में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। महिलाओं के लिए जल जीवन मिशन में भी आवंटन कम कर दिया है। जल जीवन मिशन में महिलाओं के लिए 31 प्रतिशत आवंटन निर्धारित किया है, जबकि पिछले दो वित्तीय वर्षों में वह 49 परसेंट था। हम 49 परसेंट से 31 परसेंट तक आ गए हैं। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन यह आवंटन महिलाओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करने की दिशा में बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में महिलाओं के लिए कम आवंटन है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यह सुनिश्चित करती है कि 100 परसेंट आवंटन महिलाओं को निर्देशित हों, ताकि सभी घर महिलाओं के नाम पर हो जाएं। हालांकि, योजना शुरू होने के बाद, हमने सरकारी डेटा देखा, तो 1 फरवरी, 2025 में केवल 23 परसेंट घर महिलाओं के नाम पर हो गए थे। यह दुर्भाग्य की बात है। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को बजट से हटा दिया गया है और इसके लिए कोई भी आवंटन नहीं रखा गया है। यह बहुत ही बुरी बात है, गंभीर चिंता का विषय है और यह महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है। कुल मिलाकर, बजट में महिलाओं के लिए बहुत कम लाभ है।

सर, एक बात यह बताना चाहती हूँ कि चार-पाँच दिन पहले मैं और सागरिका घोष जी बात कर रहे थे कि हमें किस विषय पर बोलना है। यहाँ पर जो हमारी साथी हैं, हमारी मित्र हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस विषय पर बोलेंगी, तो मैंने बोला कि मैंने बजट के ऊपर तो कभी बोला नहीं है। इस बार तैयारी करके बोलूँगी, तो हमारे एक दूसरे साथी हैं, उन्होंने वहाँ आकर बोला कि इस पर क्या बोलना है। अगर महिलाओं को बजट पर बोलना है, तो किचन के लिए बोलिए। हम दोनों स्तंभित हो गए कि अगर एक हमारा साथी सांसद हमारे जैसी महिला सांसद से इस तरह से बातें करता है कि आप सिर्फ किचन के ऊपर बोलिए, तो इसका क्या मतलब होता है। सर, यहाँ कुर्सी पर महिलाएं भी बैठती हैं। हमारी वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने महिला होते हुए भी लगातार आठवां बजट पेश किया है। हमारी नेता सोनिया जी हैं। उनकी नेता ममता बनर्जी जी हैं। इस देश की प्रधान मंत्री, इंदिरा जी हुई हैं, तब भी आप बोलते हैं कि महिला है, तो किचन के लिए बोलिए। हमें कितना प्रूव करना होगा और कितनी बार प्रूव करना होगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): माननीय सदस्या, इस समय तो हम महामहिम द्रौपदी मुर्मू और निर्मला सीतारमण जी पर ही चर्चा कर रहे हैं।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः सर, मैं तो निर्मला जी की सराहना ही कर रही हूँ। निर्मला ताई के लिए ही बोल रही हूँ। सर, मैं सिर्फ मानसिकता दर्शाती हूँ। यह महिलाओं के लिए पुरुषों की मानसिकता दर्शाती है कि अगर हम यहाँ पर भी आ गए, तो भी हमें नीचे देखने की जो मानसिकता है, वह कम होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)... इसमें कोई दायां-बायां नहीं है, सब की सेम मानसिकता है। जब तक महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता, तब तक वह पूर्णतः स्वयंपूर्ण हो गई, ऐसा हम नहीं मानते हैं। 1992 में 73वाँ और 74वाँ अमेंडमेंट किया गया था। हमारे नेता, राजीव गाँधी जी के विज़न से हमारे देश में पंचायत राज के माध्यम से 33 परसेंट आरक्षण लागू हो गया था। मुझे गर्व है कि उस पंचायती राज के बिल के माध्यम से मैं जिला परिषद् से लेकर यहां संसद तक आ सकी। इसका अगर श्रेय जाता है, तो उस बिल को जाता है, जिसमें हम महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, उसका श्रेय हमारे नेताओं को जाता है, चाहे वे सोनिया जी हों या राजीव जी हों। इन्होंने हमें यह अवसर पहली बार दिया। यह सरकार भी बिल लाई है। ...(**व्यवधान**)... मैं भी यही बताने वाली हूं। यह सरकार भी बिल लाई है। वह महिला आरक्षण बिल नहीं है, वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। सर, यह तो बीरबल की खिचड़ी पकाने वाली बात है। ...(**व्यवधान**)... सर, यह बिल आ गया, पास भी हो गया, लेकिन सेन्सस कब होगा, फिर डीलिमिटेशन कब होगा? उसके बाद में बिल कब लागू होगा? हमारी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण कब मिलेगा? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए नारी शक्ति वंदन अगर लागू करना है, तो तुरंत सेन्सस करवाएं। जैसे हमारे नेता राहुल जी ने बोला है – जातिवार, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी - आप जातिवार जनगणना कराएं और हमारी महिलाओं और बाकी सभी जातियों को उनका अधिकार दें, जिससे समाज के हर क्षेत्र में अच्छी तरह से पावर बांटी जाए।

मैं निर्मला ताई से अनुरोध करूंगी कि इस बजट में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए प्रावधान करने की कोशिश करें। धन्यवाद, जय हिंद!

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद। श्री साना सतीश बाबू। आपकी मेडन स्पीच है। आप बोलिए।

SHRI SANA SATHISH BABU (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for the opportunity to speak in this esteemed House. I thank the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, for presenting the Budget to strengthen India's economic foundation. As India is set to contribute 15 per cent of the global growth between 2024 and 2029, this Budget aligns with hon. Prime Minister Narendra Modi's vision for the self-reliant and developed India by 2047. Andhra Pradesh contributes nearly 4.7 per cent to India's GDP under the leadership of our hon. Chief Minister, Nara Chandrababu Naidu garu and this percentage will further increase. Our State is making remarkable advancement, attracting Rs.4 lakh crore worth of investments in just seven months. There are notable investments, such as Rs.9,500 crores in BPCL refinery, Rs.5,000 crores in industrial nodes, that is, Vizag-Chennai corridor and Rs.1.8 lakh crore of investments in green hydrogen hub. A lot of private investments

by Arcelor Mittal and TCS are coming up. In just seven months, our Government has secured funds from the Central Government for projects – Rs.1,500 crores for Amaravati Capital development, Rs.12,000 crores for the Polavaram Irrigation Project and Rs.11,440 crores for Vizag-Steel plant. However, under the previous Government, the economy of Andhra Pradesh was destroyed, the administration collapsed and the State was ...*(Interruptions)*...

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: *

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया, आप बैठ जाइए। मेडन स्पीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ...(**व्यवधान**)... कृपया, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आपकी बात अंकित नहीं होगी। आप कृपया बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA: This is the maiden speech of hon. Member. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मस्तान राव साहब, कृपया आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य, आमतौर पर मेडन स्पीच में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है। आप शांत रहिए और उनको सुनिए। ...(**व्यवधान**)... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANA SATHISH BABU: I would like to answer the baseless rumours spread by the Opposition Lok Sabha MP in my State. Firstly, in Polavaram Project, for the last five years, nothing was done by the previous Government. ...*(Interruptions)*... Sir, this is not fair on the part of the hon. Member. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Nothing is going on record. Please sit down. ...*(Interruptions)*... मस्तान जी, आप भी बैठ जाइए। आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए। यह गलत है। Maiden speech में disturb करना बिल्कुल गलत है। सदन के नियम और परंपराएँ हैं। आप बोलिए।

SHRI SANA SATHISH BABU: The TDP Government, between 2014 and 2019, had completed 72 per cent of the Polavaram Project. Now, with the support of the Central Government, commitment for sanction of Rs.12,000 crore has been made. During the last five years, nothing was moved. Rs.8,000 crores were taken by them from the

* *Not recorded.*

Central Government but nothing moved in the Polavaram Project. The previous Chief Minister did not visit the Polavaram Project site even once. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आपको सुनना ही होगा। यहाँ आलोचना-प्रत्यालोचना सुनने के लिए ही हम बैठते हैं। कृपया बैठे रहिए। ...(**व्यवधान**)... Don't disturb. ...*(Interruptions)*... यह अंकित नहीं होगा। ...(**व्यवधान**)... यह अंकित नहीं होगा। मैं आपको allow नहीं कर रहा हूँ। कृपया बैठ जाएँ। आप मर्यादाओं को नहीं तोड़ें। आप बोलिए।

SHRI SANA SATHISH BABU: Now the present Chief Minister, Chandrababu Naidu Garu, has visited the project site five times in the last seven months and every Monday, he reviews the progress of the project. Under the leadership of Chandrababu Naidu Garu, Polavaram will no longer be a victim of neglect. It will be a symbol of Andhra Pradesh's progress.

Now, regarding Amaravati, we have got the support of the Central Government and it has allotted Rs.15,000 crore for the development of Amaravati. During the last five years, there was no Capital for Andhra Pradesh. The people of Andhra Pradesh felt ashamed because of this. Even after the High Court's directions, there was no Capital for Andhra Pradesh. Still, the former Chief Minister was thinking about three Capitals. Anyway, now, at the initiative of the present Chief Minister, 28,000 farmers have given their land for the new Capital. We are building India's first Greenfield Smart City Capital of Amaravati.

Now, I will talk about the Vizag Steel Plant. In the last five years, the privatisation issue was there. Now, after the NDA Government came again in power, we have secured Rs.11,400 crore allocation for the revival of the Vizag Steel Plant. Yet, YSRCP MPs are saying that the plant will be privatized. If the Government wanted to sell it, why would it invest such a massive amount to revive it? Adding to that, the Union Minister for Steel has clearly stated that the Centre has no plans to privatize it. As per the NITI Aayog report, the previous State Government reduced Andhra's revenue growth from 17.1 per cent to 9.8 per cent. ...*(Interruptions)*...

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please sit down.

---

* *Not recorded.*

SHRI SANA SATHISH BABU: On the other hand, they had exhausted Rs.30,497 crore in revenue deficit grants. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Nothing is going on record. यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... बिना मेरी अनुमति के कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आप बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... कृपया बैठ जाएँ। इनका कोई भी वाक्य रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

SHRI SANA SATHISH BABU: Funds which were meant for five years, they spent them within three years. They had just crippled the State finances and exposed their inefficiency. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): खड़े होकर बोलने की अनुमति नहीं है और बैठे-बैठे आप बोलेंगे नहीं।

SHRI SANA SATHISH BABU: Sir, I am not from the same party. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़, आप बैठें। ...(**व्यवधान**)... कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SANA SATHISH BABU: Sir, I am explaining as to how the State was crippled. In the last five years, whatever liquor scam they have done in the State...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): यह ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा हो गया है। कृपया बैठ जाएँ। मैं आपको warning दे रहा हूँ। आप बैठ जाएँ।

SHRI SANA SATHISH BABU: In the last five years, ...*(Interruptions)*...: We have evidence. The investigation is going on. We have evidence. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): यहाँ हम सुनने और बोलने के लिए बैठे हैं। कृपया बैठ जाएँ और सुनें। ...(**व्यवधान**)... It is not going on record. ...*(Interruptions)*... कृपया आप बैठ जाएँ और सुनें। ...(**व्यवधान**)... आप इनका समय मत लीजिए। आप बोलिए।

SHRI SANA SATISH BABU: Sir, Rs. 20,000 crores have been siphoned off. In Delhi, the revenue loss on account of liquor scam may be Rs. 2,000 crores, and, here, it is a scam of 20,000 crores of rupees... ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप कृपया बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... आप यह चर्चा नहीं करेंगे। ...(**व्यवधान**)... आप यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। मैं बताता हूं। ...(**व्यवधान**)... Yes. राज्यों के विकास के बारे में ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... Please sit down. मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं। ...(**व्यवधान**)... यह नहीं चलेगा। यह बिल्कुल नहीं चलेगा। आप बोलिए, आप राज्यों के विकास के बारे में बोलिए, राज्यों को भारत सरकार से पैसा देने के मामले में, राज्य के लिए माँग करने के बारे में बोल सकते हैं।

SHRI SANA SATISH BABU: Sir, Andhra Pradesh has the largest coastline after Gujarat. We have 937 kilometres coastline. Still, we lack ports, which have not been developed in the last 10-15 years. There is one more thing. Kakinada is my own place. Still, there is a scope for shipbuilding yard at Kakinada. Uppada-Kakinada road, a 20 kilometre stretch, is rapidly eroding due to shoreline erosion but no one is taking it up. I request the Central Government to allot Rs. 200 crores from the National Disaster Management Funds for constructing a protective sea wall with tetrapods to safeguard the region.

Sir, in the last Budget, under the PRASAD scheme, the Central Government sanctioned Rs. 50 crore for the Annavaram Temple. Actually, we want to develop a separate Greenfield road from Annavaram to Kakinada port, for which we request fund allocation in the Budget.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

Sir, with the unwavering support of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, and hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, Chandrababu Naidu *garu* is taking steps for the development of the State.

In the end, I would say that Andhra Pradesh is on the path to become a $2.5 trillion economy by 2047 but we need continued support from the Centre to achieve this target. Under the able leadership of Chandrababu Naidu *garu* and with strategic planning and collaboration, Andhra Pradesh is set to achieve new benchmarks of development. We will not just rebuild our State, but we will be the torchbearer of India's growth story. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Next speaker is, Dr. Fauzia Khan.

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, इस वर्ष के अर्थ संकल्प को देखकर सांप-सीढ़ी का खेल याद आ रहा है। Snakes and Ladders. इसमें सारा खेल आंकड़ों का है। कहीं आंकड़े चढ़ते हैं, कहीं आंकड़े गिरते हैं। एक तरफ हमारा सामान्य गरीब नागरिक सपनों की

आशाओं की जगमगाती सीढियां चढ़ता है, तो खुश हो जाता है और कुछ भी पल में निराशा भरे वास्तव के काले-काले सांप उसे निगल जाते हैं और यह आंकड़ों का खेल इसी तरह चलता रहता है।

सर, जब कोई मध्यमवर्गीय व्यक्ति खुशी-खुशी टैक्स में बचत की सीढ़ी चढ़कर, टैक्स से बचे पैसे लेकर बाजार में जाता है, तो वहां जीएसटी के, महंगाई के, फैले हुए भ्रष्टाचार के काले-काले सांप उसको नजर आते हैं। यह वास्तव है और ये वास्तव के साँप हैं। विद्यार्थी जब डिग्री लेकर, सीढ़ी चढ़कर, नौकरी ढूंढ़ने के लिए जाता है, तो unemployable होने के, नौकरी के लिए अयोग्य होने के साँप उसे निगल जाते हैं।

सर, इंडिया स्किल्स की रिपोर्ट कहती है कि 51.25 per cent graduates are not competent to be employed. हमारे पास इतने unemployable youths हैं। स्कूल तो हैं, कॉलेजेज़ तो हैं, पर दर्जा कहां है, क्वालिटी कहां है? एनईपपी यह रिकमेंड करती है कि जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, लेकिन 2017 से 2024 तक हम क्या प्रावधान कर रहे हैं? We are constantly giving between 2.7 per cent to 2.9 per cent. सर, दर्जा कहां से आएगा? न टॉयलेट्स हैं, न कंप्यूटर्स हैं, न हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर है। ASER की रिपोर्ट कहती है कि हमारे क्लास फाइव के 48 परसेंट बच्चे क्लास टू के टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं, 75 परसेंट बच्चे डिवीजन नहीं कर सकते हैं। Approximately, seven lakh teaching posts from class 1 to 8 are lying vacant. यह लोक सभा में दिए हुए रिप्लाई में कहा गया है। Can we have good quality education without good quality teachers?

सर, टीचर ट्रेनिंग बहुत बड़ा साँपों का क्षेत्र है, क्योंकि शिक्षकों के सलेक्शन, एजुकेशन, प्रशिक्षण के लिए जितना प्रावधान होना चाहिए, उतना बिल्कुल नहीं होता है। सर, आजकल एक नया खेल चल रहा है। शिक्षक सरकार की सैलेरी लेता है और अपनी जगह 5-10 हजार रुपए देकर एक दूसरा शिक्षक नियुक्त कर लेता है और स्वयं कोई दूसरा व्यवसाय करता है तथा उसकी जगह एक दूसरा आदमी काम कर रहा होता है। सर, ऐसी चीज के लिए सरकार को कानून लाना चाहिए। यह इतनी भयानक चीज़ है कि इससे हमारा दर्जा बिल्कुल गिर रहा है। देश को विकास की सीढ़ी चढ़ना हो, तो बिना शिक्षा के दर्जे के यह हो ही नहीं सकता है। यहां कटौती करेंगे, तो हम विकसित कैसे बनेंगे? यह मेरा प्रश्न है।

जब हम एक्सपेंडिचर कट्स की बात करते हैं, तो कौन-से विभागों के एक्सपेंडिचर कट किये गए हैं? एजुकेशन के, हेल्थ केयर के, माइनॉरिटी के, ट्राइबल के, सोशल जस्टिस के, 'फसल बीमा योजना' जैसी योजना में कट किया जाता है। सर, 'जल जीवन मिशन' का सिर्फ 41 परसेंट एक्सपेंडिचर हुआ है आज तक। कहते हैं कि पानी हर जगह पहुंच गया है। क्या यह विकसित भारत की सीढ़ियां हैं?

सर, गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री रहते हैं कि जब रुपया गिरता है, तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज हमारा रुपया डॉलर की तुलना में 85.56 हो गया है, तो आज हमारी प्रतिष्ठा को क्या निगल गया है? यह मेरा प्रश्न है। अगर इस सांप-सीढ़ी के खेल में इस देश में कोई पूरी तरह सुरक्षित है, तो वह है कुछ पूंजीपति। ये लोग सीढ़ियों पर सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। आज देश की अधिकतम संपत्ति इनकी अपनी हो गई है।

'फरेब की दुकां पर ईमां बिक रहा है,
चंद सिक्कों के लिए इंसां बिक रहा है,
संभल जाओ अभी वरना कल पता चलेगा
सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां बिक गया है।'

†**ڈاکٹر فوزیہ خان) مہاراشٹر** : (اُپ سبھاپتی مہودے، اس سال کے ارتھ سنکلپ کو دیکھ کر سانپ سیڑی کا کھیل یاد آرہا ہے۔ Snakes and Ladders اس میں سارا کھیل آنکڑوں کا ہے۔ کہیں آنکڑے چڑھتے ہیں، کہیں آنکڑے گرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا عام غریب شہری سپنوں کی آشاؤں کی جگمگاتی سیڑھیاں چڑھتا ہے، تو خوش ہوجاتا ہے اور کچھ بھی پل میں نراشا بھرے واستو کے کالے کالے سانپ اسے نگل جاتے ہیں اور یہ آنکڑوں کا کھیل اسی طرح چلتا رہتا ہے۔

سر، جب کوئی متوسط طبقہ کا آدمی خوشی خوشی ٹیکس میں بچت کی سیڑھی چڑھکر، ٹیکس سے بچے پیسے لیکر بازار میں جاتا ہے، تو وہاں جی ایس ٹی کے، مہنگائی کے، پھیلے ہوئے بھرشٹاچار کے کالے کالے سانپ اس کو نظر آتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت کے سانپ ہیں۔ طالب علم جب ڈگڑی لیکر، سیڑی چڑھکر، نوکری ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، تو بے روزگار ہونے، نوکری کے لیے ناقابل ہونے کے سانپ اسے نگل جاتے ہیں۔

سر، انڈیا اسکلز کی رپورٹ کہتی ہے کہ 51.25 per cent graduates are not competent to be employed. ہمارے پاس اتنے unemployable youths ہیں۔ اسکول تو ہیں، کالجز تو ہیں، پر درجہ کہاں ہے کوالٹی کہاں ہے؟ لیکن 2017 سے 2024 تک ہم کیا پراؤدھان کررہے ہیں؟ We are constantly giving between 2.7 per cent to 2.9 per cent. سر، درجہ کہاں سے آئے گا؟ نہ ٹائلیٹس ہیں، نہ کمپیوٹرس ہیں، نہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے۔ ASER کی رپورٹ کہتی ہے کہ ہمارے کلاس فائیو کے 48 بچے کلاس ٹو کے ٹیکسٹ نہیں پڑھ سکتے ہیں 75 فیصد بچے ڈویژن نہیں کرسکتے ہیں۔ Approximately, seven lakh teaching posts from class 1 to 8 are lying vacant. یہ لوک سبھا میں دیے ہوئے ریپلائی میں کہا گیا ہے۔ Can we have good quality education without good quality teachers?

سر، ٹیچر ٹریننگ بہت بڑا سانپوں کا شیتر ہے، کیوں کہ شکشکوں کے رلیشن، ایجوکیشن، پرشکشن کے لیے جتنا پراؤدھان ہونا چاہئیے، اتنا بلکل نہیں ہوتا ہے۔ سر، آج کل ایک نیا کھیل چل رہا ہے۔ شکشک سرکار کی سیلری لیتا ہے اور اپنی جگہ 5-10 ہزار روپے دیکر ایک دوسرا شکشک مقرر کرلیتا ہے اور خود کوئی دوسرا کام کرتا ہے اور اس کی جگہ ایک دوسرا آدمی کام کررہا ہوتا ہے۔ سر، ایسی چیز کے لیے سرکار کو قانون لانا چاہئیے۔ یہ اتنی بھیانک چیز ہے کہ اس سے ہمارا درجہ بلکل گررہا ہے۔ دیش کو ترقی کی سیڑھی چڑھنا ہو، تو بِنا شکشا کے درجے کے یہ ہوہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں کٹوتی کریں گے، تو ہم ترقی یافتہ کیسے بنیں گے؟ یہ میرا سوال ہے۔

جب ہم ایکسپینڈیچر کٹس کی بات کرتے ہیں، تو کون سے وبھاگوں کے ایکسپینڈیچر کٹ کئے گئے ہیں؟ ایجوکیشن کے، ہیلتھ کئیر کے، مائنارٹی کے، ٹرائبل کے، سوشل جسٹس کے،' سوشل بیما یوجنا 'جیسی یوجنا میں کٹ کیا جاتا ہے۔ سر،' جل جیون مشن 'کا صرف 41 فیصد ایکسپینڈیچر ہوا ہے آج تک۔ کہتے ہیں کہ پانی ہر جگہ پہنچ گیا ہے۔ کیا یہ ترقی یافتہ بھارت کی سیڑھیاں ہیں؟

سر، گجرات کے سابق مکھیہ منتری کہتے ہیں کہ جب روپیہ گرتا ہے، تو دیش کی پرتشٹھا گرتی ہے۔ آج ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلہ میں 85.56 ہو گیا ہے، تو آج ہماری پرتشٹھا کو کیا نگل گیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ اگر اس سانپ سیڑی کے کھیل میں اس دیش میں کوئی پوری طرح محفوظ ہے، تو وہ ہے کچھ پونجی پتی۔ یہ لوگ سیڑھیوں پر سیڑھیاں چڑھتے جارہے ہیں۔ آج دیش کی زیادہ تر جائیداد ان کی اپنی ہوگئی ہے۔

فریب کی دکاں پر ایماں بک رہا ہے،
چند سکوں کے لیے انساں بک رہا ہے،

† Transliteration in Urdu script.

سنبھل جاؤ ابھی ورنا کل پتا چلے گا
سارے جہاں سے اچھا ہندستاں بک گیا ہے۔

Sir, remember, it is not the snake bite that kills. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापतिः कृपया सीट पर बैठ कर बात न करें। ...(**व्यवधान**)...

डा. फौजिया खानः सर, £ और हम नफरतों के खेल खेलने में ही मशगूल हैं। ...(**व्यवधान**)...
Remember, it is not the snake bite that kills.

†**ڈاکٹر فوزیہ خان** : سر، £ اور ہم نفرتوں کےکھیل میں ہی مشغول ہیں۔

श्री उपसभापतिः £ - आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। ...(**व्यवधान**)...

DR. FAUZIA KHAN: But the venom which circulates afterwards is fatal. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

DR. FAUZIA KHAN: I would like to make some policy suggestions.

श्री उपसभापतिः आपका समय खत्म हो गया। ...(**व्यवधान**)...

DR. FAUZIA KHAN: I would like to make some policy suggestions.

श्री उपसभापतिः आपका समय खत्म हो गया। ...(**व्यवधान**)... कृपया अपनी सीट पर बैठ कर न बोलें। आपका समय खत्म हो गया। ...(**व्यवधान**)...कृपया आप कन्क्लूड करें। ...(**व्यवधान**)...

DR. FAUZIA KHAN: Sir, please give me one minute to make some policy suggestions.

श्री उपसभापतिः कृपया आप बैठे-बैठे पीछे से टिप्पणी न करें। ...(**व्यवधान**)...

DR. FAUZIA KHAN: There should be 4 per cent wealth tax on *punjipatis* in the Finance Bill. This is my recommendation.

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

† Transliteration in Urdu script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. FAUZIA KHAN: Yes, Sir. Six per cent of GDP should be allocated to education; 3 per cent of GDP should be allocated to health. Sir, today the common man has lost himself in a maze of mirrors, frantically searching for a way out. (*Time-bell rings.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. माननीय हरीस बीरन जी। ...(**व्यवधान**)... माननीय हरीस बीरन जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)... Just wait a minute. माननीय मंत्री जी।

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्या ने अभी कहा कि 'जल जीवन मिशन' पर मात्र 41 परसेंट एक्सपेंडिचर हुआ है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्या को एक बार आंकड़ों को ठीक से, दुरुस्त तरीके से देखना चाहिए। जब हमने काम प्रारंभ किया था, तब केवल 3 करोड़, 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, जबकि आज 19 करोड़, 24 लाख में से 16 करोड़ घरों में पानी पहुंच रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: सर, यह क्या है? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय जयराम जी, माननीय मंत्री जी उस तथ्य के बारे में बता रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: सर, 3,60,000 करोड़ रुपये के एक्सपेंडिचर की जो सीमा तय की गई थी और जिसका कैबिनट अप्रूवल था, उसका 3,40,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्च हो चुका है। अभी इस बजट में नया प्रोविजन किया गया है और उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है। सर, मुझे लगता है कि आंकड़ों को थोड़ा दुरुस्त करके बोलना चाहिए।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। माननीय श्री हरीस बीरन जी।

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, I stand on behalf of my party, the Indian Union Muslim League, to oppose this anti-people, anti-backward classes and anti-Kerala Budget. I am not an astrologer, but I want to make a prediction here. For the next Budget of 2026, the hon. Finance Minister is going to grant a special financial package to Kerala. She might possibly grant an AIIMS to Kerala. She might perhaps grant some more disaster relief fund to Kerala. She might also grant relief to the rubber farmers in Kerala. The answer is very simple why she is going to give all these things next year. Kerala is going for elections next year. The Budget has been reduced to a mere political tool for winning elections, which is very, very unfortunate.

Sir, for healthcare sector, which is a very crucial sector, what has been allocated is only some 10,000 additional seats for the MBBS. We know that the primary healthcare system is in shambles. Nothing is there in the Budget to improve the primary healthcare systems, which are the backbone of the healthcare delivery system. There should have been a good capital investment, which would have spurred the economic activity and provision of healthcare in villages. There is constant under-spending when it comes to capital expenditure by the Ministry of Health over the years. As far as cost of medicines is concerned, there is an announcement in the Budget that rare medicines as well as cancer drugs will be fully exempted from customs duty. This will not benefit the patients because the rare disease medicines are very, very costly. I mentioned the other day that the spinal muscular atrophy medicine costs around Rs.6.5 lakh per bottle and it requires 30 bottles of medicine. Even if you exempt it from customs duty, the benefit will not reach the patients. So what the Finance Minister should have done -- and I urge the Finance Minister to do that -- is to give the local drug manufacturer the licence to manufacture generic drugs in India by invoking Section 100 of the Patents Act. If the drug costing Rs.6.5 lakh per bottle is manufactured in India, it will cost only approximately Rs. 3,000 per bottle. That will be the difference. That has to be done. I urge the Finance Minister to consider this.

As far as the Non-Resident Indians are concerned, one major problem that they are facing while disposing of their land and properties is that they are not getting the benefit of indexation which the Resident Indians are getting. While the Resident Indians are getting the benefit of indexation, the Non-Resident Indians have to pay a huge amount of tax while they dispose of their properties. I urge the Finance Minister to have parity between the Non-Resident Indians and the Resident Indians.

As far as minorities and tribal communities are concerned, this is a very depressing Budget. They have introduced significant cuts in several educational schemes for minorities and tribals. The National Fellowship and Scholarship for Higher Education of Scheduled Tribe Students has seen a 99.99 per cent reduction with its allocation dropping from Rs. 240 crore in the Revised Estimates for 2024 to just Rs. 0.02 crore in the Budget Estimates for 2025. Similarly, the Pre-Matric Scholarship for Minorities was allocated Rs. 326 crore in the Revised Estimates will now receive only Rs. 90 crore, marking a 72.4 per cent decrease. Similarly, the Post-Matric Scholarships for Minorities have been reduced by 69.9 per cent from Rs.1,145 crore to Rs.343 crore. Now, there are several fellowship schemes which have been stopped and scrapped including the Maulana Azad National Fellowship Scheme.

Through you, I urge the hon. Finance Minister to reinstate all the scholarship schemes.

Sir, as far as global warming and climate change is concerned, this is an international phenomenon with a lot of local consequences. We have seen as to what happened domestically in Wayanad and in other places of India where landslides occur very frequently. For that, there is nothing in the Budget to overcome and prevent this kind of natural calamities. Same is the case with human-animal conflict in villages bordering forest. I urge the hon. Finance Minister to have some allocation for border villages to have fencing so that human-animal conflict is, to some extent, avoided. Similarly, there should be budgetary allocation for rehabilitation of communities affected by floods and other natural disasters, including the Wayanad natural disaster.

Sir, as far as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme is concerned, allocation for rural areas which favours the welfare of the poor has been constantly reduced. Spending under MGNREGA has been lowered by 31 per cent which is quite unfortunate. The hon. Prime Minister, while replying here to the debate on the Motion of Thanks to the President's Address, said that in the year 2013, the tax exemption limit was only Rs.2 lakh whereas in 2025, they have increased it to Rs.12 lakh. The hon. Prime Minister should also remember, and I have to remind him, that in 2013, you could have got one dollar with Rs.50; now, you can get one dollar by spending around Rs.87. That is the kind of devaluation the money is having. So, this is actually causing concern to the whole nation. This also has to be completely taken into account.

Now, Sir, as far as the four engines, which have been mentioned in the Budget Speech, are concerned, nothing has been mentioned about unemployment. Unemployment is something which is rising in this country and there is no provision over here. The level of earning of regular wager as well as the salaried class has been reduced from Rs.12,615 to Rs.11,858. (*Time-bell rings*.) I am concluding. The cost of healthcare has also increased. So, the Government's priority to provide affordable healthcare for villagers should be made. I am concluding.

In conclusion, I would say that this is a Budget that favours the rich and ignores the vast majority of India's population, which is the common man. Thank you.

श्री उपसभापतिः श्री दीपक प्रकाश जी। आपके पास बोलने के लिए 10 मिनट का समय है।

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड)**:** माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी एव केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का दिल की गहराई से अभिनन्दन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने 140 करोड़ जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट लाने का काम किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही है। मां भारती के जिस भाग में सूर्य की रोशनी जाती है, वहां पर खुशहाली आए, यह प्रधान मंत्री जी का संकल्प इस बजट के अंदर है। महोदय, यह विकसित भारत का रोडमैप है। यह बजट चार प्रमुख - डबल इंजन जिसको कहते हैं, उस प्रमुख इंजन के द्वारा संचालित होगा। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात के माध्यम से इस देश में खुशहाली लाने का जो प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट हैं, वह इस बजट के अंदर दिख रहा है।

महोदय, हमारे सामने बैठे हुए कांग्रेस के और अन्य कई साथियों ने इस बजट के बारे में कई टिप्पणियां की हैं। अगर किसी व्यक्ति को या किसी चित्रकार को आंख बंद करके कांग्रेस और कांग्रेस के शासन काल की तस्वीर बनाने के लिए कहा जाए, तो तस्वीर से जो चीज़ें उभर कर सामने आएंगी, वे वित्तीय अराजकता की आएंगी। वह financial anarchism का आएगा और कांग्रेस के शासनकाल में किस प्रकार से policy paralysis के माध्यम से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हम लोगों ने इस देश के अंदर देखा है। यही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के सवाल पर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में देश को आक्रोशित होते हुए देखा है और परेशान होते हुए देखा है।

उपसभापति महोदय, कांग्रेस के शासनकाल में अगर घोटालों की बात की जाए, तो शायद आप सब लोगों को स्मरण होगा कि कोयले की जो खान होती थी, वह चुटके में आवंटित होती थी। कोयला घोटाला, अगस्ता हेलिकॉप्टर घोटाला, बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, डीएलएफ घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, मुंध्रा घोटाला, नागरवाला घोटाला, मारुति घोटाला, कुओ ऑयल घोटाला, सत्यम घोटाला, यूरिया घोटाला, और भी घोटालों की चर्चा की जाए, तो इस सदन के अंदर कई दिन लग सकते हैं। मैंने 2जी घोटाले का नाम लिया ही नहीं, लेकिन अच्छा हुआ कि आप लोगों ने स्मरण दिला दिया।

सर, हमारे सामने कल चिदम्बरम साहब बेरोजगार और बेरोजगारी के बारे में घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। इतने आंसू बहा रहे थे कि अगर सच में उनके सामने बाल्टी रख देते, तो पूरी बाल्टी भर जाती। उनको सच का सामना करना चाहिए। बेरोजगार, बेरोजगारी दर के बारे में मैं 1972-73 का उल्लेख करना चाहता हूं। नेशनल सैम्पल सर्वे, जिसको एनएसएसओ कहा जाता है। जब पहली बार सर्वे हुआ, तो उस समय 1972-73 में बेरोजगारी की दर 8.35 प्रतिशत थी। उस वक्त आपका शासन था। पहली बार एनएसएसओ के द्वारा सर्वे किया गया था। चिदम्बरम साहब, बेरोजगार और बेरोजगारी के बारे में बहुत जबरदस्त भाषण दे रहे थे। 2004 से लेकर 2008 तक वे वित्त मंत्री थे। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः उपसभापति महोदय, चिदम्बरम साहब हाउस में नहीं हैं, तो उनका नाम न लिया जाए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः प्लीज़, आप बैठ जाइए।

श्री दीपक प्रकाशः मैडम, सच का सामना आप भी कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः आप बोलिए, आपका समय जा रहा है।

श्री दीपक प्रकाशः वे 2004 से लेकर 2008 तक वित्त मंत्री थे, तो 2009 में बेरोजगारी की दर 10 प्रतिशत थी। अगर कहा जाए, तो आज मोदी जी के शासनकाल में बेरोजगारी दर तीन प्रतिशत से भी कम है। यह है मोदी मैजिक।

सर, आज कांग्रेस बेरोजगार और बेरोजगारी के बारे में बात करती है। सच तो यह है कि देश की जनता ने हर कांग्रेसी को बेराजगार बना दिया है। वे बेरोजगार की व्यथा नहीं, बल्कि अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे थे। कांग्रेस के कार्यकाल में वित्त मंत्री, जिसको हम कह सकते हैं कि 1974 की बात मैं आपके सामने और सदन के सामने लाना चाहता हूं। उस वक्त के वित्त मंत्री, जब सदन के अंदर बजट पेश कर रहे थे, तो उनका दृश्य देखने लायक रहा होगा। उस वक्त के वित्त मंत्री जी ने 1974 में घुटना टेक और धरतीपकड़ आत्मसमर्पण से भरा हुआ बजट लाने का काम किया था। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि कृषि उत्पादन में 9.5 प्रतिशत फीसदी की गिरावट आई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और संसद में यहां तक मान लिया कि तमाम उपायों के बावजूद महंगाई बढ़ना जारी है। उस पर हम रोकथाम नहीं कर पाए। उनको महंगाई कम न कर पाने का खेद था और उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने सदन में जो कहा, उसको मैं क्वोट कर रहा हूं, "It is a matter of deep regret to me that despite these measures prices have continued to rise." महोदय, उस वक्त के वित्त मंत्री को सच कहना महंगा पड़ा। उस वक्त के वित्त मंत्री को सच बोलने का खामियाजा भुगतना पड़ा था, उस वक्त सच कहने के कारण इंदिरा जी ने उन्हें वित्त मंत्री पद से हटाने का काम किया। महोदय, उसके बाद 1975 में जो बजट आया, उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने उस बजट को लाने का काम किया था। उन्होंने क्या कहा था, मैं उसको आपके सामने क्वोट करना चाहता हूं। And I quote, "Inflation has been spreading and its devastating impact across national boundaries, continue to impose on developing countries... The impact on the living standards of our people and on the pattern of real incomes within the country has been serious enough." यह आपके वित्त मंत्री ने कहा था। ...(**व्यवधान**)... मैं नाम बता देता हूं। पहले वित्त मंत्री, जो 1974 में बजट लाए थे, उनका नाम यशवंतराव बलवंतराव चव्हाण था और 1975 में जो बजट लाए थे, उनका नाम सी. सूर्यमनियम था।

महोदय, अगर हम कांग्रेस और कांग्रेस के कालखंड की चर्चा करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अच्छा बजट वह है, जो गरीबों के पेट की भूख को खत्म करने का काम करे, अच्छा बजट वह है, जो सामाजिक जीवन के स्तर को ऊँचा कर सके।

महोदय, मैं झारखंड से आता हूँ और झारखंड से आने के कारण मैंने देखा है कि वहाँ पर लातेहार नाम से एक जिला है। वहाँ पर एक गारू प्रखंड है और आप इसके बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं। मैं विद्यार्थी जीवन में एक बार एक सर्वे के काम से वहाँ पर गया था। मैंने वहाँ पर देखा कि आदिवासी समाज को अनाज उपलब्ध नहीं था, चावल उपलब्ध नहीं था और उन्हें कटहल खाकर अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता था। महोदय, मैं यह कांग्रेस के कालखंड की बात कर रहा हूं।

मैं हाल के दिनों में वहाँ पर गया था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के शासन में वहाँ पर हर घर में चावल पहुँच रहा है, हर घर में रोशनी पहुँच रही है और हर घर में लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए health sector better हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। महोदय, हर घर में शौचालय बना है। महोदय, इतना ही नहीं है, हर व्यक्ति की चिंता करने का नाम ही मोदी है।

महोदय, मैं कांग्रेस के कालखंड के मिजोरम के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। महोदय, 1959 और 1960 में मिजोरम में भयानक अकाल पड़ा था। लोग मर रहे थे, उनका जीवन खतरे में था, लेकिन उस वक्त की सरकार, जो केंद्र में नेहरू जी की सरकार बैठी हुई थी, उसने उनकी खैरियत पूछने का भी काम नहीं किया, उनके बारे में विचार नहीं किया। महोदय, उस अकाल के कारण आदिवासी समाज के कई लोगों ने अपनी आहुति देने का काम किया था। उसके बाद उन्हीं अकालपीड़ित लोगों ने मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट बनाने का काम किया। महोदय, मिजो नेशनल फेमिन फ्रंट के माध्यम से ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापतिः दीपक जी, आप कंक्लूड कीजिए।

श्री दीपक प्रकाशः उपसभापति जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। महोदय, उन्हीं लोगों में एक अलग अलगाववाद पैदा हुआ। अगर नेहरू जी को चिंता होती, तो वहाँ पर अलगाववाद पैदा नहीं होता। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Deepak*ji*, please conclude. Just conclude.

श्री दीपक प्रकाशः महोदय, 1966 में उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की इंदिरा जी की सरकार ने जिस प्रकार की क्रूरता से व्यवहार किया, उसके कारण ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.दीपक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दीपक प्रकाशः महोदय, मैं ज्यादा न बोलते हुए इस बजट पर इतना ही कहूंगा कि यह विकसित भारत बनाने का बजट है, इसलिए सभी मिलकर इसका समर्थन कीजिए।

महोदय, आपने मुझे बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः दीपक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यण, मैं आप सभी से समय के बारे में सहयोग चाहूंगा। अभी लगभग तीन दर्ज़न स्पीकर्स बोलने के लिए बचे हुए हैं। आप प्लीज़ अपने समय को follow करें। मैं चेयर की ओर से remind नहीं कराना चाहूंगा, आप स्वयं को self-restraint रखें। आपके लिए जो समय allocated है, वह वहाँ पर प्रदर्शित होता है। जब समय खत्म होता है, मैं तब ही याद दिलाता हूं। Kindly cooperate, क्योंकि अभी लगभग तीन दर्ज़न

स्पीकर्स बोलने के लिए बाकी हैं। Shri Abdul Wahab; not present. माननीया प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

6.00 P.M.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र): सर, वित्त मंत्री जी ने लगातार आठवाँ बजट पेश किया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगी। साथ-ही-साथ, आम जनता को लगातार आठवीं बार जो £ मिला है, उसकी सुनवाई रखना चाहूँगी।

श्री उपसभापति: शायद £ शब्द अनपार्लियामेंटरी होगा। We will check.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: सर, बदहाली पार्लियामेंटरी है, तो बदहाली रख लीजिए।

श्री उपसभापति: यह अपेक्षा है कि पार्लियामेंटरी ही है।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: हाँ, पार्लियामेंटरी है, तो बदहाली। सर, जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उसमें उन्होंने जनता को 12 लाख तक इनकम टैक्स की राहत दी। मैं इसका स्वागत करती हूँ, पर यह जो 11 साल बाद मिडिल क्लास के लोगों की सुनवाई हुई है, जो हर बार उम्मीद से वित्त मंत्री जी की तरफ, बजट की तरफ देखते थे, पहला बजट हुआ, दूसरा बजट हुआ, तीसरे बजट से निर्मला सीतारमण जी ने कमान संभाली, पर उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा था। इसी मध्यम वर्गीय जनता के दिए 240 के आंकड़े ने उन्हें मजबूर कर दिया कि उन्हें यह 12 लाख की राहत मिले, तो मैं इसका स्वागत करना चाहती हूँ कि 240 पर आए, तो शायद मध्यम वर्गीय लोगों की सुनवाई भी हुई। ये मध्यम वर्गीय लोग वे हैं, जिन्होंने देखा कि 2,09,000 करोड़ लोगों का कॉरपोरेट लोन राइट ऑफ कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 2024 में 1,70,000 करोड़ कॉरपोरेट लोन राइट ऑफ हो रहे थे और वे फिर भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो केंद्र सरकार है, वह उन्हें इनकम टैक्स की थोड़ी छूट देगी। उन्होंने देखा कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, फिर भी ये वही मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो उम्मीद की आस लगाए बैठे थे, तो आज उनकी सुनवाई हुई है, मैं उसका स्वागत करती हूँ।

सर, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। हम महाराष्ट्र से जो हर सौ रुपये का योगदान केंद्र में डालते हैं, हमें उसके सिर्फ सात रुपये वापस मिलते हैं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश तरक्की करे और महाराष्ट्र का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता है, उससे पूरे देशवासियों को फायदा मिले, विकास हो, प्रगति हो। हमें इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर जिस तरीके से बजट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन purpose से करने लगे हैं, उससे मुझे तकलीफ होती है। सर, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। बिहार के लिए जो भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, स्वयं संजय यादव जी ने कहा कि जो भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, उनमें से कोई भी धरातल पर तब्दील नहीं होते हैं। बजट में हर

£ *Exupnged as ordered by the Chair.*

साल अनाउंसमेंट्स होती हैं। ...(**व्यवधान**)... आप करेक्ट कर देना। जब आपका समय आए, तब आप करेक्ट कर देना। सर, इन्होंने इस बजट में बिहार के लिए new canal projects approve किए हैं। चूँकि मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, तो विदर्भ और मराठवाडा भी उसी उम्मीद से देखते हैं कि शायद हमारा भी नाम लिया जाएगा और जो हमारे irrigation projects हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। 2022 में officials के आंकड़े थे कि करीब 100 projects complete करने के लिए Rs.43,500 crores का irrigation support चाहिए। चूँकि पिछला साल इलेक्शन का साल था, तो last year सरकार ने 600 करोड़ का special package irrigation project के लिए drought hit विदर्भ और मराठवाडा के लिए दिया। सर, उसमें इस्तेमाल कितना हुआ – उसमें से सिर्फ 30 प्रतिशत इस्तेमाल हुआ - 400 करोड़, जो कि Revised Estimate है और इस टाइम पर कोई ज्यादा allocation हुआ ही नहीं है। महाराष्ट्र के साथ बार-बार इस तरीके का भेदभाव होता है। क्या महाराष्ट्र के किसान देश के किसान नहीं हैं? क्या महाराष्ट्र ने भी अपना खून पसीना नहीं बहाया है? जीएसटी के माध्यम से आपका जो टैक्स कलेक्शन होता है, डायरेक्ट टैक्स में जो देते हैं, वे देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के माध्यम से हर वर्ग देता है, उन्हें राहत मिलनी चाहिए। सर, मैं एक और आंकड़ा पेश करना चाहूँगी। नागपुर में नाग रिवर हैं, जिसमें पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ का Budget Estimate financial year 2024-25 में किया गया और उसमें procedural delays की वजह से सिर्फ छः करोड़ allot हुए और इस्तेमाल हुए। अब जो नया बजट आया है, उसमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ दिए गए हैं। सर, मखाना बोर्ड की बात हुई, institutional aids की बात हुई, food technology institute की बात हुई, increasing seats in IIT, Patna की बात हुई। National Institute of Industrial Engineering, Mumbai को IIM बना दिया है, पर उसके लिए बजट का कोई आवंटन नहीं किया गया है। क्या महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य हो गया है, जहाँ से पैसा लिया जाएगा, पर वहाँ पर किसी तरीके से, equitable manner से वापस नहीं किया जाएगा। जब अजीत पवार जी हमारे महाराष्ट्र के वित्त मंत्री होते थे, जब हम महाविकास अघाडी में थे, तब वे बार-बार जीएसटी काउंसिल में जो महाराष्ट्र का जीएसटी revenue आना था, वह नहीं दिया जा रहा था, उसे लेकर आवाज उठाते थे, पर कहीं-न-कहीं अब वे भी शांत हो गए, क्योंकि अब वे वहाँ से वित्त मंत्री बन गए हैं। सर लाडकी बहन योजना की बात मैंने पहले भी कही थी कि ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं एक मिनट और लूंगी।

श्री उपसभापतिः अब आप कन्क्लूड करें।

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदीः सर, मैं कन्क्लूड कर रही हूं। लाडकी बहन योजना से साठ लाख महिलाओं को वंचित किया जा रहा है और साथ ही साथ जो स्कीम्स अनाउंस की गई थीं, उनको भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। यह देश के साथ ...(**समय की घंटी**)... महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं। धन्यवाद, जय महाराष्ट्र! जय हिंद!

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। माननीया श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, 10 मिनट।

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं माननीया वित्त मंत्री जी, नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी की संवेदनशीलता की कायल हूं कि देश का बजट प्रस्तुत करते समय उन्होंने मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री रामदुलारी देवी, जो दलित समाज से आती हैं, उनके द्वारा उपहार में दी गई साड़ी को पहना।

[**उपसभाध्यक्ष** (**डा. दिनेश शर्मा**) *पीठासीन हुए।*]

इससे उन्होंने न केवल बिहार के लोगों के प्रति अपने प्रेम और विश्वास को सार्थक किया, बल्कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' को भी चरितार्थ किया।

मोदी जी ने सबके दिलों में विश्वास रख दिया,
कुछ करने का जज्बा खास कर दिया,
और जब बजट पेश हुआ देश का,
तो मखाना के बदौलत बिहार में इतिहास रच दिया।

यह है माननीय मोदी जी का बजट, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए लगभग 100 करोड़ से अधिक की राशि का ऐतिहासिक प्रावधान किया, इसके लिए हम आभारी हैं। इससे महिला उद्यमिता, स्वरोजगार और सुरक्षा के लिए कई अवसर मिलेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि जब बिहार में जंगल राज था, पति-पत्नी की सरकार थी, तो महिलाओं का घर से निकलना दूभर था। उस शासन काल में चारा घोटाला, चरित्र घोटाला, मेधा घोटाला, पुलिस वर्दी घोटाला, पाइप घोटाला और न जाने कितने घोटाले हुए, मैं उन पर जाकर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूं। इतना ही नहीं, यहां तक कि युवाओं को ठगने के लिए लैंड फॉर जॉब्स स्कैम, अर्थात् नौकरी के बदले जमीन घोटाला भी बड़े पैमाने पर किया गया था। तत्कालीन मुख्य मंत्री ने बिहार में बड़े पैमाने पर चरवाहा विद्यालय खोले थे, जो आगे चलकर चारा घोटाले के माध्यम बने। इसके बारे में जिक्र करके मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूं, बल्कि यह बताना चाहती हूं कि आज आईआईटी पटना प्लेसमेंट की दृष्टि से देश के कई आईआईटी संस्थानों से आगे है। बजट में आईआईटी पटना के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके विस्तार के बाद यह संस्थान देश के टॉप 5 आईआईटीज़ में शामिल हो जाएगा। यहां छात्रावास समेत अन्य तरह की अवसंरचना का विकास होगा।

महोदय, मिथिला में एक कहावत है, जो मैं आपको बताना चाहती हूं:

पग-पग पोखर माछ मखान,
सरस बोल मुस्की मुख पान,
विद्या, वैभव, शांतिक, प्रतिक,
सुंदर नगर इ थीक मिथिलाधाम।

महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि मिथिला की पहचान पोखर यानी तालाब, मछली, पान और मखाना से जुड़ी हुई है। देश की लगभग 80 से 90 प्रतिशत मखाना की खेती बिहार के मिथिलांचल में होती है। आंकड़ों के अनुसार बिहार के लगभग 35-40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती होती है। बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। इसके गठन से इस क्षेत्र में शोध कार्य को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीकों से उत्पादन का प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी तथा मखाना बाजार और संगठित हो जाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य कुछ बता रहे थे, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब पति-पत्नी की सरकार थी, तो महिलाएँ घर से नहीं निकल पाती थीं और व्यापारियों के शटर 6 बजे शाम को बंद हो जाते थे। न रोड थी, न सड़क थी, न घर था, न नल था, न जल था और महिलाएँ खुले में शौच जाती थीं। महोदय, आज माननीय प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के सुशासन में, उनके शासन काल में महिलाओं को जो सम्मान मिला, वह किसी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला था और बिहार में जंगल राज में नहीं मिला था, यह मैं सदन को बताना चाहती हूँ।

महोदय, चंद शब्दों में मैं अपने बिहार के बजट को दर्शाना चाहती हूँः

मोदी जी के इस युग में आई क्रांति की बयार,
बजट में मिला हमारे बिहार को विशेष उपहार।
कोशी के शोक को हरा,
युवाओं को मिला आईआईटी का विस्तार,
मखाना बोर्ड हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट,
सब पाकर हमारा बिहार,
विकास की नई उड़ान भरने को है तैयार हमारा बिहार।

यह है मोदी जी का बजट और माननीया वित्त मंत्री, आदरणीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का देश के लिए यह बहुत ही लाभकारी बजट है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बजट में जिस पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय मदद की घोषणा की गई है, उससे नहरों का न केवल विस्तार होगा, बल्कि इस परियोजना के आधुनिकीकरण के बाद पहले की तुलना में दो गुना अधिक लगभग 50 हजार हेक्टेयर भूमि को खेती के लिए पानी मिल सकेगा। बजट में बिहार के लिए बड़ी घोषणाओं में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा प्रमुख है। बिहार में इस प्रकार के संस्थान की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इससे कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण होगा और किसानों को उनकी उपज के उचित दाम मिलेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बजट में राष्ट्रीय स्तर पर लघु एवं सीमांत किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा में वृद्धि का फायदा बिहार के किसान भी उठाएँगे। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ा कर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बिहार में अभी लगभग 40 लाख से अधिक किसानों के पास क्रेडिट काड्र्स हैं। उन्हें सस्ती दर पर पहले से अधिक ऋण मिल

सकेगा, जिससे बिहार के उद्यमी, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में बिहार के हवाई अड्डों को यात्रियों के भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की घोषणा से विकास को पंख लगेंगे। बिहार में चार नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएँगे और पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी। संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हर घर नल से जल पहुँचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इससे बिहार राज्य के ग्रामीण इलाकों में पेय जल संकट का समाधान होगा। ई-श्रम पोर्टल पर एक करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा। इससे इन श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के लाभ मिलेंगे। बिहार रेलवे को इस बार बजट में 10 हजार करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पिछली यूपीए सरकारों के समय से 9 गुना अधिक है। महोदय, इस सकारात्मक बजट में बिहार को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): संक्षिप्त कीजिए, कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता: यह हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी की दूरदृष्टि को सिद्ध करता है। वह यह सिद्ध करता है कि देश में एक संवेदनशील सरकार है, ...(**समय की घंटी**)... जो जनहित के लिए सदैव तत्पर रहती है।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता: एक मिनट, महोदय।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): नहीं, अब कोई मिनट नहीं।

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता: बिहार के प्रति इस संवेदनशीलता एवं उदारता के लिए ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अब आप समाप्त कीजिए। अब कुछ नोट नहीं होगा।

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता: *

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): नेक्स्ट। श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी। Five Minutes.

---

* *Not recorded.*

श्री उपेन्द्र कुशवाहा (बिहार): महोदय, भारत सरकार की ओर से यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, जब से मैं बजट के बारे में थोड़ी समझदारी रख रहा हूं, इसे देख रहा हूं, तब से केंद्र सरकार की ओर से पहली बार ऐसा बजट रखा गया है। बजट के बारे में जहां भी चर्चा हो रही है, सदन के अंदर या सदन के बाहर, उस चर्चा के केंद्र में हमारा बिहार है। यह हम पहली बार देख रहे हैं, इसलिए मैं बिहारवासियों की ओर से और अपनी ओर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी का और माननीया वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।

महोदय, इन लोगों ने तो बिहार के साथ हमेशा अन्याय ही किया। आजादी के पहले से ही बिहार के साथ अन्याय हुआ है। बाद में जब इनको मौका मिला, तो इन लोगों ने अन्याय ही अन्याय किया। जब से नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार आई है, तब से हम सब लोगों की अपेक्षा, बिहार के लोगों की अपेक्षा थी कि बिहार को न्याय मिलेगा, तो निश्चित रूप से इस बजट के माध्यम से और उसके पहले भी जो बजट आया था, उसके माध्यम से केंद्र की सरकार ने बिहार के साथ न्याय किया है, इसलिए हम इस बजट का धन्यवाद करते हैं।

महोदय, पहली बार किसानों की चिंता की गई है। यह मैं विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार में कृषि ही आय का मुख्य स्रोत है। केंद्र की सरकार ने बिहार के संदर्भ में किसानों की चिंता की है। किसानों के जो मौलिक सवाल हैं, उन पर सरकार ने ध्यान देकर चिंता की है।

महोदय, अभी नहीं, थोड़ा पहले ही चीनी मिल जहां भी चल रही थी, प्रायः बंद हो गई थी। अभी कांग्रेस के एक माननीय सदस्य बोल भी रहे थे कि चीनी मिल बंद है। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब से भारत सरकार से राज्य की सरकार लगातार आग्रह कर रही थी कि इथेनॉल उत्पादन की अनुमति हमें दीजिए। इसके लिए लगातार कोशिश किए जाने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने राज्य को इथेनॉल उत्पादन की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते चीनी मिल घाटे में चल रही थी। लेकिन हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार को इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दे दी और इसका परिणाम यह है कि वहां जो कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग हैं, उनकी स्थापना शुरू हो गई है। खगड़िया, बेगूसराय और पूर्णिया के इलाके में, जहां सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन होता है, वहाँ अभी इथेनॉल प्लांट लगा है, उसकी अभी शुरुआत हुई है, उसके चलते पहले लोग जो किसी तरह से 12 रुपये या 14 रुपये प्रति किलो मकई बेच पाते थे, आज उसका दोगुना से ज्यादा दाम लोगों को मिलने लगा है। इस तरह से इस सरकार ने किसानों के लिए सोचने का काम किया है।

महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और किसानों की अपनी समस्याएँ हैं। बिहार का एक भाग सुखाड़ से परेशान होता है और एक भाग बाढ़ से परेशान होता है। वहाँ बाढ़ से जो परेशानी है, उसके लिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि नेपाल से बात करके उन इलाकों में बाढ़ की समस्या का स्थाई निदान निकल पाए, इसके लिए भारत की सरकार को पहल करनी चाहिए। महोदय, वहाँ जो सुखाड़ वाला इलाका है, शाहाबाद का इलाका, मगध का इलाका, गंगा के दक्षिण वाला जो इलाका है, उसमें अगर वर्षा ठीक से नहीं होती है, तो वहाँ सुखाड़ की स्थिति बनती है। अंग्रेजी राज में उस समय की बनी हुई नहर प्रणाली है, जहां से सिंचाई का काम कुछ हो

जाता है, लेकिन जितनी सिंचाई हो सकती थी, जितनी उसकी क्षमता थी, उस क्षमता में धीरे-धीरे ह्रास हुआ, क्योंकि जिस सोन नदी से उस नहर में पानी जाता है, उस सोन नदी में गाद भर गया है। सोन नदी में जो गाद भर गया है, उसकी उड़ाही की जरूरत है, उसके आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। मैं भारत सरकार से माँग करना चाहता हूँ कि सोन नहर के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव पर निश्चित रूप से केंद्र की सरकार विचार करे। महोदय, चूँकि सोन नदी में पानी कम आ रहा है, इसलिए सोन नदी में पानी के बहाव को तेज करने के लिए...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हो गया।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। सोन नदी में पानी का बहाव कम हो रहा है, इसके लिए अभी नहीं, बल्कि 30-35 साल पहले डैम बनाने की योजना, जिसका नाम इन्द्रपुरी जलाशय है, उसको बनाने की योजना का शिलान्यास हुआ, लेकिन वह अभी तक नहीं बन पाया। उसके नहीं बनने के पीछे कारण यह है कि यह कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। यह बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): कृपया आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री उपेन्द्र कुशवाहा: महोदय, चूँकि इसमें एक राज्य नहीं, बल्कि कई राज्य जुड़े हुए हैं, इसलिए केन्द्र सरकार से हमारी अपेक्षा है कि इन राज्यों से जुड़ी हुई जो यह समस्या है, इसके लिए केन्द्र की सरकार पहल करे और इन्द्रपुरी जलाशय को पूरा कराए, ताकि सिंचाई का काम आगे बढ़ पाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, जो भी वक्ता हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जो समय निर्धारित है, उसको देख कर ही वे अपना उद्बोधन करेंगे। डा. जॉन ब्रिटास।

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Respected Vice-Chairman, Sir, please give me two or three minutes more. I will not be making a speech. यहाँ पर बहुत सारी बातें बोली गई हैं।। will only dole out some pearls of wisdom. संजय जी, यह pearls of wisdom क्या है? यह ज्ञान का मोती है। मैं ज्ञान का मोती देना चाहता हूँ। अब आप यह ज्ञान का मोती सुनिए। On August 12, 2013, with a great sense of concern about the falling rupee, because it was about to cross the 62 mark against the dollar, the middle class was struggling to fund education abroad due to rupee depreciation. प्रियंका जी, यह किसने बोला? 'वे नहीं हैं। वे हार गए।' In 2022, the same person said, 'rupee is not falling, it is only finding its natural course.' अयोध्या जी, यह किसने बोला? 'Rupee is not falling, but dollar is strengthening.' रुपया तो नहीं गिर रहा है, डॉलर strengthen हो रहा है। संजय जी, अब दूसरा ज्ञान का मोती - 'Our rupee is continuously falling. During Atalji's time, it was at 40-45

to a dollar. Under this Government, it keeps falling to 62-65-70'. In 2014, संजय जी, यह किसने बोला? क्या आपको मालूम है? Again, in 2013, the same leader thundered, 'The rupee is in ICU. The Government says, it will recover in two months, but did it? They have lost control of the country.' 'डॉलर 60 रुपए हो गया, they have lost control of the country', - यह किसने बोला? निर्मला सीतारमण जी ने पहले बोला। The words 'they have lost total control of the country' were spoken by none other than Narendra Modiji. If the rupee has reached the 90 mark against a dollar, according to his stand, the country has been lost! कंट्री पूरा गया है। Will the Prime Minister agree that the country has been completely lost? Anyway, my friend, Trump, is doing everything to destroy this country. Sir, I did a statistics. In the last 11 years, rupee has gone down from 60 to 90 against the dollar. A depreciation of 50 per cent has happened. During the ten years of Dr. Manmohan Singh Government -- मनमोहन सिंह नहीं थे, मौनमोहन सिंह थे, वे inefficient थे, सब कुछ थे, -- in his time, despite his voluntary devaluation of rupee, it reached 60 from 45, which was just a 33 per cent depreciation.

In your 10 years, there has been 50 per cent depreciation. Sir, I don't want to speak about petrol. मोदी साहब ने पेट्रोल के बारे में क्या बोला। On petrol, he made a very profound statement. The Members from the Treasury Benches were saying कि यह गरीबों का बजट है। यह किसने बोला है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि यह मिडिल क्लास का बजट है। उन्होंने गरीबों को छोड़ दिया। अभी यह मिडिल क्लास का बजट है। I will just tell you the hoax which is being played. Despite giving away Rs.1 lakh crore, the projection for the next year is 14.4 per cent increase in income tax. That means, this Government needs to make, at least, Rs.2 lakh crore from the middle class. उनसे छीनेंगे। Is it middle-class Budget or is it anti middle-class Budget? It is a corporate Budget. I will tell you why it is corporate Budget. It is because without even giving any giveaway to the corporate sector, the projected growth in corporate tax revenue is hardly 10 per cent. But, for income tax, it is 14.4 per cent! Now, I do not know how to refer to fiscal federalism, but I will just quote again. यह ज्ञान का मोती मैं आपको दे देता हूँ -- "The State's right to financial autonomy for planning annual estimates of expenditure under Article 202 of the Constitution is severely eroded. State Legislatures pass various Bills in their Assemblies which suffer inordinate delay in awaiting the Governor's or President's assent". अयोध्या जी, यह किसने बोला? Shrimati Nirmala Sitharaman spoke about this in Nani Palkhivala Lecture in 2011. कालिता जी, क्या आप भूल गए? उस टाइम आप यहां थे। छोड़ दीजिए! See the contradiction. See what they speak and what the reality is. Again, Shrimati Nirmala Sitharaman, in 2011, said, "We are a large country with States differing in geo-topography and demography. The destiny of States should not be decided from Delhi." दिल्ली से कहा जाता था कि ऐसा मत करना, यह federal country है। "You should give autonomy and freedom to the

States to decide about the destiny". सर, यह किसने बोला? यह निर्मला सीतारमण जी ने बोला। ये अभी क्या बोल रहे हैं? ये अभी क्या करते हैं? ये वहां से 7 लाख करोड़ का सरचार्ज लेते हैं, लेकिन स्टेट्स को कुछ नहीं देते हैं। You are starving the States. Whatever you have spoken, in fact, on dollar, rupee, petrol, fiscal federalism, सर, ये उल्टा करते हैं। Now, I need to have a clarification. The Economic Survey was speaking about the need to have trust. Trust होनी चाहिए, trust in people. Unless you trust in the demographic dividend, the country cannot go ahead. That is what the Economic Survey says. But the Finance Secretary says, "No, we need to have animal spirit'. Look at this. अब ये human being को भूल गए और you require animal spirit! अगर हम चाइना के बारे में कुछ बोलेंगे, तो you people are accusing us of being pro-China. I will tell you, in the history of India, never before such an import has happened from China. The import from China has doubled. The trade deficit between China and India has doubled. Now, do you know what is the dispute? Do you want import from China? Do you want money from China? आपको investment चाहिए या import चाहिए? आप आपस में discuss करके सोच लीजिए कि क्या चाहिए, वह बता दीजिए। You are the biggest pro-China Government ever seen in this country, but you put journalists behind the bars saying that they are pro-China. So, take a decision, I mean, where do you belong to? Now, Trump is creating mahyem, though we address him as 'my friend'. The Import Duty has gone up on steel and aluminium. It is going to affect our industries. Further, the corporates who have got debt from a foreign country, their burden has gone up. This is a country which relies on imports. Do you know what our share in the world exports is? It is hardly 2 per cent. नीरज साहब, 2 परसेंट है। बाकी सब कुछ हम import कर रहे हैं। The burden, that is being heaped on this country, is unimaginable. You can help leaders. There is no harm in that. You can help them, but when you help them, please remember that they are chaining our brothers. They are putting chains on their legs and handcuffs on their hands. So, we have to decide on what our foreign policy should be and how we should interact and deal with the other countries and what should be the way in which we should tread ahead. I have only one request. सर, प्रियंका जी ने अभी बोला था, that Maharashtra is part of this country, but none from Maharashtra got up and said, as though they were agreeing with her. Sir, this country belongs to everybody. Not even once the Finance Minister mentioned about Kerala.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप conclude कीजिए।

DR. JOHN BRITTAS: Kerala is very much part of this country. How you can deny...(*Time-bell rings.*)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा) : आपका बोलने का समय पूरा हो गया है ...(**समय की घंटी**)... जो ऑलरेडी 5 मिनट बढ़ाया जा चुका है। अब आप conclude कीजिए।

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am concluding. My request, through you, Sir, is, let them uphold what what Modiji spoke to the nation in 2014, and what Nirmalaji spoke to the nation in 2013. Let them uphold that. That will resolve the problem. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आपका allotted time पूरा हो गया है। मैं आपको सलाह तो नहीं दे रहा हूं, पर एक सूचना दे रहा हूं कि आज 18 देशों में रुपये का transaction होता है, रुपये का महत्व बढ़ा है। अब डा. सिकंदर कुमार...

डा. सिकंदर कुमार (हिमाचल प्रदेश): मान्यवर, आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2025-26 के लिए सदन में जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपका और हमारे सदन के नेता आदरणीय नड्डा जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया और लगातार आठवीं बार growth-oriented और 'विकसित भारत' का बजट पेश करने के लिए निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सभी वक्ताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों के बजट का विषय हमारे बीच में रखा। मैं कुछ बातें सदन के बीच में रखना चाहता हूं। यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और आशा के अनुरूप देने के लिए देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वह युवा हो, महिला हो, कर्मचारी हो, मज़दूर हो, एससी/ एसटी हो, ओबीसी हो - हर वर्ग के लिए इस बजट में कल्याणकारी योजनाएं समाहित हैं। इस बजट में जहां विकास की रफ्तार बढ़ेगी, जहां समावेशी विकास और सुनिश्चित होगा और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, वहीं मध्यम वर्ग की परचेज़िंग पावर बढ़ेगी। मैं समझता हूं उसकी वजह से आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, उसके लिए भी मैं आदरणीय मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

इस बजट में जहां आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य दिखता है, वहीं दूसरी ओर इस बजट में विकसित भारत का संकल्प दिखता है। सर, मैं छोटे-से प्रदेश पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल प्रदेश, दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। मैं देश के माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि पिछले दस वर्ष के अंतराल में, पिछले दस वर्ष के कालखंड में हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि-बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें और रेल कनेक्टिविटी की बात करें, तो हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है, वह आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और उनकी परियोजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हुआ है। मैं उसके लिए भी माननीय मोदी जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

मान्यवर, पिछले दस वर्ष के कालखंड में हिमाचल प्रदेश में केन्द्र सरकार ने जो योजनाएं शुरू की थीं और वे कंप्लीट भी हो गई हैं। लगभग 70 परसेंट वे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और 30 परसेंट पर काम जारी है। एम्स, हिमाचल प्रदेश ने कभी नहीं सोचा था कि विश्वस्तरीय संस्थान हमारे जैसे छोटे प्रदेश को मिलेगा और बहुत कम अंतराल में ढाई साल में वह बनकर तैयार हुआ और हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित हुआ, उसके लिए मैं तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री और नेता सदन माननीय नड्डा जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से हमें विश्वस्तरीय संस्थान मिला और हिमाचल प्रदेश भी उसका लाभ ले रहा है। इसके साथ ही PGI satellite centre, जो साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का हिमाचल प्रदेश ऊना में बना, चार Medical colleges के लिए 1 हजार, 40 करोड़ रुपये माननीय नड्डा जी ने हमें दिए। जहां देश भर में कैंसर एक गंभीर बीमारी है, देश भर में इसके पेशेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है, तो मैं मोदी सरकार का और वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने 2025-26 के बजट में यह फैसला लिया कि हरेक डिस्ट्रिक्ट में Daycare cancer center खोलने का प्रावधान किया, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसी बजट में, जहां एमबीबीएस की सीट्स इस साल में दस हजार बढ़ाने के लिए और आने वाले पांच वर्ष में 75 हजार एमबीबीएस सीट्स बढ़ाने के फैसले का स्वागत करता हूं और उसके लिए भी मैं मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करूं, तो हिमाचल प्रदेश में Central University, Dharamshala – Rs. 1,300 crore; IIIT, Una - Rs. 300 crore; Hydro-engineering college, Bilaspur – Rs. 140 crore; IIM, Nahan – Rs. 500 crore; Medical Device Park, Nalagarh – Rs. 350 crore; Bulk Drug Park, Haroli, Una – Rs. 1,900 crore; Atal Tunnel – Rs. 3,200 crore; जिस रोड कनेक्टिविटी के बारे में मैं बात कर रहा था, Pinjaur-Nalagarh, four lane – Rs. 1,692 crore; Kiratpur-Manali four lane – Rs. 6,000 crore; Parwano-Shimla four lane – Rs. 13,784 crore; Pathankot-Chakki-Mandi highway– Rs. 10,067 crore, Shimla-Mataur highway – Rs. 10,512 crore और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि जब देश में चार वन्दे भारत ट्रेन्स चलीं, तो उन चार में से एक हिमाचल प्रदेश को दी गई, उसके लिए भी मैं नरेन्द्र मोदी जी का और रेलवे मिनिस्टर का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस वर्ष भी रेलवे के लिए हिमाचल जैसे छोटे-से राज्य के लिए, जो 2014 में 108 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान होता था, आज हिमाचल प्रदेश के लिए 2,716 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, उसके लिए भी मैं माननीय रेलवे मिनिस्टर और मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं।

सर, मैं जो ये योजनाएं गिना रहा था, लगभग एक अरब से ऊपर ये योजनाएं हैं। और मैं सदन में कहना चाहता हूं हमारे विपक्ष के मित्रों से कि हिमाचल प्रदेश में 35 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी और देश में लगभग 55 वर्ष के ऊपर कांग्रेस ने राज किया है। मुझे दस हजार करोड़ का एक प्रोजेक्ट बता दें, जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, जो उन्होंने स्वीकृत किया हो। आज हिमाचल प्रदेश, दूसरे देशों के साथ आगे बढ़ रहा है। सर, Reform, Perform and Transform के संकल्प के साथ देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है।

महोदय, मोदी सरकार की पिछले दस वर्ष की आर्थिक नीतियों की वजह से, बेहतर आर्थिक नियोजन की वजह से और कुशल वित्तीय प्रबंधन की वजह से, 2014 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, आज वह 5वें नंबर पर आ गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 2027 में देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी।

मान्यवर, कोरोना महामारी के बावजूद और विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वर्ष 2021 और 2024 के बीच में भारत ने 8 प्रतिशत की दर से विकास किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। आज भी जो global growth rate है, उसमें भारत का 15 प्रतिशत योगदान है। महोदय, IMF, जो कि International Monetary Fund है, उसके अनुमान के अनुसार 2028 तक भारत का world global growth rate में 18 परसेंट योगदान होगा। हमारे लिए यह भी एक बहुत सुखद समाचार है, जो माननीय मोदी जी की आर्थिक नीतियों और वित्त मंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

मान्यवर, एक समय ऐसा भी था, जब भारत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास लोन लेने के लिए गया था, तो हमारे भारत देश को लोन देने से मना कर दिया गया था। हमें इसलिए मना कर दिया गया था क्योंकि हमारे पास गिरवी रखने के लिए foreign exchange reserves नहीं था, लेकिन आज, जब हम यह कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पर आई है, तो मुझे यह कहते हुए गर्व भी महसूस हो रहा है कि भारत आज विश्व का चौथा ऐसा देश है, जिसके पास सबसे ज्यादा foreign exchange reserves है, जो 644.39 billion dollars है।

महोदय, आज हम विश्व की दस बड़ी इकोनॉमी की बात करे तो दस बड़ी इकोनॉमी में आज अगर कोई सबसे बढ़िया growing economy है, तो वह हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है। आज अगर हम भारत का दूसरे देशों से कंपेरिज़न करें, तो हमारे देश में दूसरे देशों की अपेक्षा cost of living, cost of consumption, cost of construction कम हैं। महोदय, poverty ratio, जो 2013-14 में 29.17 per cent था, वह 2022-23 में घटकर 11.28 per cent रह गया और दस साल के अंतराल में यह 17.89 per cent कम हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): कृपया कन्क्लूड कीजिए।

DR. SIKANDER KUMAR: Please give me two minutes, Sir. During this period, 24.82 crore people have come out of poverty. यानी यह संख्या 25 करोड़ है। (*Time-bell rings.*) उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जीएसटी पर बात कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): कृपया, आधे मिनट में अपनी स्पीच समाप्त कीजिए।

DR. SIKANDER KUMAR: Sir, please give me two minutes.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): नहीं, आधे मिनट में अपनी स्पीच समाप्त कीजिए। ऐसा माननीय सभापति जी का आग्रह है, क्योंकि बहुत सारे सदस्यों को बोलना है।

डा. सिकंदर कुमार: महोदय, मुझे कुछ डेटा देने हैं, इसलिए 2 मिनट दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): वह समय पार्टी से कटेगा, आप एक मिनट में समाप्त कर दीजिए।

डा. सिकंदर कुमार: महोदय, जीएसटी हमारे सामने वाले मित्र ही लाए थे, लेकिन उसे इम्प्लिमेंट करने का काम अगर किसी ने किया है, तो वह मोदी जी ने किया है। महोदय, जब जीएसटी नहीं था, तो हमें 35-40 per cent tax देना पड़ता था, लेकिन जीएसटी लगने के बाद यह 18 per cent हुआ। जीएसटी की वजह से 2018 में इसका collection 0.9 lakh crore था, जो वर्तमान में आज 1.95 lakh crore हो गया है।

महोदय, अभी हमारे मित्र Exchange Rate Depreciation की बात कर रहे थे, इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब Exchange Rate Depreciation 6.3 per cent से घटकर 3.1 per cent हो गया है। महोदय, आप जो बात कह रहे थे, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि Fiscal deficit as percentage of GDP, जो 2024-25 में 4.9 per cent था, वह आज घटकर 4.4 per cent रह गया है। (*Time-bell rings.*)

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): महोदय, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

DR. SIKANDER KUMAR: Revenue deficit as percentage of GDP, 1.9 per cent से घटकर 1.5 per cent रह गया है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्य, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. सिकंदर कुमार: हमारी Per capita income 86,454 रुपये से बढ़कर 2.7 लाख रुपये हो गई है। Tax-payers, जिनकी बात कर रहे थे, वह संख्या 3 crore, 80 lakh से बढ़कर लगभग 6 crore, 77 lakh हो गई है।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्य, आपकी सारी बातें आ गई हैं।

DR. SIKANDER KUMAR: Bank NPA 11 per cent से 0.6 per cent हो गया है। सर, टैक्स एग्ज़म्पशन्स 2 लाख से ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्य, मेरा अनुरोध है कि जो भी वक्ता हैं, वे समय का ध्यान रखें, उन्हें टोकना न पड़े, इसलिए जितना समय निर्धारित है, उसी समय में बोलिए।

डा. सिकंदर कुमार: महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्य, आपकी बात पूरी हो गई है, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम रखिएगा।

डा. सिकंदर कुमार: महोदय, मुझे बस एक बात कहने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्य, अगर मैं आपको टाइम दूंगा, तो मुझे सभी को समय देना पड़ेगा। अगर पार्टी अपना समय काटने के लिए तैयार है, तो मैं समय दे सकता हूं।

डा. सिकंदर कुमार: महोदय, मुझे बस दो मिनट दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अगर माननीय मंत्री जी कहें, तो मैं समय दे दूंगा।

डा. सिकंदर कुमार: महोदय, मैं आदरणीय मोदी जी को और माननीय निर्मला सीतारमण जी को ऐसा बजट लाने के लिए धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): राघव चड्ढा जी, आपके पास 37 मिनट हैं। मुझे विश्वास है कि आप समय पर ही समाप्त करेंगे।

श्री राघव चड्ढा (पंजाब): महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्वाद कि आपने मुझे यूनियन बजट 2025-26 पर आम आदमी पार्टी की ओर से बात रखने का मौका दिया। इस बजट को सरकार ने मिडिल क्लास का बजट बताया और कहा कि इस बजट में मिडिल क्लास की सारी समस्याओं का हल है। मैं सबसे पहले मिडिल क्लास की चर्चा करना चाहूँगा। उसके बाद अपने भाषण के अन्य भागों पर जाता जाऊँगा।

पहली बात तो यह है कि सरकारें मिडिल क्लास को एक आत्मा रहित कंकाल समझती हैं, जिसकी हड्डियों पर चढ़कर पाँच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना चाहती हैं। सर, इस देश का मिडिल क्लास कमरतोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा है। गरीबों के लिए तो अकसर सब्सिडीज़ और स्कीम्स लाई जाती हैं, जो कि लानी भी चाहिए। अमीरों के लिए Production Linked Incentive Scheme, rebates, tax incentives और न जाने क्या क्या लाया जाता है, लेकिन इस देश के मिडिल क्लास को कुछ हासिल नहीं होता है। ऐसा लगता है कि सरकारें समझती हैं कि देश के मिडिल क्लास के न सपने हैं, न अरमान हैं, लेकिन वह सोने का अंडा देने वह वाली मुर्गी है, जिसकी गर्दन जब चाहे मरोड़ कर टैक्स वसूल लिया जाए। इसी के चलते, मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में माँग, यानी कि डिमांड इसलिए गिर रही है, क्योंकि इस देश का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। आप एफएमसीजी सेक्टर से लेकर गाड़ी बेचने वाली कंपनियों की सेल्स के तमाम आंकड़े उठाकर देखेंगे, तो वे आपको यही बताएंगे कि इस देश का मिडिल क्लास खर्च नहीं कर रहा है और खर्च इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी जेब में आमदनी ही नहीं है। सर, मिडिल क्लास सिर्फ census के लिये नहीं है। उसके भी अपने अरमान हैं, उसके भी अपने सपने हैं। 1989 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ

अमेरिका में एक पिक्चर बनी थी, जिसका नाम था - 'Honey, I Shrunk the Kids'. मुझे लगता है कि भारत देश में वर्ष 2025 में पिक्चर बननी चाहिए - 'Honey, I Shrunk India's Middle-Class'. सर, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास से ऐसे टैक्स वसूला जाता है, जैसे हम किसी अधिकार से टैक्स ले रहे हैं और सुविधा अहसान मुताबिक दी जाती है। सर, नेस्ले इंडिया, जो इस देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में आती है, उसके आंकड़े आए। उन आंकड़ों में यह पता लगा कि उन्होंने आठ वित्तीय वर्षों में इस वर्ष सबसे कम ग्रोथ दर्ज कराई है। जब नेस्ले इंडिया के चेयरमैन से यह बात पूछी गई कि आप अपनी lowest growth पर क्यों आ गए, तो उन्होंने कहा कि भारत का मिडिल क्लास खरीद नहीं रहा है, भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। सर, मैं महंगी गाड़ी और महंगे मकानों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सस्ती गाड़ी और सस्ते मकान, जिन्हें मिडिल क्लास खरीदता है, उनकी डिमांड घटती जा रही है, उनका प्रोडक्शन घटता जा रहा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर है।

सर, सरकार द्वारा काफी चर्चा हुई कि हम मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की टैक्स रियायत लेकर आए हैं। मैं बतौर Charted Accountant यह बताना चाहता हूँ कि न ही यह टैक्स exemption है, न ही यह टैक्स डिडक्शन है, यह एकमात्र टैक्स रिबेट है। इस रिबेट का स्वागत हम सब करते हैं। हम सबको खुशी हुई, लेकिन मैं आपको इन तीनों में फर्क बताना चाहता हूँ और यह दिखाना चाहता हूँ कि इंडियन मिडिल क्लास से अभी भी चोर दरवाजे से कैसे इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। पहली बात, यह इनकम टैक्स exemption नहीं है। Exemption यह होता है कि एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही न, जैसे कि इस देश में खेतीबाड़ी से जो कमाई होती है, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। यह वह नहीं है। यह टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज़ करिए, आपने साल में 15 लाख रुपये कमाए और इनकम टैक्स डिडक्शन 12 लाख रुपये की मिली, तो तीन लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यह टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, यह टैक्स रिबेट है। अगर आपने साल में 12 लाख तक पैसा कमाया, आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख लाख से ज्यादा कमाए, फर्ज़ करिए, आपने 12 लाख, 1 हजार रुपये कमाए, तो आपके स्लैब के अनुसार, आपसे पूरे 12 लाख, 1 हजार पर इनकम टैक्स वसूला जाएगा।

दूसरी बात, कैपिटल गेन्स की करते हैं। आप अपना कोई मकान बेचते हैं, सोना बेचते हैं, equities बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उसके मुनाफे पर जो टैक्स लगता है, वह इस 12 लाख की सीमा में नहीं आएगा। उस पर आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। इस 12 लाख की रियायत से भारत देश में कितने लोगों को फायदा हुआ, यह भी समझने की आवश्यकता है। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं, जिसमें मात्र आठ करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और इनमें से मात्र तीन करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं, यानी कि आठ करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, पाँच करोड़ लोग ज़ीरो इनकम दिखाकर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। उनसे कोई इनकम टैक्स नहीं वसूला जाता है, लेकिन जो बाकी तीन करोड़ बचे हैं, वे ही इनकम टैक्स भरते हैं। इससे किन लोगों का फायदा हो रहा है, यह भी समझने की आवश्यकता है। सर, आप इसका मुकाबला करिए। सीएमआईई का डेटा बताता है कि इस देश में consumption के आधार पर 43 करोड़ भारतीय मिडिल क्लास में आते हैं। 43 करोड़ में से मात्र दो से तीन करोड़ लोगों को ही इसका फायदा होने जा रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन बाकियों के लिए क्या है?

वित्त मंत्री जी ने जब यह फैसला सुनाया, तब यह कहा कि इससे भारत की consumption बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी का चक्का, इकोनॉमी का पहिया चलने लग जाएगा। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन में भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि इस टैक्स रियायत से इस देश की consumption बढ़ने वाली नहीं है। अगर आप वास्तव में इस देश की खपत, यानी consumption बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स से साथ-साथ जीएसटी नाम का टैक्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी वह टैक्स है, जो इस देश का अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी भी देता है। जब गरीब आदमी अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए माचिस खरीदता है, तो वह उस पर भी जीएसटी देता है और जब अमीर आदमी सफर करने के लिए मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू खरीदता है, तो वह भी उस पर जीएसटी देता है। जीएसटी वे लोग भी देते हैं, जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं और जिन 80 करोड़ भारतीयों को सरकार फ्री राशन देती है, जीएसटी उनसे भी वसूला जाता है। सही मायने में अगर आप भारत में consumption यानी खपत को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी कम करना पड़ेगा और उसे स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा।

सर, मिडल क्लास इस देश की सबसे देशभक्त क्लास है, जो सबसे ज्यादा टैक्स देती है। साधारण पैंट शर्ट पहने हुआ मिडल क्लास का आदमी जब नौकरी से लौटते हुए मैट्रो की लाइन में खड़ा होता है, तो उसे यह चिंता नहीं होती कि वह घर जाकर कौन सी पिक्चर देखेगा या कौन सा पकवान खाएगा। उसे यह चिंता होती है कि वह अगले हफ्ते अपने बच्चों की फीस कैसे भरेगा, अपने बाबूजी का आपरेशन कैसे कराएगा। इसके अलावा वह यह भी सोचता है कि बहुत साल नौकरी कर ली, अब एक स्कूटी खरीद लेता हूं, लेकिन जब वह बाजार जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह स्कूटी जो 40,000 रुपये की मिलती थी, वह अब एक लाख की मिलने लगी है या एक ऑल्टो कार, जो पहले तीन-साढ़े तीन लाख रुपए की मिलती है, अब दस लाख रुपए की मिलने लगी है। सर, यह सच्चाई है और ऐसा इसलिए है, क्योंकि सैलरी बढ़ती नहीं है, बचत होती नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ती है।

सर, रिपोर्ट्स बताती हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में सैलरी औसतन मात्र तीन प्रतिशत ही बढ़ी है, जबकि फूड इन्फ्लेशन 10 प्रतिशत, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 15 प्रतिशत और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और न जाने कितने इन्फ्लेशन्स के आंकड़े ऊपर मंडरा रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले सैलरी मात्र तीन प्रतिशत बढ़ी है। देश का मिडिल क्लास एक बहुत बड़े debt trap में भी फंसने जा रहा है। मैं यह भी भविष्यवाणी आज करना चाहूंगा, क्योंकि भारत का household debt to GDP ratio आज 40 प्रतिशत पर खड़ा हो गया है। सरल भाषा में बताऊं, तो भारत का मिडिल क्लास परिवार आज रोजमर्रा के जीवन के लिए, अपने डेली एक्सपेंसेज के लिए लोन लेने पर मजबूर हो गया है, चाहे वह पर्सनल लोन हो, चाहे वह क्रेडिट कार्ड के जरिए हो या अन्य प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन से ब्याज पर पैसा लेना हो। यानि कि जो सैलरी एक तारीख को आती है, वह पहले ही आपके रोजमर्रा के जीवन के खर्चों के लिए ब्याज पर जो पैसा लिया हुआ है, उसके भुगतान में चली जाती है और भारत का मिडिल क्लास एक debt trap में फंसता चला जा रहा है। यह लोन कोई मकान बनाने के लिए या दफ्तर खरीदने के लिए या asset creation के लिए नहीं है। यह day-to-day expenses meet करने के लिए है, जो भारत के मिडिल क्लास को एक debt trap में खड़ा करता जा रहा है। सर, सैलरी तो

महीने की 7 तारीख को आती है, परंतु एक तारीख को ही मकान मालिक दरवाजा खटखटाने के लिए आ जाता है कि किराया दो। सारी उम्र काम करने के बाद एक मिडिल क्लास का आदमी सोचता है कि अंत में रिटायरमेंट के समय जमीन खरीदकर अपने लिए एक छोटा मकान बनाएगा। जमीन खरीद कर मकान बनाना तो छोड़िए, आज रियल एस्टेट के प्राइसेज़ मिडिल क्लास की अर्निंग्स के मुकाबले इतने ज्यादा हैं कि दो-तीन जन्म काम करने के बाद रिटायरमेंट लेने के बाद भी शायद वह 2 बीएचके अपार्टमेंट भी नहीं खरीद पाएगा। इसलिए मिडिल क्लास आज सरकार को वह गाना सुनाना चाहता है किः

'सारी उम्र हम मर-मर के जी लिए,
एक पल तो अब हमें जीने दो'।

सर, सच्चाई यह है कि मिडिल क्लास के घरों में जब कभी शादी का कार्ड आता है, तो उन्हें चिंता हो जाती है कि शगुन में कितना पैसा देना पड़ेगा और साथ ही साथ नया सूट सिलवाना पड़ेगा, ट्रेन का खर्चा हो जाएगा इत्यादि।

सर, मिडिल क्लास के साथ-साथ एक दूसरे बड़े मुद्दे को मैं आज इस वक्तव्य में आपके सामने पेश करना चाहूंगा, वह रेलवे का मुद्दा है। रेलवे का एक अतिरिक्त बजट आया करता था, जिसकी प्रथा बंद हो गई है। भारतीय रेल का महत्व इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि उसके लिए एक अतिरिक्त बजट सदन में पेश किया जाता था, क्योंकि अब रेल बजट पेश नहीं होता है, तो उस पर व्यापक चर्चा भी नहीं होती है। लेकिन इस वक्तव्य के माध्यम से मैं रेल बजट संबंधी कुछ चीजें आपके सामने अवश्य रखना चाहूँगा। इस यूनियन बजट 2025-26 में माननीया वित्त मंत्री जी ने 2,55,000 करोड़ का financial allocation रेलवेज़ के Capex के लिए माँगा है। यह 2009 से 2014 के बीच में लगभग 50,000 करोड़ होता था, जो आज 5 गुना बढ़ कर 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। इस पर व्यापक चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

सर, भारतीय रेल, जो भारत की लाइफलाइन कही जाती थी, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर मजबूरी न हो, तो शायद कोई यात्री रेल की ओर देखना भी न चाहे। रेल जनता की रेल जरूर बना रही है। इसका कारण यह है कि भारतीय रेल को अपनी पीआर, सोशल मीडिया कैंपेन्स और रील्स ज्यादा पसंद हैं, न कि रेल की सुविधाओं को कैसे बेहतर करना है, वह पसंद है। सर, भारतीय रेल एक समय इस देश की 140 करोड़ आबादी का गौरव और उम्मीद हुआ करती थी, गरीबों का सहारा हुआ करती थी, लेकिन आज मैं यह बताना चाहता हूँ कि भारतीय रेल की यह स्थिति है, अगर आप पूरे सबकॉन्टिनेंट की तमाम रेलवेज़ से कंपेयर करें, तो शायद यह बद से बदतर होती जा रही है।

सर, जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है, स्विट्जरलैंड की है, डेनमार्क की है, स्वीडन की है और अन्य देशों की है, उससे ज्यादा लोग भारतीय रेल में रोज़ सफर करते हैं। सर, इतना महत्व है भारत की रेलवे का! लेकिन कई बड़ी चिंताएँ आज भारत के एक आम रेल यात्री को सता रही हैं, जिनके लिए मैं चाहूँगा कि इस budgetary allocation के माध्यम से वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी इन्हें address करें। पहला है, घटती रफ्तार और बढ़ता किराया। सर, जहाँ दुनिया की ट्रैवल की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं भारतीय रेल, जो हमारी लाइफलाइन है, उसकी रफ्तार घट

रही है। पहले तो शताब्दी और राजधानी की स्पीड कम कर दी गई, ताकि वंदे भारत की स्पीड बढ़ा दी जाए और उसको fastest train घोषित किया जाए। लेकिन, अब जून, 2024 की रिपोर्ट बताती है कि वंदे भारत की भी स्पीड को कम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमारी रेल ट्रैक्स उतनी पर्याप्त नहीं हैं कि इतनी तेज रफ्तार पर वंदे भारत भाग सके। सर, आज हम विश्व गुरु बनने तो अवश्य चले हैं, लेकिन यह बात जाननी भी जरूरी है कि चीन और जापान की सबसे slowest रफ्तार पर चलने वाली ट्रेन भारत की सबसे fastest रफ्तार पर चलने वाली ट्रेन से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती है। अगर रेल धीमी होगी, तो देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था का चक्का धीमा चलेगा। सर, किराए की तो क्या ही बात करें! जिस वंदे भारत का प्रचार रेल मंत्री जी करते थकते नहीं हैं, आज उस वंदे भारत का किराया इतना है कि गरीब आदमी छोड़िए, आम आदमी भी उसे afford नहीं कर पा रहा है। सर, वित्तीय वर्ष 2013-14 में average fare per passenger per kilometer 32 पैसे हुआ करता था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 160 प्रतिशत बढ़ कर 66 पैसे हो गया है। रेल के किराए में इतना इजाफा देखा गया है। सर, हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने का वादा था, लेकिन हवाई चप्पल पहनने वालों को इतना निचोड़ दिया कि शायद अब वे रेल यात्रा के भी लायक नहीं रहे।

सर, दूसरी समस्या है, थर्ड एसी और सेकंड एसी के बुरे हालात हैं। थर्ड एसी, सेकंड एसी को एक समय पर लग्जरी माना जाता था, लेकिन आज वह जनरल बोगी से भी बुरी स्थिति में है। अगर थर्ड एसी, सेकंड एसी की टिकट मिल भी जाए, तो सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बैठेंगे, थोड़ी देर में कोई शख्स आकर कहेगा, भाई साहब, थोड़ा adjust करिए, थोड़ा सरकिए, हमें भी बैठने दीजिए। यह वास्तविकता है। आज सोशल मीडिया और तमाम तरीके के पोर्टल्स पर आप देखेंगे, तो क्या भारत सरकार आम रेल यात्री को आरामदायक यात्रा, आरामदायक सफर दे रही है, वह देख कर आप समझ जाएँगे। जैसे कहते हैं कि भारतीय रेल के एक यात्री के लिए हिंदी का सफर अंग्रेजी का सफर बन गया है। कई रूट्स पर आलू की बोरियों की भाँति लोगों को ठूँसा जा रहा है और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए, तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सर, यहाँ भेड़-बकरियों की तरह भोले-भाले लोगों को ट्रेन में ठूँसा जा रहा है और पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पर सिर्फ धक्का दिया जा रहा है। हमारे देश के भोले-भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझ कर स्वीकार कर लेते हैं।

सर, मैं तीसरी बड़ी रेल समस्या, जो कि mismanagement, अव्यवस्था है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सर, पहले तो रेल की टिकट मिलती नहीं, अगर मिल भी जाए, अगर आपने दो-ढाई-तीन महीने पहले टिकट बुक कराई हो, टिकट कंफर्म हो जाए, तो सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं। सर, आप अपना अनुभव देखिए। जब आप सबसे पहले अपनी ट्रेन में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं, तो आपको चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। अगर आप बुजुर्गों के साथ या घर-परिवार की महिलाओं के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक clean washroom तक आपको मुहैया नहीं कराया जाता। हालात ये हैं कि लोग मजबूर हैं प्लेटफार्म पर अखबार बिछा कर सोने के लिए और waiting area के नाम पर तो सिर्फ एक नेम प्लेट, एक बोर्ड लगा नजर आता है, और कुछ नहीं नजर आता। सर, ट्रेन पर चढ़ने से लेकर ट्रेन से उतरने तक अव्यवस्था की एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है।

7.00 **P.M.**

सर, यहां तक कि आज जब एक यात्री ट्रेन में इस ठंड के मौसम में एक लंबा सफर तय करता है और सोचता है कि थोड़ा आराम कर लूं, वह कंबल-चादर खोल कर ओढ़ने का प्रयास करता है, तो उस कंबल-चादर से बहुत बदबू आती है, बहुत दुर्गंध आती है। उसके जवाब में रेल मंत्री और रेल मंत्रालय बताता है कि हम महीने में एक बार कंबल धोते हैं। सर, अगर महीने में एक बार कंबल धोएंगे, तो सुगंध आएगी या दुर्गंध आएगी! मैं चाहूंगा कि सरकार इसका फैसला करे। पिछले दो वित्तीय वर्षों में hygiene-related complaints में 500 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। यह इस बात को दिखाता है कि हमारे देश की रेल hygiene standards को कितना compromise करती जा रही है।

सर, अगर प्लेटफॉर्म पर भूख लग जाए, तो आपको पानी वाली चाय, गंदे तेल में तले समोसे और छोले-भटूरे अवश्य मिल जाएंगे। इसी के साथ-साथ अगर आपने IRCTC का खाना बुक किया हो और रेल विभाग आपको खाना दे, तो जब आप वेज थाली मंगाएँगे, तो उसमें आपको complimentary मच्छर, कॉकरोच और कीड़े-मकोड़े भी नसीब हो सकते हैं। जब आप वेज थाली ऑर्डर करेंगे और ये आपको नसीब नहीं होंगे, तो सूखी रोटी, कच्चे चावल और पानी जैसी दाल तो अवश्य मिलेगी।

सर, महाकुंभ को लेकर कई बड़े-बड़े आयोजन किए गए और कहा गया कि भारतीय रेल बड़ी सक्रिय होकर महाकुंभ का आयोजन कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और आसपास के कई रेलवे स्टेशंस को बंद करना पड़ा, क्योंकि सरकार crowd management नहीं कर पाई। ...(**व्यवधान**)... मैं पूछना चाहूंगा कि महाकुंभ के लिए ये स्पेशल ट्रेनें कहां पर चल रही है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसके पास एक स्पेशल ट्रेन की कंफर्म टिकट है?

सर, मैं एक चौथी बड़ी जिस चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह है - आम आदमी से [£] । पहले तो IRCTC की website का interface कुछ इस प्रकार का है कि आप वहाँ से टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। जब टिकट बुक करने के लिए third party apps पर जाएंगे, तो वे आपसे मोटा कमीशन लेंगी। अब खुदा-ना-खास्ता आपकी यात्रा कैंसिल हो जाए, तो आपसे एक मोटा cancellation charge भी वसूला जाएगा। अब प्लेटफॉर्म टिकट की तो क्या बात करें। आपके सगे-संबंधी अगर आपको प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आएँ, तो प्लेटफॉर्म पर कितना खर्चा होता है, प्लेटफॉर्म टिकट किस रेट पर बेची जाती है, वह आपको पता है। हालात ऐसे हैं कि अगर आप वहां प्लेटफार्म पर 'Bisleri' का पानी खरीदिए, तो 'Bisleri' का नकली पानी आपको दिया जाता है। वहाँ ऐसे-ऐसे brands के chips, chocolates, biscuits और पानी दिये जाते हैं, जिन brands का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा।

सर, पांचवी समस्या ज्यादा से ज्यादा normal trains चलाने की आवश्यकता है। बुलेट ट्रेन और वंदे भारत से ज्यादा किफायती यात्रा normal trains में हो जाए, तो देश का आम आदमी खुश

[£] *Exupnged as ordered by the Chair.*

हो जाएगा। आज इस भीषण महंगाई और भयंकर बेरोजगारी का आलम कुछ इस प्रकार है कि लोगों के पास समय ही समय है, लेकिन पैसा नहीं है। भले ही आप आधा घंटा या एक घंटा रफ्तार धीमी कर दें, लेकिन 2000 में मिलने वाली ट्रेन की टिकट को 500 या 600 कर दें, तो आम आदमी का बहुत भला हो जाएगा।

सर, इसी के साथ-साथ मैं बुजुर्गों की बंद हुई सब्सिडी पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार ने वर्ष 2020 में बुजुर्गों को रेल टिकट पर मिलने वाली जो सब्सिडी थी, वह बंद कर दी, जिसके चलते सरकार ने काफी ढोल बजाकर कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उसने 2,242 करोड़ रुपए 150 मिलियन senior citizens से वसूल किए हैं। यानी कि रेलवे की इनकम में लगभग 2,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। अब बताइए कि क्या हम अपने बड़े बुजुर्गों की हड्डियां निचोड़ कर भी पैसा वसूलेंगे? एक सीनियर सिटीजन पूरी जिंदगी भर काम करने के बाद यह सोचता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद तीर्थ करने जाऊंगा, धार्मिक स्थानों पर जाऊंगा, लेकिन आज हम यह सब्सिडी बंद करके उन पर महंगाई का एक बड़ा burden डाल रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी को और रेल मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर ये बड़े-बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो शायद ये आप ही के लिए दुआएं मांगेंगे।

सर, अब यह मेरा आखिरी पॉइंट है। मैं इसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहले सुरक्षित यात्रा की गारंटी हुआ करती थी, लेकिन आज कोई गारंटी नहीं है। रेल मंत्री कहते हैं कि हमने 'कवच' नामक एक नया सिस्टम लागू किया है, जिससे अब रेल दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन कवच सिस्टम लागू होने के बाद क्या एक महीना भी ऐसा बीता, जब रेल दुर्घटना का कोई समाचार हमारे सामने नहीं आया? बीते 5 सालों में 200 से ज्यादा rail accidents हुए हैं, जिनमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और अनगिनत लोग injured हुए हैं। C&AG की अभी जो रिपोर्ट आई है, वह यह बताती है कि वित्तीय वर्ष 2018 से 2021 के बीच जितने भी rail accidents हुए हैं, उनका 75 प्रतिशत कारण lack of track maintenance रहा है। यानी कि rail track की maintenance में जो कमी है, उसकी वजह से रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह हाउस भारतीय रेल को ढाई लाख करोड़ रुपए sanction करने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि रेलवे विभाग कम से कम track maintenance तो ठीक-ठाक तरीके से कराएगा। सर, इसी के साथ-साथ जितनी भी ये समस्याएं बताई गईं हैं, अगर रेल मंत्री रील से ज्यादा रेल पर ध्यान दें, तो अवश्य इनका इलाज हो जाएगा। मैं एक आम रेल यात्री के अनुभव को एक्सप्लेन करते हुए चार पंक्तियां आपके सामने पढ़ना चाहूँगाः

अजब गजब चल रहा है रेल का खेल,
हमेशा गाड़ी लेट तो कहीं ब्रेक फेल।
महंगी टिकट के बाद भी सीट मिलने की आस नहीं,
सुरक्षित पहुंच जाएं इस बात पर विश्वास नहीं।
भिड़ रही हैं ट्रेनें, मर रहे हैं लोग,
रेल मंत्री लगा रहे हैं अमृत काल का भोग।
बुकिंग से लेकर टिकट कैंसिलेशन तक दर्जनों टैक्स का जाल,
भेड़ बकरियों की तरह ठूँसे जा रहे हैं लोग, कैसे मनाएं अमृत काल।

बेरोजगारों के देश में हो रही है बुलेट ट्रेन की बात,
सरकार कैसे समझेगी आम आदमी के मन के जज्बात।
रेल मंत्री को रेल नहीं, रील पसंद है,
टिकट के नाम पर मनमाना बिल पसंद है।
खाना मांगने पर मिलता है कॉकरोच, छिपकली और मच्छर,
इतना बदहाल हो चुका है, हमारी लाइफलाइन का स्ट्रक्चर।
आखिर कैसे सुधरेगी व्यवस्था, कैसे बदलेंगे हालात,
सरकार समझने को तैयार नहीं आम आदमी के जज्बात।

सर, मैं अपने अगले भाग में, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आई है, उसका क्या आर्थिक इंपैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सर, पहले तो 4 फरवरी, 2025 को अमेरिका की सेना का एक माल ढोने वाला बड़ा विमान 104 भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए भारत आया। पता लगा कि उन भारतीयों के हाथ में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें थीं, बेड़ियां बांध कर उनको लाया गया। बताया जा रहा है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय प्रवासी हैं, जो बिना दस्तावेज के वहां रह रहे हैं, जिनको अब एक-एक करके अमेरिका भारत वापस भेजने जा रहा है। सर, हम चले तो विश्व गुरु बनने थे, वहां अमेरिका ने अपनी मिलिट्री लगा कर हजारों लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सर, मैंने बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका के किसी नागरिक को डिपोर्ट होने की खबर तो नहीं पढ़ी, लेकिन भारतीयों के साथ जो अमानवीयता हुई, उसकी खबर जरूर पढ़ी।

सर, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि illegal immigration को तो शायद इस सदन में बैठा कोई भी व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन नाउम्मीदी के शिकार जो युवा रोजगार की तलाश में वहाँ गए, उनके साथ जो inhuman treatment हुआ, उसको लेकर तो हमें आवाज बुलंद करनी ही चाहिए। 40 घंटे तक उनके हाथों और पैरों में बेड़ियाँ बांध कर रखा गया, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। सर, मुझे लगता है कि इसको लेकर शायद इस देश के हर नागरिक का खून खौलता होगा। इसी उदाहरण के सामने हमारे पास एक और उदाहरण है और वह यह है कि इस दुनिया का एक बहुत छोटा-सा देश कोलंबिया है। जब कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो को पता लगा कि अमेरिका से एक सेना का माल ढोने वाला विमान इसी प्रकार कोलंबिया के नागरिकों को, जो बिना दस्तावेज के वहां पाए गए, कोलंबिया छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उस विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं कोलंबिया सरकार का अपना विमान भेजूंगा और पूरे सम्मानजनक तरीके से मैं अपने नागरिकों को वापस लाऊँगा। सर, वास्तव में कोलंबिया, जो डट कर अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, इस मायने में तो वह असल विश्व गुरु बना।

सर, मैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी पूछना चाहूँगा कि वे इन नागरिकों को, हमारे भाइयों-बहनों को रिसीव करने के लिए खुद क्यों नहीं गए? उनको वापस लाने के लिए हमने भारतीय वायु सेना का अपना जहाज क्यों नहीं भेजा? जब हमारे पास पहले से ही सूची थी कि इन 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो हमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्या अमेरिकी दूतावास से किसी को बुलाया, किसी से चर्चा की गई, अपना विरोध दर्ज कराया? अंत में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा - इन तमाम राज्यों के ये लोग थे, जो

आए, लेकिन प्लेन को न जाने किस कारणवश अमृतसर में उतारा गया। मैं चाहूँगा कि इस विषय पर भी, इस स्ट्रेटेजिक डिसीजन पर भी माननीय विदेश मंत्री जी सदन का ध्यान आकर्षित करें।

सर, क्या आपने कभी सुना है कि स्विटजरलैंड का कोई नागरिक, डेनमार्क का कोई नागरिक, ब्रिटेन का कोई नागरिक, नीदरलैंड का कोई नागरिक नौकरी की तलाश में डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका गया हो? आपने नहीं सुना होगा। भारतीय ही क्यों मजबूर है डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका पहुंच कर, वहां पर मेहनत-मजदूरी, छोटी-मोटी लेबर का काम करने के लिए? वह इसलिए, क्योंकि इस देश में तमाम सरकारों ने हमारे देश के युवाओं को बेरोजगार रखा। सर, वादा तो था 2 करोड़ नौकरियां देने का, लेकिन सरकार वह 2 करोड़ नौकरियां दे नहीं पाई। शायद lack of opportunities और unemployment के चलते लोग अमेरिका जाने को मजबूर हो गए। सर, मैं बताना चाहूँगा कि आप इसको इस परिपेक्ष्य में भी देखने की कोशिश करें कि अमेरिका के सबसे पिछड़े राज्यों में एक राज्य है मिसिसिप्पी। मिसिसिप्पी राज्य में अमेरिका की सबसे lowest per capita income है। मिसिसिप्पी की भी lowest per capita income 48,000 डॉलर प्रति वर्ष है। सर, उसका compare भारत की per capita income से कीजिए। भारत की per capita income मात्र 1,160 डॉलर है। कहां अमेरिका की सबसे गरीब राज्य की per capita income 48,000 डॉलर प्रति वर्ष है, यानी मिसिसिप्पी में रहने वाला एक आदमी साल में औसतन 48,000 डॉलर कमाता है, वहीं एक भारतीय औसतन 1,160 डॉलर कमाता है। सर, ऐसी स्थिति में क्यों नहीं कोई बेहतर जिंदगी के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाने पर मजबूर होगा? सर, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के निर्णय का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट भारत पर पड़ने जा रहा है, मैं उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सर, सबसे पहले मैं एच-1बी वीज़ाज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एच-1बी वीज़ाज़, जो अब भारी रिस्ट्रिक्शंस के साए में फंसे हुए हैं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वह भारतीयों को होगा। सर, वर्ष 2023 में 3,86,000 एच-1बी वीज़ा एप्लीकेशंस अमेरिकी सरकार को आईं, जिनमें से 72% एप्लीकेशंस भारतीयों की थीं। यानी कि अगर एच-1बी वीज़ा मिलना मुश्किल होगा, तो उसकी सबसे ज्यादा मार भारत के स्किल्ड लोगों पर पड़ेगी। दूसरा, अगर स्ट्रिक्टर एच-1बी वीज़ा होगा और एच-1बी वीज़ा वालों के वेज़ में मॉड्यूलेशन की जाएगी, तो उसके चलते वे तमाम कंपनियां, जो अमेरिका में भारतीयों को रोजगार देती हैं, वे भारतीयों को निकालकर लोकल अमेरिकंस को जॉब्स देंगी, जिसके चलते एक बहुत बड़ी बेरोजगार हिंदुस्तानियों की फौज परेशान हो जाएगी और वह भारत वापस आने को मजबूर हो जाएगी।

सर, तीसरा पॉइंट ट्रंप के प्रपोज्ड टैरिफ्स के बारे में है। सर, ये टैरिफ्स क्या हैं, जिनकी इतनी चर्चा होती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ्स लगाने जा रहा है, प्रपोज्ड टैरिफ्स लगाने जा रहा है? मैं उसको एक सरल उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। टैरिफ को आप एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी के चश्मे से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए, अमेरिका में बैठा एक बायर हिंदुस्तान के एक मैन्युफैक्चरर से 100 रुपये की एक शर्ट खरीदता है। आज उसे वह शर्ट 100 रुपये की पड़ती है, लेकिन अगर अमेरिका की यह नई हुकूमत, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 20% की टैरिफ शर्ट्स पर लगा दे, ऐपेरेल्स पर लगा दे, तो वह 100 रुपये की शर्ट अमेरिका के बायर को 100 रुपये की नहीं, 120 रुपये की पड़ेगी। फिर, अमेरिका का बायर हिंदुस्तान से 120 रुपए की शर्ट खरीदने की बजाय 108 रुपए की, 105 रुपए की, 104 रुपए की वियतनाम, फिलिपींस और

बंगलादेश जैसे देशों से खरीदेगा। यह है टैरिफ का खेल, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स घटेंगे, मांग घटेगी, कारखाने बंद होंगे और रोजगार जाएगा।

सर, पहला, आईटी एक्सपोर्ट्स - भारत 245 बिलियन डॉलर का सालाना आईटी एक्सपोर्ट्स करता है, जिसका 80% एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को होता है। उसका सबसे पहले प्रहार आईटी एक्सपोर्ट्स पर होगा। दूसरा, 15 से 25% यूएस टैरिफ्स इंडियन ऐपेरेल्स, यानी टेक्सटाइल्स पर लगने जा रहे हैं, जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको दिया। इसके चलते भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की कॉस्ट एडवांटेज घट जाएगी, सोर्सिंग और बाइंग हिंदुस्तान से बंद हो जाएंगी और एस्टीमेट्स बताते हैं कि भारत के टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स इंडस्ट्री की करीब 2 मिलियन जॉब्स बंद हो जाएंगी, जिनमें से मेरे पंजाब के लुधियाना में बहुत सारे टेक्सटाइल हब्स हैं, तमिलनाडु में हैं और गुजरात में हैं, उन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

सर, इसके साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज्ड टैरिफ्स ऑन इंडियन फार्मास्यूटिकल्स लगाने जा रही है। आज भारत यूएस को जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जेनेरिक ड्रग्स, जेनेटिक दवाइयां एक्सपोर्ट करता है, उन सब पर यह इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूएसए की जितनी खपत है, उसकी 40% जेनेरिक दवाइयां और ड्रग्स भारत सप्लाई करता है। इतना बड़ा प्रहार भारत की इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पर होने जा रहा है, जिसके चलते रेवेन्यू लॉसेस और जॉब लॉसेस होने जा रहे हैं।

तीसरा प्वाइंट, प्रपोज्ड 25% यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन ऑटो कंपनीज़ - सर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर 25% की ड्यूटी लगाने जा रही है, जिसके चलते 14 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड इंपैक्ट होने जा रहा है। इसके चलते भारत में मैन्युफैक्चर हो रहीं ऑटोमोबाइल्स की डिमांड घटेगी, एक्सपोर्ट घटेगा, कारखाने बंद होंगे और 10 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा सकती हैं।

सर, चौथा और महत्वपूर्ण प्वाइंट यह है कि एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की फौज भारत की ऑलरेडी बेरोजगार फौज में जुड़ जाएगी। सर, आप पूछिए, कैसे? सर, 7 लाख, 25 हजार वे लोग जो बिना दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं, जिन्हें अमेरिका कह रहा है कि हम भारत भेज देंगे; एक मिलियन वे लोग, जिनका ग्रीन कार्ड अभी पेंडिंग है, उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल हो जाएगा; लाखों एच-1बी वीज़ा एप्लीकेंट्स, जिनको एच-1बी वीज़ा मिलना अब नामुमकिन-सा हो गया है; उनके अतिरिक्त, भारत में जो टेक्सटाइल्स, फार्मा, आईटी और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें jobs lay offs होंगे। यानी, इन लाखों unemployed लोगों की फौज भारत आकर भारत की ऑलरेडी unemployed लोगों की फौज में जुड़ जाएगी। उसको हम इस इकोनॉमिक साइकिल में कैसे reintegrate करेंगे, कैसे इस unemployment और under employment का सामना करेंगे?

सर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के निर्णयों का भारत पर जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा, उसके संदर्भ में मेरा आखिरी प्वाइंट यह है कि भारत की foreign inward remittances घट जाएंगी, भारत का forex reserves घटेगा। सर, वर्ष 2024 में documented and undocumented अप्रवासी भारतीय, जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने कुल मिलाकर 111 बिलियन डॉलर्स भारत भेजे। यानी, वहां पर जो आदमी रहता है और कमाई करता है, वह उस पैसे को हिंदुस्तान भेजता था, ताकि हिंदुस्तान में उसका जो परिवार है, उसके जो बूढ़े मां-बाप, बीवी-बच्चे और भाई-बहन हैं, वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। जब उनकी नौकरियां ही नहीं रहेंगी, जब वे पैसा ही नहीं कमाएंगे,

तो वे क्या पैसा भेजेंगे? जब वे पैसा ही नहीं भेजेंगे, तो भारत के forex reserves घटेंगे और forex reserves घटने की वजह से रुपया और कमज़ोर होगा तथा डॉलर और मज़बूत होगा।

सर, इस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के प्रपोज़्ड टैरिफ की वजह से भारत के corporate tax collections में तीन से चार हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान होने जा रहा है और इंफोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां अब 80 से 90 प्रतिशत अमेरिकी लोगों को नौकरियां देंगी। वे भारतीय, जो H-1B Visa पर वहां काम करते रहे हैं, उनको निकालने का काम शुरू होने जा रहा है। सर, अमेरिका जो कहता है, उसे एक वफादार दोस्त की तरह भारत हमेशा से करता रहा है। अमेरिका कहता है कि ईरान से कम तेल खरीदो, तो हम कम तेल खरीदते हैं, अमेरिका कहता है कि मुझसे वैपंस खरीदो, तो हम डिफेंस हेलीकॉप्टर्स उनसे खरीदते हैं, अमेरिका कहता है अमुक देश पर मैंने सैंक्शंस लगा दिये हैं, उस पर restrictions लगा दिए हैं, आप उसके साथ अपना व्यापार बंद कर दो, तो हम व्यापार बंद कर देते हैं, अमेरिका कहता है रूस से डिफेंस एयर सिस्टम ना खरीदो, तो हम उसे निलंबित कर देते हैं, लेकिन उसकी इन सारी चीज़ों को मानने और एक वफादार दोस्त होने के नाते भारत को मिलता क्या है?

सर, सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत में एक बहुत बड़े वर्ग ने और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने ट्रम्प को जिताने के लिए सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाया कि ट्रम्प चुनाव जीत जाए। उन्होंने न जाने कितने ट्वीट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर वीडियोज़ बना कर अपलोड किए कि ट्रम्प जीत जाए, यहां तक कि कुछ लोगों ने तो हवन और अनुष्ठान भी किए कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बन जाएं।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): आप मानते हैं कि हवन में शक्ति है।

श्री राघव चड्ढा: लेकिन उसके बदले में हमें हासिल क्या हुआ, मैं वह बताना चाहता हूं। सर, पहला झटका जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, वह भारत को दिया। सर, 104 भारतीय, जो वापस आए हैं, जिनके हाथों में ज़ंजीरें और पैरों में बेड़ियां थीं, उनके लिए भी चार पंक्तियां सुनाता हूं। आप ग़ौर फरमाइएगा:

सपना था कि अमेरिका जाकर कुछ कमाएंगे
यह नहीं पता था कि ऐसे बांध कर वापस लाए जाएंगे
हाथों में हथकड़ी, पैरों में बंधी रही बेड़ियां
दर्द से टूटती और चटकती रहीं एड़ियां
कस के बांधा ज़ंजीरों से, जैसे कोई सामान
टपकते आंसू सुनाते हैं क्रूरता की दास्तान
सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मंज़र
मगर अपनों ने ही घोप दिया पीठ में ख़ंजर
क्या बीती होगी उन पर, ये वही जानेंगे
उनके ज़ख्मों को विदेश मंत्री नहीं पहचानेंगे
हर चेहरे पर लिखी है क्रूरता की कहानी
गुनाह सिर्फ इतना कि वे हैं हिंदुस्तानी।

सर, अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए devaluation of the Indian rupee पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, आज रुपया all-time low पर है। जब मई, 2014 में यह सरकार बनी थी, तब एक डॉलर 58 रुपये के आसपास मंडराता था। आज एक डॉलर 87 रुपये के आसपास मंडरा रहा है, which is an all-time low. सर, रुपया कोई कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है, रुपया सिर्फ एक करेंसी भी नहीं है, रुपया हमारे देश की प्रतिष्ठा है। जब करेंसी गिरती है, तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तमाम देश दूसरे देश को कितना सम्मान देना है, यह इस बात से भी तय करते हैं कि उसकी करेंसी की कितनी वैल्यू है। अगर हमारी इंटरनेशनल पहचान कमज़ोर होती है, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होती है।

सर, जैसे-जैसे रुपया गिरता है, वैसे-वैसे हमारे देश में इंफ्लेशन बढ़ती है। इसलिए, क्योंकि हम बहुत सारी वस्तुएं इम्पोर्ट करते हैं, तो इम्पोर्टेड इंफ्लेशन भी हमारे देश के टोटल इंफ्लेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि मान लीजिए हम पिछले साल अमेरिका से एक शर्ट 74 रुपये की खरीदते थे, क्योंकि एक डॉलर 74 रुपये का था। आज वही शर्ट खरीदने के लिए हमें 86-87 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि भारत के लिए वह कॉस्ट बढ़ेगी, भारत के buyer के लिए वह कॉस्ट बढ़ेगी और in turn वह ज्यादा कॉस्ट आम आदमी को pass on की जाएगी।

सर, पांच प्रकार की इंफ्लेशन बढ़ रही है, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिरता जा रहा है, रुपया न्यूनतम स्तर पर आकर खड़ा हुआ है। पहला है, फूड इंफ्लेशन। सर, भारत edible oil और pulses बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट करता है। भारत की खपत का 56 प्रतिशत edible oil हम इम्पोर्ट करते हैं और भारत की pulses की consumption का 15 प्रतिशत quantity इम्पोर्ट करते हैं। जब हम इतनी बड़ी quantity में ये चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, तो अगर रुपया गिरेगा, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होगा, तो हमारा फूड इंफ्लेशन बढ़ेगा।

दूसरा इंफ्लेशन जो बढ़ेगा, वह है एनर्जी इंफ्लेशन। सर, हम अपने क्रूड ऑयल, यानी कि पेट्रोल-डीज़ल और जेट फ्यूल्स को इम्पोर्ट करते हैं। भारत की जितनी खपत है, उसका 85 प्रतिशत क्रूड ऑयल अन्य देशों से इम्पोर्ट करते हैं, उसके अतिरिक्त कोल और नेचुरल गैस भी इम्पोर्ट करते हैं। जब रुपया गिरेगा तो एनर्जी बास्केट की वस्तुओं का दाम भी बढ़ेगा और ये और अधिक महंगी होती जाएंगी। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो हर चीज पर इम्पैक्ट होगा। चाहे वह रोटी, कपड़ा, मकान, सब्जियां, फल और दूध ही क्यों न हो? इसी के चलते जब क्रूड ऑयल अंतरराष्ट्रीय बाजार में घटता भी है, तो उसका लाभ हम अपने नागरिकों को नहीं दे पाते, क्योंकि भारत सरकार की जेब ढीली होती रहती है, क्योंकि रुपया गिर रहा है और हमें डॉलर खरीदने के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ता है। सर, तीसरा इन्फ्लेशन 'Devaluation of Indian rupee' के चलते होगा, वह 'Healthcare inflation है।' Bulk drugs, medical equipments और healthcare consumables बड़ी तादाद में अन्य देशों से भारत खरीदता है, जिसके सारे contracts dollar में settle किए जाते हैं। इसके चलते रुपये गिरने की वजह से healthcare के items भी महंगे होते जाएंगे। चौथा इन्फ्लेशन 'Education inflation' है। भारत के लाखों बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। मां-बाप रुपये में कमाते हैं, लेकिन tuition fee, accommodation fee, living expenses ये तमाम चीज़ें डॉलर में खर्च करने पर मजबूर होते हैं, इसलिए 'Devaluation of

the Indian rupee' अगर किसी को hit करेगा, तो उन लोगों को करेगा, जो विदेश में पढ़ रहे हैं। आज से चार साल पहले एक संपन्न परिवार अगर अपने बच्चे को United States of America में चार साल का under-graduation course कराने के लिए भेजता था, तो करीब-करीब एक करोड़ रुपये का खर्चा आता था। आज, क्योंकि डॉलर इतना मजबूत और रुपया इतना कमजोर हो गया है, यह अमाउंट बढ़कर दो से ढाई करोड़ रुपये हो गया है। सर, इसी के साथ-साथ मैं बताना चाहूंगा कि गिरते हुए रुपये के चलते पांचवीं बड़ी inflation जो इस देश में होने जा रही है, वह 'Electronics inflation' है। सर, major electronic और electronic components भारत import करता है। ...(**व्यवधान**) ...

उपसभाध्यक्ष (**डा. दिनेश शर्मा**): आप समाप्त कीजिए।

श्री राघव चड्ढा: सर, मैं समाप्त कर रहा हूं। भारत import करता है। इन सारे electronic items की settlement USD में होती है। जब रुपया गिरता है, तो भारत में ये सारे पदार्थ महंगे मिलेंगे। यानी महंगा laptop, महंगा phone, महंगा tablet, महंगा iPad और electronic manufacturing units, जो input के लिए electronic components import करते हैं, वह भी महंगा होता जाएगा। सर, अंत में मैं SBI की एक report क्वोट करना चाहूंगा, जो यह बताती है कि अगर रुपया पांच प्रतिशत गिरता है, तो भारत में इन्फ्लेशन प्वाइंट फाइव परसेंट बढ़ती है। 'Direct correlation between decline of the Indian Rupee and increase in the inflation.' ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (**डा. दिनेश शर्मा**): धन्यवाद, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राघव चड्ढा: सर, अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि कई बार राजनैतिक बयान आते हैं, जब रुपया गिरता है। सर, सिर्फ 30 seconds में समाप्त कर रहा हूं। सर, वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे और इस सरकार में भी मंत्री रहे हैं। अब तो वे लोक सभा में एमपी हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, जब रुपया गिरा था। उन्होंने कहा था कि "The worth of the Indian rupee against the dollar was equivalent to Rahul Gandhi's age when UPA came to power. Today, it is equal to Sonia Gandhi's age, and, very soon, it will touch Manmohan Singh's age." आज वे कहां हैं? आज वे बयान क्यों नहीं देते हैं, आज रुपये पर चिंता क्यों नहीं करते? अब कोई ध्यान क्यों नहीं देता है? रुपये पर बयान क्यों नहीं देता, रुपया तो हर दिन गिर रहा है ...(**समय की घंटी**)... अब गिरते रुपये पर कोई ज्ञान क्यों नहीं देता, यह मैं पूछना चाहूंगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**डा. दिनेश शर्मा**): आपको बहुत समय मिला। राघव जी, धन्यवाद। Next, Shri Ramji, Bahujan Samaj Party; not present. Shri Sanjay Seth; ten minutes.

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं इस ऐतिहासिक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट केवल आर्थिक प्रगति का मार्ग तय नहीं कर रहा है, बल्कि

देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव भी रख रहा है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए अपनी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने आठवीं बार लगातार बजट पेश करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सर, इस बार का बजट 50 लाख, 65 हज़ार करोड़ रुपये का है। जो पिछले बजट की तुलना में 7.4 परसेंट अधिक है।

सर, माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश की रक्षा के लिए विशेष ध्यान देते हुए 6 लाख, 81 हज़ार करोड़ रुपये इस बजट में रखे हैं। यह कांग्रेस के शासन के समय में दी जाने वाली राशि से 168 परसेंट अधिक है। दूसरी चीज़, जो बार-बार विपक्ष इस वक्त कहता रहा है कि इसमें मिडिल क्लास को तो बेनिफिट मिल गए, लेकिन गरीब और किसान के लिए कुछ नहीं मिला है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में कृषि मंत्रालय के लिए जो बजट ऐलोकेट होते थे, उससे 362 परसेंट अधिक बढ़ाकर 1.37 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ गाँव के विकास के लिए भी 1 लाख, 88 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, क्योंकि मोदी जी की यह सोच है कि गाँव का विकास होगा, तो देश का विकास होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यूपीए सरकार की सोच सिर्फ अमीरों के लिए नीतियाँ बनाने की रही है, लेकिन मोदी जी का मंत्र है — 'स्वस्थ भारत-समृद्ध भारत।' इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 99 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का बजट दिया है।

महोदय, महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 44.49 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है, जोकि पिछले साल की तुलना में 37.25 परसेंट अधिक है। महोदय, कांग्रेस के दौर में आम जनता पर टैक्स का बोझ लादा जाता था। 2014 तक 2.5 लाख रुपये से ऊपर की इन्कम पर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 12 लाख रुपये तक की इन्कम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह आम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सबसे बड़ी छूट है।

महोदय, 2014 से पहले देश में एमएसएमईज़ तो थे, लेकिन उनकी सरकार में इस सेक्टर पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था, परंतु आज मोदी जी की सरकार में एमएसएमईज़ हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ बन चुके हैं। महोदय, 2020-21 में एमएसएमई सेक्टर में जहाँ 3 लाख, 95 हज़ार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता था, वहीं यह 2024-25 में बढ़कर 12.3 लाख करोड़ हो गया है। एमएसएमई एक्सपोर्ट करने वालों की संख्या 2020-21 में 52 हज़ार, 849 थी, जो अब बढ़कर 1 लाख, 73 हज़ार, 350 हो गई है। महोदय, एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में बड़े कदम उठाए गए हैं। माइक्रो इंटरप्राइज़ के लिए पहली बार एक customized credit card scheme शुरू की गई है, जिसमें 5 लाख रुपये तक की लिमिट होगी और पहले साल में 10 लाख क्रेडिट काड्र्स बनाए जाएंगे। महोदय, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को आसान ऋण मिले, इसके लिए loan guarantee cover 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें आप बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं। महोदय, इसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट करने वाले एमएसएमईज़ के लिए 20 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन की भी सुविधा दी गई है। 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जा रहा है।

महोदय, इस बजट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इस बजट में जो इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, वह यह है कि 1 करोड़ युवाओं के लिए internship कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे वे बड़े उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इसमें 1.5 लाख से अधिक स्टार्ट-अप्स कार्यरत हैं

और अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने लिए भी 1 हज़ार करोड़ रुपये का venture capital fund लाँच किया गया है।

महोदय, भारत के युवा केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बने हैं। आज Make-in-India, आत्मनिर्भर भारत, Start-up India, Digital India and Stand-up India जैसी योजनाओं ने युवाओं के लिए अनगिनत अवसर खोले हैं। महोदय, मोदी सरकार ने स्टार्ट अप्स के लिए एक नई ऊँचाई पर पहुँचने का बड़ा ऐलान किया है। 10 हज़ार करोड़ रुपये का एक फंड, फंड ऑफ फंड्स के नाम से स्टार्ट-अप्स के लिए बनाया गया है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी।

महोदय, हमारी सरकार का विज़न एकदम स्पष्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। इस दिशा में प्रधान मंत्री मोदी जी द्वारा पिछले दस सालों में अभूतपूर्व काम हुए हैं। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2004 में 65 हज़ार, 569 किलोमीटर था, जो 2014 में बढ़कर 91 हज़ार, 287 किलोमीटर हो गया था और अब 2024 में, 1 लाख, 46 हज़ार, 145 किलोमीटर तक पहुँच गया है।

महोदय, यूनियन बजट में घर खरीदने वालों के लिए भी बहुत बड़ी छूट दी गई है। दो self occupied घरों पर annual value शून्य रहेगी और दूसरे घर पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह उन लोगों के लिए राहत है, जो दूसरा घर खरीदना चाहते थे। होम लोंस में भी काफी बड़ी छूट मिली है। आरबीआई ने अभी 25 बीपीएस की कटौती की है, जिससे 20 साल के लोन की अवधि की ईएमआई पर 1.8 परसेंट की कमी आएगी। इससे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लोन का बोझ हल्का होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए, तीन करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 5,36,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आज वहाँ डबल इंजन की सरकार है, जिसके चलते केंद्र सरकार से अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है, जिससे राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढाँचे के विकास गति तेज हो रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में यूपी को केंद्रीय करों से 2,55,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो प्रदेश के विकास के लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता है। केंद्र की 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत, यूपी को अब तक 10,795 करोड़ रुपये मिले हैं। यूपी को केंद्रशासित योजनाओं के लगभग 87,000 करोड़ रुपये तथा अन्य केंद्रीय योजनाओं में 13,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है, जबकि केंद्रीय वित्त आयोग से भी उत्तर प्रदेश को दस हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। 2024-25 के बजट में यूपी को 3,61,000 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि इस बार इसे बढ़ाकर चार लाख करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया है, जिससे प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 96 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर काम जारी है, जिनकी कुल लंबाई 2,600 किलोमीटर होगी। आज वहाँ पर एक्सप्रेसवेज़ का जाल बिछ रहा है। वहाँ पर आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, वहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसी तरीके, हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। यह 1,334 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। पहले चरण में इसका 1,01,590 स्क्वायर मीटर टर्मिनल होगा और 3.9 किलोमीटर का रनवे होगा। राज्य को मिलने वाली केंद्रीय सहायता और बजट आवंटन में वृद्धि हुई है, जिससे यूपी देश का सबसे तेजी से विकसित होता राज्य बन गया है। यह डबल इंजन की सरकार का प्रभाव है कि आज उत्तर प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है,

जहाँ बुनियादी ढाँचे, कनेक्टिविटी और औद्योगिकीकरण में क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निवेशक लाखों-करोड़ों रुपये का निवेश करने के लिए आ रहे हैं। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Mr. Chairman, Sir, a number of speakers properly explained how this Budget fails to address the genuine concerns of common people of our country and how the proposals are detrimental to the interest of economy. I do join with them. Six speakers from my State, cutting across political lines, were raising certain genuine concerns related to the State of Kerala and thereby certain issues related to the federal structure of our country. I am in full support with them.

Sir, the fact is that the economy is in deep crisis; there is no doubt at all. Let me quote you one example from an answer furnished today in the Rajya Saba. The internal and external debts of our country in the year 2019-2020 was Rs.100 lakh crores, approximately. After four years, in 2023-24, it has increased to Rs.171.7 lakh crores! That means, during the last five years of this Modi Government's regime, there is an increase of Rs.67 lakh crore in the form of internal and external debt. This is one of the harsh realities which we have to understand. The more they chant 'Modi, Modi', the more Indian rupee is going down. This is a fact.

The Household Consumption Survey clearly states that 34 per cent of our population is spending just below Rs.100 per day. While we talk about this Budget, 93 per cent of the total workforce is in the unorganised sector, and this number is increasing day by day because contractual labour has become the order of the day. What does this Budget offer for the unorganised sector? There is a consistent demand from all the progressive sections and trade unions to include them in the ESI scheme. What is the Government's response about inclusion of these workers in the ESI scheme? There is nothing to offer.

The legally-enforceable MSP is one of the demands of the farming community. There have been a lot of agitations. We have witnessed these agitations. But, what is the fate of those promises? I had a chance to ask a question to the hon. Union Minister the other day, and his answer was quite evasive. By always talking about Jawaharlal Nehru and UPA period, how can they justify themselves? They have to prove themselves that they are doing something meaningful. With just rhetoric, can they cover up all their failures? How many missions have been announced by this Government? 'N' number of missions have been announced. I think even the Ministers don't know the exact numbers. They keep on announcing one after another mission or scheme. I request, through you, Sir, that at least the Government should

come out with a White Paper on these schemes, scams related to these schemes, the benefits, if at all there are any, and the failures. Moreover, the Government always keeps on advising the States like Kerala about the importance of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. That is one of the important Acts. Kerala was denied its genuine rights citing the provisions of this Act. The fiscal deficit of the Central Government has increased to 5.4 per cent during these years. It should remain, at least, below 3 per cent, or, up to 3 per cent only. The Central Government itself has increased it to 5.4 per cent. This is the data made available to this august House. The GDP-debt ratio has risen to 58.1 per cent. It should be below 40 per cent.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अब आप कन्क्लूड कीजिए।

SHRI SANDOSH KUMAR P: So, these are the realities. Don't boast much about your benefits. From the day you are ruling the country, nothing progressive has happened. The more you chant 'Modi, Modi', the more the country is going down. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): थैंक यू। माननीय सभापति जी ने पहले कहा था कि माननीय सदस्य बोलने के बाद नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे सदस्य चले गए हैं। मैं चाहूंगा कि सब लोग बोलने के बाद भी बैठें। आदरणीय श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा। आपका 10 मिनट का समय है।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे केंद्रीय बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' के सिद्धांत के अनुरूप ही वित्तीय बजट में सबके विकास का प्रावधान रखा है।

महोदय, यह समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह विकसित भारत के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता देकर बजट का उद्देश्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करते हुए सतत विकास और निजी क्षेत्रों के निवेश को प्रोत्साहित करना है। यह बजट माननीया वित्त मंत्री जी द्वारा विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित करता है। मैं इस बजट के लिए माननीया वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बजट में देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण सभी विषयों के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। यह बजट देश की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी शक्ति को केन्द्र में रख कर बनाया गया है। महोदय, माननीय प्रधान

मंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना अति आवश्यक है। एक सर्वे के अनुसार वर्तमान सरकार के प्रयासों के कारण देश की आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि लगभग 41 परसेंट बढ़ी है, परंतु आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, वह काफी कम है। उनके पास कम आय वाली नौकरियाँ एवं व्यापार हैं। इस बजट के माध्यम से देश में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए दो योजनाओं की घोषणा की गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु अगले 5 वर्षों में 5 लाख एससी-एसटी महिला उद्यमियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए टर्म लोन प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगले 5 वर्षों में इन उद्यमियों को दो करोड़ रुपए तक का टर्म लोन प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दूसरी योजना के अंतर्गत पहली बार व्यापार करने वाली 5 लाख बहनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इस योजना में एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्ग से आने वाली बहनों को शामिल करने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, इन दोनों योजनाओं से एससी, एसटी एवं ओबीसी श्रेणी से आने वाली हमारी बहनों को देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करने का एक बड़ा अवसर प्राप्त होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से आँगनवाड़ी बहनों का एक महत्त्वपूर्ण योगदान है। आँगनवाड़ी सेवा केन्द्र एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ बच्चों एवं एक करोड़ गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार प्रदान किया जाता है। एक सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आँगनवाड़ी देश के बच्चों और महिलाओं के लिए एक मजबूत स्तंभ है। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार द्वारा आँगनवाड़ी को सशक्त करने के लिए इस बजट में घोषणा की गई है। बजट में वित्त मंत्री जी द्वारा आँगनवाड़ी और पोषण अभियान के अंतर्गत पौष्टिक सहायता के लिए लागत मानकों में वृद्धि की घोषणा की गई है। इस घोषणा से आँगनवाड़ी बहनों के आर्थिक सशक्तीकरण के साथ ही गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण के लिए पोषक आहार उपलब्ध हो सकेगा। देश की मातृशक्ति को सशक्त करने की दिशा में की गई इन घोषणाओं के लिए देश की समस्त मातृशक्ति की ओर से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीया वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बजट में मातृशक्ति के प्रावधानों के अतिरिक्त देश के लिए महत्वपूर्ण अनेक विषयों के लिए प्रावधान किए गए हैं। देश के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 100 जिलों में सिंचाई एवं फसल उपरांत भंडारण की सुविधाओं को विकसित करने के उद्देश्य से माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की है। इससे देश के लगभग एक करोड़ 70 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त, किसानों के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। महोदय, ये प्रावधान निश्चित रूप से देश के अन्नदाताओं को सशक्त करने का कार्य करेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान देश के मध्यमवर्गीय करदाताओं का है। महोदय, बजट में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर टैक्स की छूट का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय लोगों को लाभ प्राप्त होगा।

महोदय, देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में लगभग 10 परसेंट की रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रावधान सराहनीय कदम हैं। कैंसर तथा दीर्घकालिक और दुर्लभ बीमारियों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स से पूर्ण रूप से छूट प्रदान की गई है। ये घोषणाएं देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण और सराहनीय योगदान हैं।

महोदय, मैं देख रही थी कि दोनों सदनों में महाकुंभ के ऊपर किस तरीके से लगातार प्रतिक्रिया की जा रही थी। अभी एक माननीय सांसद असत्य बोल कर चले गए हैं। इनको याद रखना चाहिए कि ये असत्य बोलते रहे और उस असत्य को दिल्ली की जनता ने नकार दिया, इनको अपना जवाब दिया। उसके बाद भी, अभी भी इनके असत्य बोलने में सुधार नहीं हो रहा है। मैं दोनों सदनों में चर्चा में देख रही थी कि विपक्ष के हमारे साथी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की आलोचना किए जा रहे थे। मैं महाकुंभ एवं अन्य धार्मिक गतिविधियों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का स्वयं के एक उदाहरण को सदन के समक्ष रखना चाहती हूं। इसलिए कि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं।

महोदय, मैं रविवार को दिल्ली से अपने निजी कार्य के लिए अपने गृह जनपद जा रही थी। मैंने एक्सप्रेसवे पर देखा कि प्रत्येक टोल प्लाजा पर 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थीं और मुझे जहां उतरना था, वहां अत्यधिक भीड़ होने के कारण मैं वहां पर नहीं उतर पाई, आगे 20 किलोमीटर दूर जाकर उतरी। तब मेरे मन में प्रश्न आया कि आज ऐसा क्या विशेष दिन है, ऐसा क्या महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो आज इतनी अत्यधिक भीड़ है? मैंने अपने चालक से कहा, अपने सहयोगी से कहा कि वह जो दुकान दिख रही है, चलो उस दुकान पर चलते हैं और वहाँ दुकानदार से बात करते हैं। मैं उस दुकान पर गई। मैं जब वहां उतरी, तो वहां दुकान पर कुछ लोग खड़े थे। जब मैंने उस दुकानदार से बात की कि आज ऐसा क्या त्यौहार है, क्या विशेष दिन है, जो यहाँ इतनी भीड़ है? तो महोदय, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस दुकानदार के चेहरे पर जो खुशी की चमक थी, वह देखने लायक थी। उस दुकानदार ने कहा कि कुंभ के प्रारंभ से ही और अब तक देश के विभिन्न राज्यों से प्रयागराज संगम में स्नान के लिए लोग आ रहे हैं, उससे अब तक इतनी भीड़ थी और इतनी भीड़ आ रही है कि हम अपनी दुकान को संभाल नहीं पा रहे हैं। तब मैंने कहा इससे आपको निश्चित तौर कुछ फायदा हुआ होगा। उसने कहा कि फायदा यह हुआ कि मैं पूरे वर्ष में जो आमदनी प्राप्त करता था, जो मेरी आय होती थी, उसमें इतने दिनों में ही 50 परसेंट से अधिक की वृद्धि हुई और अभी तो काफी दिनों तक महाकुंभ चलने वाला है। यह सुन कर मुझे खुशी हुई। महोदय, मुझे आश्चर्य तो तब हुआ कि जब मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकी, तो उस पेट्रोल पंप का मालिक मुस्लिम था, वह मेरी गाड़ी के पास आया और उसने कहा कि बहन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने उससे पूछा कि मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हो, तो उन्होंने बोला कि आपने हमें पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको जानता हूं। मैंने फिर पूछा कि धन्यवाद किस बात का? तो उसने कहा कि यह मेरा पेट्रोल पंप है। यहाँ मेरी आमदनी नहीं निकल रही थी और मैं मजबूर था कि इस पेट्रोल पंप को बंद करूँगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अब संक्षिप्त कीजिए, आपका समय पूरा हुआ।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: सर, बस एक मिनट। उसने कहा कि इससे मेरा पेट्रोल पंप जीवित हो गया। महोदय, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे मुस्लिम भाई-बहनों को महाकुंभ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तब मेरे मन में दो पंक्तियां आईं।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): अब कन्क्लूड कीजिए। आपने बहुत अच्छा कहा। आपकी सारी बात आ गई।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से, माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीया वित्त मंत्री जी को पुन: आभार देते हुए ...(**समय की घंटी**)... अपनी दो पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगी। मेरी पंक्तियां ये हैं कि:

मोदी का करते करते विरोध
ये संविधान विरोधी बन गए।
और करने लगे महाकुंभ का विरोध
ये सनातन विरोधी बन गए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): बहुत धन्यवाद। The next speaker is Shri Ajit Kumar Bhuyan. You have five minutes.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN (Assam): Sir, since I am from Assam and a lone voice of opposition from the North-East in this Upper House, I will only speak about the North-East in the limited time allotted to me.

Sir, Budget is the annual financial statement of the Government. This financial statement, as we all know, is the reflection of economic priorities of the incumbent Government. Government's priority in a country like India should always be towards achieving the goal of reduction of inequality among the citizens as well as among the component States. Achieving such a goal is becoming an urgency in view of the kind of inequality that has afflicted our nation. Moreover, with all financial powers centralized with the Union Government, it is upon the Central Government to proportionately distribute resources among the States. But to our dismay, this Budget lacks vision in these two fronts. Sadly enough, like all previous Budgets presented by this Government, this Budget has also transformed to an electoral rhetoric for coming Bihar election. We do not have any grievances against doling out benefits to Bihar, but the questions come to mind as to why this Government remembers States only during election. This is not the purpose why Budget is

presented. When the vast majority of our countrymen are in crying need of *roti, kapada* and *makan*, this Government is giving deaf ears to such needs. The Budget is a clear proof of this. This Budget is also a glaring example of step-motherly attitude towards the North-Eastern part of the country.

In the Budget speech, there is nothing special for Assam except some announcement for Namrup Fertilizer Plant now known as Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited. This was established in 1969, but the condition of the plant is pathetic. Except some announcement about this pioneer fertilizer plant, nothing tangible is taking shape on ground year after year. The ambitious four-lane Highway Road connectivity across the country East-West and North-South pitched during Vajpayee rule two decades ago is yet to connect my State of Assam in its letter and spirit.

The city of Guwahati has lone international airport in the entire North- East which is very often said as the gateway of North-East and was also declared as Smart City under hon. Prime Minister's ambitious scheme. But the city lacks basic minimum civic amenities, particularly safe drinking water although mighty river the Brahmaputra is flowing relentlessly along the city. The Double Engine Sarkar has not been able to supply safe drinking water to more than 70 per cent of the city dwellers even now. The water supply schemes that were executed spending crores of rupees of public money failed to deliver their intended services. There is no sincerity on the part of the Government to unravel the truth and to book the culprits for reasons known to the Government both at the Centre and the State. I urge upon the Government to take urgent appropriate measures with time-bound schedule. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): श्रीमती दर्शना सिंह, 10 मिनट।

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे केंद्रीय बजट, 2025-26 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।

महोदय, मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक सर्वस्पर्शी, समावेशी और दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें इस देश के प्रत्येक नागरिक की चिंता की गई है। महोदय, यह बजट भारत के 140 करोड़ लोगों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है।

महोदय, 2014 में जब देश में माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस बजट में देश के विकास की गति को तेज करने, सभी वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र

में निवेश बढ़ाने, घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी का कहना है कि महिला सशक्तिकरण मेरी प्रतिबद्धता है और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पहली बार उद्यमी बनने वाली 5 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 5 वर्षों में दो करोड़ रुपये तक का ऋण देने की व्यवस्था इस बजट में की गई है, ताकि महिलाएं अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो सकें। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं शामिल हों, इसकी भी चिंता की गई है। इसका मतलब यह है कि देश के हर 10 में से 7 महिलाओं को रोजगार से जोड़ना होगा। महोदय, जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तो वे न सिर्फ अपने परिवार को मजबूत करेंगी, बल्कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। इसके अलावा, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का भी विस्तार किया गया है, जिससे 8 करोड़ बच्चों, एक करोड़ गर्भवती महिलाओं और 20 लाख किशोरियों को लाभ मिलेगा। यह योजना महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।

महोदय, मैं यह बताना चाहती हूँ कि 2014 में जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री पद की शपथ ली, तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण का संकल्प किया। 2014 से लेकर आज तक हर कदम पर महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी दर्जनों योजनाएं चलाई गईं, जिनसे महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हों। हम लोगों ने देखा कि माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2023 में "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" पारित करके महिलाओं को लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में 33% आरक्षण दिया गया। यह एक ऐसा साहसिक निर्णय था, जो इस देश की आधी आबादी, यानी महिलाओं के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे महिलाओं की नेतृत्व क्षमता के साथ-साथ उनके निर्णय लेने के अवसर भी बढ़ेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी का जो यह कहना है कि अब समय आ गया है कि हम केवल महिलाओं के विकास की बात न करके महिलाओं के नेतृत्व में इस देश का विकास हो, इस पर काम करें, तो निश्चित तौर पर, ये सारे निर्णय उनके इस संकल्प को एकदम मजबूत बनाते हैं। अब जब भी महिलाओं के विकास की बात आएगी, तो इस काल को जरूर याद किया जाएगा और माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति इस देश की आधी आबादी हमेशा ऋणी रहेगी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को सम्मान और समानता से जीने का अवसर दिया है।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी का हमेशा यह मानना रहा है कि जब देश का किसान समृद्ध और संपन्न होगा, तभी देश उन्नत और विकास की दिशा में सही मायने में आगे बढ़ेगा, इसलिए इस बजट में "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" की शुरुआत की जा रही है, जिसका सीधा लाभ देश के 10 करोड़ किसान भाइयों को होगा। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार उर्वरक उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने कई आवश्यक कदम भी उठाए हैं। इसी दिशा में सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को फिर से शुरू किया है और असम के नामरूप में एक नए यूरिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है। महोदय, मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस उर्वरक उत्पादन से किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल सकेगी और यूरिया उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनेगा।

8.00 **P.M.**

महोदय, सरकार ने अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कड़ी मध्यम वर्ग को अपनी आर्थिक योजना के केंद्र में रख कर यह दिखा दिया है कि मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं के...

उपसभाध्यक्ष (डा. दिनेश शर्मा): माननीय सदस्या, मैं आपको बीच में ही रोकता हूं। आज का जो निर्धारित समय 8 बजे तक का था, वह पूरा हुआ। आपका जो भाषण बचा है, वह 13 फरवरी को जारी रहेगा। The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Thursday, the 13th February, 2025.

The House then adjourned at eight of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 13th February, 2025.